राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 267

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 4 मार्च 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

इजरायल के संसदीय चुनाव में नेतन्याहू बहुमत के करीब

>> 13

सरोकार

दिव्यांगों के लिए वरदान 'सस्ता' एक्सोस्केलेटन सूट

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ के नवउद्यमी ने सरकारी सहयोग से एक्सोस्केलेटन सूट बनाया है, जो बाजार में उपलब्ध 60 लाख से तीन करोड़ तक की कीमत वाले विकल्पों के मुकाबले 26 लाख में मिलेगा। भविष्य में ऐसे उपकरण दिव्यांगों को सुलभ हो सकेंगे। (पेज-11)

जागरण विशेष

इस बार जमकर उड़ेगा स्प्रे वाला प्राकृतिक गुलाल

हाथरस : इस होली में स्प्रे वाला गुलाल खूब धमाल मचाएगा। प्राकृतिक रंगों से तैयार इस गुलाल की देश-विदेश में जमकर सप्लाई हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कारखानों में जनवरी में ही इसका स्टॉक खत्म हो गया था। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

सीएए पर सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर यूएन मानवाधिकार आयोग

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने का फैसला किया है। भारत ने कहा है कि यह हमारा आतंरिक मामला है। किसी विदेशी पार्टी को भारत के आतंरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पुलवामा हमले की साजिश में शामिल रहे बाप-बेटी गिरफ्तार

श्रीनगर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलवामा हमले की साजिश में शामिल बाप-बेटी को गिरफ्तार किया है। हकरीपोरा निवासी तारिक आतंकियों को ले जाने में मदद करता था और उसकी बेटी इंशा ठहरने की व्यवस्था के साथ आतंकियों को सुरक्षा बलों से बचाने में मदद करती थी।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

देश में बुजुर्गों को अब एक कॉल पर मिलेगी मदद

नई दिल्ली : बुजुर्गों का ख्याल रखने में जुटी मोदी सरकार ने उन्हें लेकर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके तहत अप्रैल तक बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया जाएगा। शुरू में इसे कुछ महीने तक ट्रायल के तौर पर रखा जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

तालिबान ने अफगानिस्तान के 16 प्रांतों पर 33 हमले किए

काबुल : तालिबान ने बीते 24 घंटों में अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 16 पर 33 हमले करके तीन दिन पुरानी युद्ध विराम संधि को ही खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि तालिबान के हमलों में छह नागरिक मारे गए हैं और 14 घायल हुए हैं। इस दौरान तालिबान के आठ लोग मारे गए हैं और 15 घायल हुए हैं।

दिल्ली पुलिस के सिपाही पर पिस्तौल तानने वाला शाहरुख गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में हुए दंगे के दौरान फायरिंग करने और दिल्ली पुलिस के हेडकांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर दंगा फैलाने, अवैध हथियार रखने और सिपाही की हत्या के प्रयास का आरोप है। उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार शाहरुख के पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। घटना को अंजाम देने के बाद वह पहले जालंधर, फिर बरेली भाग गया था। बरेली से शामली जाते समय क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया। उसे मंगलवार शाम ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड के दौरान उसके मददगारों और ड्रग्स तस्कारों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। हालांकि अभी तक शाहरुख का कोई आपराधिक रिकार्ड सामने नहीं आया है।

बड़ी कामयाबी

- क्राइम ब्रांच ने उप्र के शामली में बस स्टैंड से दबोचा
- कोर्ट में किया गया पेश, पुलिस को मिली चार दिन की रिमांड
- दिल्ली से जालंधर और वहां से बरेली भाग गया था शाहरुख

दिल्ली में दंगों के दौरान पुलिकर्मी पर पिस्टल तानने और कई राउंड फायरिंग करने वाला शाहरुख (चेहरा ढका) मंगलवार को दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसे उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया। ध्रुव कुमार

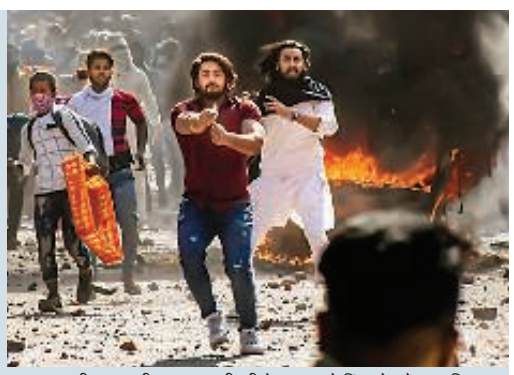

शाहरुख की यह तस्वीर 24 फरवरी की है जब उसने हिंसा के दौरान पुलिस कर्मी पर पिस्टल तान दी थी और कई राउंड फायर किया था। (फाइल) **प्रेट्र**

किए थे तीन हवाई फायर : दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर एके सिंगला के मुताबिक शाहरुख ने बताया कि दंगे के दौरान 24 फरवरी को वह अकेला ही पिस्तौल लेकर निकला था। पथराव होते देख तीन हवाई फायर किए। इसके बाद गुस्से में आकर हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी, हालांकि कोई फायर नहीं किया और वहां से भाग गया। जाफराबाद से एस्टीम कार से निकलने के बाद वह रात में कनॉट प्लेस की पार्किंग में सो गया था। वहां से तड़के दोस्त के पास पंजाब के जालंधर चला गया। वहां वह ज्यादा देर नहीं रुका और भागकर बरेली चला गया, रास्ते में उसने अपनी कार को छिपा दिया। वहां ड्रग्स तस्करों के पास छिपा रहा। मंगलवार को बरेली से निकलकर जब वह दोस्त के पास शामली आ रहा था। तभी क्राइम ब्रांच ने शामली बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया।

दो वर्ष पहले मंगवाई थी पिस्तौल : पूछताछ में शाहरुख ने बताया कि वह शौक में पिस्तौल रखता था। उसके घर में जुराब बनाने की अवैध फैक्ट्री चलती है। फैक्ट्री के एक कर्मी के जरिये दो वर्ष पहले उसने मुंगेर से पिस्तौल मंगाई थी। दंगे वाले दिन वह आठ कारतूस लेकर निकला था, इसमें तीन फायर किए थे, दो कारतूस कहीं गुम हो गए। तीन उसके पास से मिले।

खंगाली जा रही कॉल डिटेल्स : दंगे के बाद शाहरुख किन लोगों के संपर्क में रहा। इसके लिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। मोबाइल की लोकेशन भी निकलवाई जाएगी, जिससे उसके द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि की जा सके। उसकी मदद करने वाले कौन थे और उसने किसके कहने पर फायरिंग की, इन सभी बातों की जांच की जा रही है।

मॉडलिंग, टिक टॉक और जिम का है शौक : बीए दूसरे वर्ष तक की पढ़ाई करने वाले शाहरुख को मॉडलिंग, जिम और टिक टॉक का शौक है। (पेज-2 भी देखें)

जागरण ने पहले ही बता दिया था, बरेली में छिपा है शाहरुख

दैनिक जागरण ने 2 मार्च के अंक में ही बरेली में ड्रग्स माफिया के बीच शाहरुख के छिपे होने की जानकारी दे दी थी। साथ ही यह भी बताया था कि शाहरुख के परिवार के अन्य लोग भी गायब हैं। गिरफ्तारी के बाद शाहरुख ने भी पुलिस को बताया कि वह दंगे के बाद बरेली में छिपा था।

संसद में दंगों पर बहस को लेकर टकराव जारी

नई दिल्ली : दिल्ली दंगों पर संसद में टकराव जारी है। विपक्ष तुरंत चर्चा चाहता है, जबकि सरकार इसे होली बाद कराना चाहती है। टकराव को देखते हुए लोस अध्यक्ष ने सदस्यों को निलंबित की चेतावनी तक दे दी। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे के कारण उपसभापति को पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। (पेज-3)

कोरोना पर बढ़ी चिंता, एक्शन में सरकार

चुनौती ▶ प्रधानमंत्री मोदी ने की वायरस से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा

दिल्ली, तेलंगाना के बाद जयपुर में भी एक मरीज, अब तक छह में संक्रमण की पुष्टि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब तक देश में छह लोगों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम ने वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से इस वायरस से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही आश्वस्त किया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देश में अब तक पुष्ट हुए छह मामलों में से तीन मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।

सोमवार को दिल्ली और तेलंगाना में एक-एक नए कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की पुष्टि के बाद मंगलवार को जयपुर में इटली के एक पर्यटक वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा का फैसला किया। स्वास्थ्य, पर्यटन और विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को कोरोना वायरस के भारत में घुसने और फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी दी। इस समय देश के 21 हवाई अड्डों पर इस वायरस से सबसे अधिक ग्रसित 12 देशों से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। सात बड़े और 65 छोटे बंदरगाहों के साथ-साथ नेपाल सीमा पर भी स्क्रीनिंग की जा रही है। विदेश और पर्यटन मंत्रालय ने चीन, ईरान समेत कई देशों के वीजा निलंबित किए जाने और वहां से आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों पर विशेष निगरानी रखे जाने की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हर दिन राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ताजा हालात का जायजा लिया जा रहा है।

- **प्रधानमंत्री ने संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पुख्ता निगरानी का दिया निर्देश**
- **देश के 21 हवाई अड्डों पर वायरस से ग्रसित 12 देशों से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य स्क्रीनिंग की है व्यवस्था**

तीसरे टेस्ट में वायरस की पुष्टि : जयपुर में इटली के एक पर्यटक के कोरोना वायरस से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है। सर्दी-जुकाम और बुखार से पीड़ित यह पर्यटक पहले टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था, यानी उसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, लेकिन दूसरा टेस्ट निगेटिव निकला था। पुणे के इंस्टीट्यूट ऑर वायरोलॉजी में तीसरे टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे कोरोना से ग्रसित घोषित किया गया। वहीं इस पर्यटक की पत्नी का पहला टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद सैंपल को अगले टेस्ट के लिए पुणे भेज दिया गया है।

चीन के कोरोना वायरस प्रभावित वुहान शहर से एयरलिफ्ट कर दिल्ली के छावला स्थित आइटीबीपी कैंप में रखे गए लोगों की मंगलवार को जांच की गई। एएनआइ

ताजा घटनाक्रम

- **आगरा के छह संदिग्ध मरीज जांच और निगरानी के लिए दिल्ली लाए गए**
- **वायरस फैलने की आशंका को देखते हुए नोएडा में दो स्कूल एहतियातन बंद**
- **तेलंगाना व कर्नाटक की राज्य सरकारों ने संदिग्धों पर निगरानी बढ़ाई**
- **महाराष्ट्र में भी छह संदिग्ध, अभी किसी व्यक्ति में वायरस की पुष्टि नहीं**
- **चीन के बाद अब ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान के वीजा भी रद**
- **भारतीयों को भी वायरस प्रभावित देशों की यात्रा से बचने की सलाह**
- **सरकार ने टीवी और एफएम चैनलों को जागरूकता संदेश फैलाने को कहा**
- **एयर इंडिया ने 25 फरवरी को वियना-दिल्ली फ्लाइट से आए यात्रियों को किया सतर्क, दिल्ली का संक्रमित मरीज इसी फ्लाइट से आया था**
- **उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सतर्कता का स्तर बढ़ा दिया है, जबकि राजस्थान में सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी का एलान कर दिया है। दोनों राज्यों में स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं।**

कैबिनेट सचिव ने भी चर्चा की : कैबिनेट सचिव ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों व केंद्र के संबंधित मंत्रालयों के सचिवों से इस मामले पर चर्चा की। इसमें संदिग्ध मरीजों को अलग रखने (आइसोलेट करने) की सुविधा तैयार करने, जिलाधिकारियों को ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर इससे निपटने के लिए तैयार रहने, तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में अलग वार्ड तैयार करने के लिए कहा।

26 प्रकार के बल्क ड्रग्स के निर्यात पर रोक

नई दिल्ली : चीन से फैले कोरोना वायरस की वजह से भारत में दवाइयों की किल्लत की आशंका को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को 26 प्रकार के बल्क ड्रग्स (कच्चे माल) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सरकार की इजाजत लेकर निर्यातक इन ड्रग्स का निर्यात कर सकते हैं। दवा कंपनियां इन ड्रग्स के निर्यात पर रोक की मांग कर रहे थे ताकि घरेलू स्तर पर दवा बनाने के लिए कच्चे माल की कमी न हो। (पेज-5)

सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या में चार दिन में फांसी की सजा

दुमका : झारखंड के दुमका जिला स्थित रामगढ़ में छह साल की मासूम बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने चचेरे चाचा सहित तीन आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई। देश का यह पहला मामला है, जहां अदालत ने चार दिन में ट्रायल पूरा कर दुष्कर्मियों को सजा सुनाई। इस दौरान रात में भी अदालत चली। मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किये गए। (पेज-7)

खांसी-जुकाम की दवा का सैंपल फेल, मामला दर्ज

नाहन: हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब स्थित डिजिटल विजन दवा कंपनी में बनी खांसी-जुकाम की दवा के सैंपल फेल हो गए हैं। कोल्ड बेस्ट सीरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला पदार्थ पाया गया है। हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल स्टेट ड्रग कंट्रोलर की टीम ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। कंपनी को सील करने के साथ लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। (पेज-10)

महिला टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ंत

सिडनी: भारत महिला टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा जो ग्रुप-बी में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरे स्थान पर रहा। इस मैच के रद होने के कारण दक्षिण अफ्रीका को एक अंक मिला और टीम ग्रुप-बी में शीर्ष पर रही। पहली बार फाइनल में जगह बनाने की कोशिशों में जुटी भारत की महिला टीम ग्रुप-ए में चारों मैच जीतकर शीर्ष पर रही थी। (पेज-14)

महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस ने की श्रेय लेने की कोशिश, उद्धव ने कहा-कोई प्रस्ताव नहीं

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण के मुद्दे पर सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेद नजर आने लगे हैं। कांग्रेस-राकांपा ने जहां नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों को जल्द पांच फीसद आरक्षण देने की बात कही है, वहीं शिवसेना के प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साफ कहा है कि इस संबंध में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं है।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट ने मंगलवार को कहा, मुस्लिमों को आरक्षण का मूल विचार कांग्रेस का रहा है। उनका दावा तथ्यपूर्ण लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस सरकार आने से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेसनीत सरकार के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण के कार्यकाल के अंतिम दिनों में मराठा आरक्षण के साथ ही मुस्लिमों को आरक्षण देने का अध्यादेश लाया गया था, लेकिन चह्वाण सरकार के जाने के बाद न तो मराठों को आरक्षण मिल सका, न ही मुस्लिमों को। भाजपानीत फड़नवीस सरकार मराठों को आरक्षण देने का प्रस्ताव तो लाई, लेकिन उसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया।

अब तक के सबसे बड़े जीएसटी फर्जीवाड़े का हुआ पर्दाफाश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बिना माल सप्लाई किए फर्जी तरीके से सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। इसके तहत 7,896 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए गए और उस आधार पर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर 1,709 करोड़ रुपये ले लिए। इस फर्जीवाड़े के लिए 23 मुखौटा कंपनियां बनाई गई थीं जिसके नाम पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा था।

सेंट्रल टैक्स कमिश्नर (पश्चिमी दिल्ली) की तरफ से इस प्रकार के सबसे बड़े पैमाने पर कोई मामला पहली बार सामने आया है।

- **7,896 करोड़ रुपये मूल्य का फर्जी जीएसटी बिल बनाया**
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर 1,709 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा**

बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया गया। इस मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले भी इनपुट क्रेडिट टैक्स के नाम पर कई रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है। माना जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद जीएसटी में गड़बड़ी का बड़ा मामला उजागर हो सकता है। जीएसटी में धांधली की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन इतने

वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 23 मुखौटा कंपनियों के नाम पर यह सारा खेल चल रहा था। अभियुक्त इन कंपनियों के खाते में खरीदारी दिखाते थे जबकि वास्तव में कोई खरीदारी नहीं की जाती थी। फिर उस नाम पर वे जीएसटी प्रणाली के तहत मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा टैक्स विभाग में करते थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे को सही साबित करने के लिए वे बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी करते थे। ताकि किसी प्रकार का कोई शक नहीं हो। ये लोग अपनी फर्जी कंपनी से खरीदारी करने वालों को बिल जारी करते थे और उस बिल के आधार पर फर्जी खरीदारी करने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करता था।

सूत्रों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद से इस प्रकार की धोखाधड़ी आम हो चली है। निर्यात के मामले में इस प्रकार के मामले सामने आए जहां बिना किसी निर्यात के ही सरकार के इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि निर्यातक ने सिर्फ कागज पर निर्यात किया और कच्चे माल की फर्जी खरीदारी के नाम पर सरकार से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के पैसे ले लिए।

नारी शक्ति को नमन

महिला दिवस के मौके पर एक नई लकीर खींचेंगे मोदी, पीएम के अकाउंट से लोग जानेंगे समाज की प्रेरक महिलाओं की कहानी, मोदी के पिछले ट्वीट से सोशल मीडिया छोड़ने की लगने लगी थीं अटकलें

मोदी एक दिन के लिए महिलाओं के नाम करेंगे सोशल मीडिया अकाउंट

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर बना सस्पेंस खत्म कर दिया है। मोदी ने मंगलवार को एलान किया कि वह महिला दिवस यानी आठ मार्च के दिन अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट समाज को प्रेरित करने वाली महिलाओं को सौंप देंगे।

पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट किया था कि वह इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इस ट्वीट से ज्यादातर लोगों ने यह अर्थ निकाला कि मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का संकेत दिया है। इसके तुरंत बाद से हैशटैग 'नो सर' ट्रेंड करने लगा। ज्यादातर यूजर्स मोदी से सोशल मीडिया नहीं छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। आश्चर्य इसलिए भी ज्यादा था, क्योंकि मोदी खुद सोशल मीडिया की पैरवी करते रहे हैं। वह इसे लोगों से संवाद की मजबूत कड़ी मानते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया छोड़ने का फैसला कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था।

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

ऐसे मिल सकता है मौका

महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करने की इच्छा रखने वाली महिलाएं ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिये प्रधानमंत्री को अपनी कहानी बता सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसी किसी प्रेरक महिला के बारे में मोदी को बता सकता है। मोदी हर साल महिला दिवस के मौके पर कुछ महिलाओं को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया है।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट करते हुए सभी संशय दूर कर दिए। उन्होंने लिखा, 'इस महिला दिवस पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं को सौंप दूंगा, जिनके जीवन और कार्यों ने हमें प्रेरणा दी है।

इसकी मदद से ये महिलाएं लाखों लोगों को प्रेरित कर सकेंगी।' उन्होंने आगे लिखा, 'क्या आप भी उनमें से हैं या ऐसी किसी महिला को जानते हैं? हैशटैग 'शी इन्स्पायर्स अस' के साथ ऐसी कहानियां शेयर कीजिए।' केंद्र सरकार के कई मंत्रालय भी सात मार्च तक इस दिशा में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। दूरदर्शन पर शेफ संजीव कपूर के साथ विभिन्न रेसिपी पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को स्वस्थ एवं पोषक भोजन की रेसिपी बताई जा रही है। कई मंत्री और सचिव इससे जुड़े लेख भी लिख रहे हैं।

राहुल ने फिर साधा निशाना

सोशल मीडिया अकाउंट पर सस्पेंस दूर होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, 'जब पूरा देश मुश्किल में है, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मसखरी कर देश का वक्त मत बर्बाद कीजिए। हर भारतीय की चिंता को देखते हुए जानलेवा कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने पर ध्यान दीजिए।' सोमवार को सोशल मीडिया छोड़ने के मोदी के ट्वीट के बाद राहुल ने लिखा था, 'सोशल मीडिया नहीं, नफरत छोड़िए।'

जेपी इन्फ्रा के 20 हजार अधूरे फ्लैट तैयार होने का रास्ता साफ

नई दिल्ली, प्रेट्र: सार्वजनिक कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है। इससे हजारों घर खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत होने वाले इस अधिग्रहण में एनबीसीसी को जेपी इन्फ्रा के अधूरे पड़े 20,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट साढ़े तीन साल में पूरा करना होगा।

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के कार्यवाहक प्रेसिडेंट बीएसवी प्रकाश कुमार ने इस सौदे को मंजूरी दी। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जेपी इन्फ्राटेक की मूल कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए 750 करोड़ रुपये को रिजॉल्यूशन प्लान में शामिल किया जाएगा। इस सौदे से न सिर्फ हजारों घर खरीदारों को राहत मिलेगी बल्कि संकट से गुजर रहे रियल एस्टेट सेक्टर को उबरने का मौका भी मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2017 में जेपी इन्फ्राटेक के लिए इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस दौरान तीसरे चरण की बोली में जेपी इन्फ्रा को एनबीसीसी के रूप में खरीदार मिला था। पिछले वर्ष दिसंबर में 13 बैंकों व 21,000 घर खरीदारों ने एनबीसीसी के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी थी। जेपी इन्फ्राटेक ने ग्रेटर नोएडा में हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत 20,000 नए घर बनाए जाने थे, पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। इस दौरान ग्राहकों के 13,364 और कर्जदाताओं के 9,783 करोड़ रुपये फंस गए। एनबीसीसी ने कर्जदाताओं को 1,526 एकड़ भूमि देने का विकल्प रखा था। इसके साथ ही सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर्जदाताओं को यमुना एक्सप्रेस-वे के असेट में भी हिस्सेदारी देगी।

100 पाठ्यक्रमों के लिए गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें से 68 पाठ्यक्रमों में कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाएं 25 अप्रैल से 5 मई के बीच होंगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 4 मार्च 2020

एनकाउंटर के डर से ड्रग्स माफिया के अड्डे से भागा शाहरुख

खुला राज ▶ नारकोटिक्स सेल की मदद से क्राइम ब्रांच ने कस दिया था शिकंजा, 25 फरवरी को मां और दो दिन बाद पिता शावर पठान भी पहुंचा था बरेली

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

वीडियो वायरल होते ही शाहरुख की पुलिस ने पहचान कर ली तो वह जालंधर होते हुए बरेली भाग गया। यहां ड्रग्स माफिया के अड्डे पर वह छिपा था। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने नारकोटिक्स सेल की मदद से यहां शिकंजा कसा तो वह बरेली से भाग निकला। दरअसल, दिल्ली पुलिस की तीसरी बटालियन में तैनात हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्टल तानने की वजह से उसे डर था कि मुठभेड़ हुई तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस के बरेली पहुंचते ही वह भाग निकला। उसने नारकोटिक्स सेल के पुलिसकर्मियों से संपर्क साध कर आत्मसमर्पण की इच्छा भी जताई थी।

ड्रग्स तस्करी का देश में इस समय सबसे बड़ा हब बरेली जिले को माना जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बरेली के कस्बा मीरगंज, मिलख और फतेहगंज से ही ज्यादातर ड्रग्स तस्करी होती है। क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क पर नजर रखती है, जिससे इस सेल के कर्मियों को दिल्ली सहित आसपास के राज्यों के बड़े ड्रग्स माफिया की पूरी जानकारी रहती है। शाहरुख की मां भी बरेली के मीरगंज की रहने वाली है। शावर पठान के ड्रग्स तस्करी का धंधा छोड़ देने पर अब कई सालों से ड्रग्स का धंधा करने लगी। उसके भी बरेली के ड्रग्स माफिया से बेहतर संबंध हैं।

24 फरवरी को करीब एक घंटे बाद जब वह घर पहुंचा तो निजी चैनलों पर तस्वीरें चलते देख परिवार के सभी सदस्य दहशत में आ गए। पुलिस की कॉल आने पर वह मोबाइल बंद करके घर से भाग गया। अगले दिन पंजाब चला गया। वहां से बरेली चला गया। पुलिस का दबाव बढ़ा तो 25 फरवरी को उसकी मां भी बरेली भाग गई। इसके बाद 26 फरवरी को पिता शावर पठान बेटी व दोनों बेटे के साथ बरेली पहुंच गया। पहले तो दिल्ली की पुलिस शाहरुख को दबोचने के लिए प्रयास करती रही। पुलिस को जब पता चला कि वह बरेली में ड्रग्स माफिया की शरण में पहुंच गया है और उन्हीं के अड्डे पर छिपा है तो हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद 26 फरवरी को शाहरुख को गिरफ्तार किए जाने की जिम्मेदारी स्पेशल सेल को दी गई। इसके बाद सेल ने बरेली जिले में डेरा डाल दिया। यहां मीरगंज, मिलख व फतेहगंज ऐसे कस्बे हैं, जिसमें कई बड़े ड्रग्स माफिया रहते हैं। इन कस्बों में जाकर किसी को पकड़ना बेहद मुश्किल है क्योंकि यहां हर सड़क पर ड्रग्स माफिया की नजर रहती है। यही वजह है कि स्थानीय पुलिस व स्पेशल सेल को सफलता नहीं मिली। हालांकि क्राइम ब्रांच ने नारकोटिक्स सेल के जरिये दबाव बनाकर शाहरुख को दबोच लिया। घटना के एक घंटे बाद जब शाहरुख की पहचान हो गई तो पुलिस को लगा जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दंगा प्रभावित शिव विहार का दौरा किया और पीड़ितों का दर्द जाना। उन्होंने लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रेट्र

दंगा पीड़ितों की मदद के लिए उतरे चार कैबिनेट मंत्री

जासं, नई दिल्ली : उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित लोगों की मदद के लिए दिल्ली सरकार के चार मंत्री सड़क पर उतर गए हैं। मंत्रियों ने अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर दंगा पीड़ितों से बात की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी मदद करने के आदेश दिए। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिव विहार, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मौजपुर, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने गोकलपुरी और मंत्री इमरान हुसैन ने बल्लीमारान का दौरा किया। सिसोदिया ने कहा कि हिंसा के कारण लोगों का काफी नुकसान हुआ है। जनता के साथ जो भी हुआ है उसको लेकर सरकार चिंतित है। सरकार लोगों की जितनी मदद कर सकती है उसके लिए पूरी जुटी हुई है। उन्होंने शिव विहार फेज-सात 25 फुटा रोड पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पहुंचकर पीड़ित परिवारों से बातचीत की।

नफरत फैलाने की शिकायत करने पर मिलेंगे 10 हजार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों की शिकायत देने वालों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने मंगलवार को हुई बैठक में सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों की सूचना देने के लिए एक ईमेल आइडी और वाट्सएप नंबर जारी किया है। इस ईमेल और वाट्सएप नंबर पर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दंगा कराने के उद्देश्य से फर्जी खबरें या अफवाहें फैलाने वालों के स्क्रीन शॉट लेकर शिकायत कर सकता है। समिति ने बताया कि दी गई सूचना पर यदि पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो सूचना देने वाले को 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।

समिति का मानना है कि होली के आसपास सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। लिहाजा पांच मार्च को दंगा प्रभावित छह विधानसभा क्षेत्रों में शांति बैठक करने का फैसला लिया है। इस बैठक में स्थानीय विधायक, समिति के सदस्य, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्थानीय धार्मिक व सम्मानित लोग शामिल होंगे।

समिति के चेयरमैन सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पर दो धर्म के लोगों के बीच दुश्मनी की भावना पैदा करने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत दिल्ली विधानसभा की समिति से ईमेल आइडी और वॉट्सऐप नंबर पर की जा सकती है। समिति ने इसके लिए इमेल आइडी dvscommittee@delhi.gov.in व वाट्सएप नंबर 8950000946 जारी किया है। भारद्वाज ने कहा कि ईमेल आइडी और वॉट्सएप नंबर की जानकारी हर व्यक्ति को दी जाएगी। अखबार, रेडियो, मास एसएमएस व विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाकर इसका प्रचार किया जाएगा।

गुनहगारों का सुरक्षित ठिकाना बना बरेली

जागरण संवाददाता, बरेली

03 तहसीलों-आंवला, फरीदपुर और मीरगंज से सप्लाई होती है ड्रग्स

12 से ज्यादा तस्करों के नाम केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थानीय इकाई में दर्ज

दूसरे शहर से बरेली में छिपने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए साझा अभियान चलता है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में भी यहां की टीम ने लखनऊ एसटीएफ की मदद की थी। ऐसे लोगों के मददगारों की पहचान समय रहते होती रहे इसके लिए खुफिया इकाई को और मजबूत करेंगे।
-शैलेश पांडेय, एसएसपी, बरेली

पनाहगार जागरण पड़ताल

उप्र में भले ही बरेली जिले की पहचान बड़े अपराधों को लेकर नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों से बड़े अपराधों में संलिप्त आरोपितों की शरणस्थली जरूर बनता जा रहा है। पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद एजाज से लेकर हिंदुत्ववादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपित और अब दिल्ली के दंगाई शाहरुख का यहां आकर शरण लेना साफ बता रहा है कि बरेली में खतरनाक ठिकाने हैं, जहां ऐसे लोगों को छिपा लिया जाता है। देश के कई प्रदेशों में नशे के रूप में मौत बांट रहे बड़े ड्रग्स माफिया भी जिले के गांवों में छिपे बैठे हैं।

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पांच साल पहले जब पाक जासूस मोहम्मद एजाज को मेरठ से पकड़ने के बाद उसके बरेली के कई मोहल्लों में रहने का पर्दाफाश किया तो यह चौंकाने वाली खबर थी। लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं थी। ऐसे ही 18 अक्टूबर को लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या के बाद दोनों आरोपित मोइनुद्दीन व अशफाक सीधे बरेली आए थे। दो दिन दोनों यहां रहे थे। हालांकि लखनऊ एसटीएफ ने हत्यारोपितों की मदद के आरोप में नात पढ़ने वाले मौलाना कैफी को मोहल्ला शाहबाद, अधिवक्ता नवेद और टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी में उसके पार्टनर कामरान को गिरफ्तार किया था।

मौलाना कैफी और नवेद को एक दरगाह के अहम लोगों का करीबी बताया गया था। आरोप है कि इन्होंने मुख्य आरोपितों को मदद कर नेपाल भागने के लिए साधन उपलब्ध कराए थे। नया मामला शाहरुख का सामने आया है। दिल्ली हिंसा के दौरान कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने की फोटो वायरल होने के बाद शाहरुख भी वहां से भागकर बरेली में ही आकर छिपा। 'जागरण' ने उसके यहां होने का पर्दाफाश किया था। मीरगंज तहसील के खानपुर मोहल्ला स्थित अपनी ननिहाल में उसने शरण ली थी। दिल्ली पुलिस की टीम ने घेराबंदी की। इस बीच मददगारों ने उसे यहां से निकालने में अहम भूमिका निभाई। वह भागा लेकिन शामली में गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े मामलों के इन आरोपितों का मूवमेंट साफ बता रहा है कि छिपने के लिए बरेली को सुरक्षित ठिकाना समझा जा रहा है।

जिले के बड़े ड्रग्स माफिया को भी बचाने वाले कम नहीं। गांवों, कस्बों की गलियों में रहने ये माफिया दूसरे प्रदेशों में पकड़े गए तब उनके गिरोह का राजफाश हुआ। फतेहगंज पश्चिमी में रहने वाले उस्मान पर मादक पदार्थ की तस्करी के दस मुकदमे दर्ज हैं। एक बार राजस्थान और दूसरी बार वह गोवा में गिरफ्तार किया गया था। शराफत दिल्ली में गिरफ्तार हुआ तो लंबे वक्त तक तिहाड़ जेल में रहा। उस पर सात मुकदमे दर्ज हैं।

फतेहगंज में रहने वाले शाहिद कल्लू पर ड्रग्स तस्करी के 13, ताहिर रुहानी पर दो मुकदमे हैं। महिला तस्कर रेहाना भी स्मैक सप्लाई में जेल जा चुकी है। नन्हे, रिफाकत, उस्मान, इशाकत, छोटा शराफत, सलीम, सोनू कालिया, मोहम्मद चांद भी पकड़े जा चुके हैं। यह केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थानीय इकाई में दर्ज हैं। इंस्पेक्टर एमपी सिंह बताते हैं कि ये सभी मादक पदार्थों की बिक्री में पकड़े जा चुके हैं। जिले में ड्रग्स तस्करी का बड़ा केंद्र फतेहगंज पश्चिमी है। एक दर्जन से ज्यादा माफिया जेल जा चुके हैं। इनके बारे में उनके गांव, कस्बे से इनपुट जुटाना बेहद मुश्किल होता है।

सीसीटीवी फुटेज में ताहिर के साथ दिखे पिस्तौल लिए 15 युवक

राकेश कुमार सिंह, नई

- दिल्ली में जामिया के आसपास छिपा बताया जा रहा है आप का निलंबित पार्षद
- पिस्तौल लिए दिखने वाले सभी युवकों की पहचान हुई, मोबाइल 26 फरवरी से लगातार बंद

दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए आइबी के सिपाही अंकित शर्मा की हत्या के आरोपित आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के काले कारनामों से अब पर्दा उठने लगा है। पुलिस के हाथ 24 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज लगी है, जिसमें वह 15 से ज्यादा दंगाइयों के साथ चांदबाग पुलिया स्थित किलेनुमा घर से बाहर निकलते और घुसते हुए दिखाई दे रहा है। इन सभी के हाथ में पिस्टल भी है। यही नहीं उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में युवक लाठी-डंडे व तबाही का सामान लेकर चलने की फुटेज भी सामने आई है। ताहिर हुसैन जामिया या उसके पासपास के इलाके में छिपा हुआ बताया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ताहिर हुसैन के साथ पिस्टल लिए दिखने वाले सभी युवकों की पहचान कर ली गई है। उन सभी युवकों के भी मोबाइल 26 फरवरी से बंद आ रहे हैं। ताहिर हुसैन 26 फरवरी से ही परिवार समेत फरार है। उसके दोनों घरों में ताला जड़ा हुआ है। परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल बंद हैं। ताहिर के साथ पिस्टल लेकर वीडियो में कैद युवकों के परिजन भी परिवार समेत फरार हैं। वीडियो में युवकों द्वारा गोलियां चलाते हुए तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। आइबी के सिपाही अंकित शर्मा हत्याकांड में पुलिस को यह बड़ा सुबूत मिल गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ताहिर हुसैन को सजा से बचा पाना मुश्किल हो सकता है। शाहरुख के पकड़े जाने पर दिल्ली पुलिस अब ताहिर हुसैन को पकड़ने की कोशिश तेज करेगी।

भारी फोर्स के साथ पुलिस ने मारा ताहिर के घर छापा

मंगलवार को करीब 1000 पुलिसकर्मियों के साथ कई डीसीपी स्तर के अधिकारियों ने चांदबाग के आसपास ताहिर हुसैन के छह संभावित ठिकानों पर दबिश दी थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। दबिश में स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच के भी कई अधिकारी शामिल थे। दिल्ली पुलिस अब जामिया व ओखला के आसपास इलाके में दबिशें देगी। 26 फरवरी की सुबह भी पुलिस ने ताहिर के चांदबाग स्थित घर पर छापा मारकर वहां से भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद किया था।

सैकड़ों अराजक तत्व किए गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के हाल के दंगों में दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है ताकि अफवाहों और दुष्प्रचार की रोकथाम की जा सके।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि राजधानी में कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा वाली जगहों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 76 कंपनियों (7,600 जवान) समेत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि 120 से अधिक एफआइआर दर्ज की गई हैं और सैकड़ों अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच अधिकारी दंगे की सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर रहे हैं। साथ ही इन वीडियो को जनता को दिखाया जा रहा है ताकि दोषियों की पहचान की जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी नजदीक से निगाह रखी जा रही है। ताकि अफवाहों और दुष्प्रचार को रोका जा सके।

राय ने कहा कि सीआरपीसी के तहत दंगा प्रभावित क्षेत्रों में धारा-144 लगाकर निषेधाज्ञा लागू की गई है। इन इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इससे लोगों में विश्वास बहाली होगी। लोगों से शांति कायम करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है।

सांसद अधीर रंजन के घर में घुसे चार युवक, कर्मचारियों से की मारपीट

जासं, नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के हुमायूं रोड स्थित आवास पर मंगलवार की शाम को चार युवकों के जबरन घुसने और स्टाफ के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक शाम 5.30 बजे अधीर रंजन चौधरी के घर में ही बने कार्यालय में चार युवकों ने प्रवेश किया।

युवकों ने कहा कि वे अधीर रंजन से मिलने आए हैं। वहां मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि वह अभी नहीं हैं। साथ ही उन्होंने युवकों का संपर्क नंबर पूछा ताकि वे अधीर रंजन को वापस आने के बाद जानकारी दे सकें। लेकिन युवक नंबर देने के बजाय उनसे तुरंत बात कराने के लिए कहने लगे। कर्मचारियों ने मना किया तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए कार्यालय में तोड़फोड़ की। अधीर रंजन चौधरी के पीए आनंद पटेल ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंची पीसीआर ने एक युवक को पकड़ा है। उसने अपना नाम राकेश नरवाल बताया है।

'प्रदर्शन आपका हक, लेकिन रास्ता रोकना सही नहीं'

गौरव वाजपेई, नई दिल्ली

▶ वार्ताकार साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे

शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ चल रहे धरना-प्रदर्शन में मंगलवार एक बार फिर हलचल बढ़ गई। यहां देर शाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकार साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। रामचंद्रन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके प्रदर्शन के हक पर अपनी सहमति दी है, लेकिन अनिश्चितकाल तक रास्ता रोकना सही नहीं है। इसलिए अब आप लोग खुद ही तय करें कि यह प्रदर्शन कैसे और कहां जारी रहेगा। अब हल प्रदर्शनकारियों को ही निकालना है। हम लोगों पर अपने फैसले नहीं थोपेंगे।

साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि कोर्ट ने उन्हे दोबारा बात करने के लिए निर्देशित किया है। ऐसे में हमें उम्मीद है शाहीन बाग के लोग ऐसा हल निकालेंगे जो पूरे विश्व के लिए नजीर बनेगा। जिस समय पूरी दिल्ली दहक रही थी उस दौरान शाहीन बाग ने शांति का संदेश दिया। ऐसे में शाहीन बाग हल भी देगा। इस होली से पहले हम इस समस्या का हल निकाल एक-दूसरे के गले लगेंगे।

दूसरे वार्ताकार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हमें इस मसले का हल संविधान के दायरे में ही ढूंढना होगा। सारे मसलों का हल झगड़े से नहीं निकलता। आप अपने बीच से कुछ लोगों को चुन लें। वे हमें आपकी बातें लिखकर दें जिसपर हम बात कर सकें। उन्होंने कहा कि आप आपस में विचार-विमर्श कर लें और हमें बताएं। जब आप कहेंगे हम जरूर आएंगे। शाहीन बाग चल रहे धरना-प्रदर्शन को मंगलवार को 80 दिन पूरे हो गए। दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद यहां प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार कम हो रही है।

करवट लेगा मौसम, कल बारिश के आसार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिन-ब-दिन बढ़ रहे तापमान के बीच बुधवार से दिल्ली का मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। दिन भर बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को बारिश भी हो सकती है, जबकि शुक्रवार को बारिश के साथ तेज हवा भी चलने के आसार हैं। इससे तापमान में कुछ गिरावट आएगी और लोगों को एक बार फिर ठंडक का एहसास होगा।

मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 41 से 100 फीसद रहा। रिज क्षेत्र मंगलवार को सबसे गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 29.5, जबकि न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, दिल्ली के प्रमुख डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। शाम या रात को कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है।

सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली छह मार्च को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीडीए को सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देने के लिए मास्टर प्लान में बदलाव की अधिसूचना जारी करने से पहले अदालत को अवगत कराने की जरूरत नहीं है। यह परियोजना राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के तीन किमी लंबे मार्ग को कवर करती है। परियोजना के तहत कई नई सरकारी इमारतें और एक नया संसद भवन का निर्माण होना है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका की तत्काल सुनवाई पर गौर किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी इस पीठ में शामिल थे। पीठ ने कहा,'उपयुक्त पीठ के समक्ष छह मार्च 2020 के लिए सूचीबद्ध।' गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने सेंट्रल विस्टा के निर्माण की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए डीडीए को मास्टर प्लान में किसी बदलाव की अधिसूचना जारी करने से पहले अदालत में आने के अपने एक न्यायाधीश के निर्देश पर 28 फरवरी को रोक लगा दी थी। लुटियंस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर के दायरे में सेंट्रल विस्टा का विकास किया जाना है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र तथा डीडीए की याचिकाओं पर निर्देश जारी किया। पीठ ने राजीव सूरी और लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) अनुज श्रीवास्तव को भी नोटिस जारी किया जिनकी याचिकाओं पर 11 फरवरी को आदेश जारी किया गया था।

पीठ ने केंद्र और डीडीए की अपीलों पर आगे की सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय की। सूरी और श्रीवास्तव ने एकल न्यायाधीश के समक्ष अपनी याचिकाओं में इस आधार पर सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध किया था कि इसमें नए संसद भवन और सरकारी दफ्तारों के निर्माण के लिए राजपथ तथा विजय चौक से लगे हरित क्षेत्र के भूमि उपयोग में बदलाव शामिल हैं। उन्होंने दलील दी है कि डीडीए के पास भूमि उपयोग और मास्टर प्लान में प्रस्तावित बदलाव का अधिकार नहीं है और केवल केंद्र सरकार ही यह कर सकती है। एकल न्यायाधीश ने 11 फरवरी के अपने आदेश में कहा था, 'अगर दिल्ली के 2020-21 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित बदलावों को अधिसूचित करने के लिए कोई फैसला लिया जाता है तो डीडीए ऐसे फैसले की अधिसूचना जारी करने से पहले अदालत का रुख करेगा।'

नया कदम

तीन पुराने कॉरिडोर के सिग्नल सिस्टम में बदलाव की तैयारी में डीएमआरसी, 14 साल से अधिक पुराना हो चुका है ब्लू लाइन कॉरिडोर, 86 .21 करोड़ की लागत से ब्लू लाइन पर लगेगा वर्चुअल सिग्नल

तकनीकी खराबी होने पर वर्चुअल सिग्नल से रफ्तार भरेगी मेट्रो

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

मेट्रो नेटवर्क में सिग्नल की खराबी के कारण परिचालन प्रभावित होने की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने तीनों पुराने कॉरिडोर के मौजूदा सिग्नल सिस्टम में तकनीकी बदलाव करने व वर्चुअल सिग्नल लगाने की तैयारी की है। सबसे पहले ब्लू लाइन (द्वारका सेक्टर 21-नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली) पर वर्चुअल सिग्नल लगाया जाएगा। इससे कॉरिडोर के किसी हिस्से पर मुख्य सिग्नल में तकनीकी खराबी होने की स्थिति में वर्चुअल सिग्नल से मेट्रो रफ्तार भर सकेगी। इससे सिग्नल सिस्टम में खराबी होने से परिचालन पर ज्यादा असर नहीं होगा। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

डीएमआरसी 86.21 करोड़ की लागत से ब्लू लाइन पर सिग्नल सिस्टम में तकनीकी बदलाव करेगा। इसके बाद दो अन्य पुराने कॉरिडोर यलो व रेड लाइन पर भी वर्चुअल सिग्नल लगाया जाएगा। ब्लू लाइन पर तकनीकी खराबी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। यह दिल्ली मेट्रो का सबसे व्यस्त कॉरिडोर भी है।

डीएमआरसी का कहना है ब्लू लाइन कॉरिडोर 14 साल से अधिक पुराना हो चुका है। उस वक्त मौजूद तकनीक के मुताबिक इस कॉरिडोर पर सिग्नल सिस्टम लगाया गया था। अब केंद्रीय परिचालन कंट्रोल (ओसीसी) रूम से सिग्नल सिस्टम नियंत्रित होता है। ब्लू लाइन का ओसीसी मेट्रो भवन में मौजूद है और इसका बैकअप ओसीसी केंद्र शास्त्री पार्क स्टेशन के पास है। सिग्नल में तकनीकी खराबी होने पर मेट्रो का संपर्क ओसीसी से कट जाता है और उसकी रफ्तार थम जाती है। ऐसी स्थिति में प्रभावित कॉरिडोर के बड़े हिस्से पर मैनुअल मेट्रो का परिचालन करना पड़ता है। इस वजह से मेट्रो रुक-रुक कर चलती है। डीएमआरसी का कहना है कि ओसीसी व बैकअप ओसीसी के बीच हॉट रिडंडेंसी लगाने की जरूरत है। यह तकनीक पहले मौजूद नहीं थी। इससे यह फायदा होगा कि सिग्नल में तकनीकी खराबी होने पर तुरंत मेट्रो में वर्चुअल सिग्नल सक्रिय हो जाएगा। मेट्रो अपनी तेज गति से ही सुरक्षित इंटरचेंज स्टेशन तक पहुंच सकेगी। इस दौरान मेट्रो स्वचालित ट्रेन परिचालन तकनीक से ही नियंत्रित होगी। यह पूरी तरह सुरक्षित तकनीक है।

फाइल फोटो

पहले ट्रायल फिर इस्तेमाल

डीएमआरसी के अनुसार ओसीसी के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर में भी बदलाव किया जाएगा ताकि अगले 10 सालों तक इस कॉरिडोर पर परिचालन बेहतर हो सके। वर्चुअल सिग्नल का पहले रात में मेट्रो का परिचालन बंद होने के बाद ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले साल मेट्रो में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा।

ब्लू लाइन पर बढ़ाए गए हैं इंटरचेंज स्टेशन : डीएमआरसी का कहना है कि ब्लू लाइन पर पहले के मुकाबले इंटरचेंज स्टेशन बढ़ गए हैं। इस पर सात इंटरचेंज स्टेशन हैं। वर्चुअल सिग्नल सभी इंटरचेंज स्टेशनों व मुख्य सिग्नल के सफ्टवेयर से जुड़ा होगा।

वाहनों के दोबारा पंजीकरण के नियम पर केंद्र से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले वाहनों के दोबारा पंजीकरण के नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दीपक वाजपेयी की याचिका पर हाई कोर्ट ने परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। वाजपेयी ने एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों के स्थानांतरण होने पर उनके दोबारा पंजीकरण करने के नियमों को विचित्र करार दिया है। वाजपेयी ने याचिका में कहा कि दूसरे राज्यों में किए गए रोड-टैक्स का भुगतान वापस लेने में वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

याचिका के अनुसार पहले वाहन मालिकों को दोबारा पंजीकरण के लिए नए राज्य में रोड-टैक्स का भुगतान करना पड़ता है और फिर उक्त रसीद के साथ पिछले राज्य में रोड टैक्स का रिफंड लेने के लिए जाना पड़ता है। उक्त रिफंड वापस लेने के लिए वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग का कई बार चक्कर काटना पड़ता है और इसके वह मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि रोड टैक्स को लेकर परिवहन मंत्रालय को एक समान नीति बनाने का निर्देश दिया जाए।

उन्होंने मांग की कि भारत भर में पंजीकृत वाहनों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया जाए। एक एकीकृत डेटाबेस होगा तो एक राज्य का वाहन दूसरे में पंजीकृत होने पर पहले राज्य में भुगतान किया स्वतः ही नए राज्य के परिवहन कार्यालय में स्थानांतरित हो जाएगा।

1.38 लाख करोड़ के 58 रक्षा सौदे किए हैं भारत ने पिछले तीन साल में। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित बजट का पूरा इस्तेमाल किया। कोई काम या आवंटन अधूरा नहीं है।

संसद में दिल्ली दंगों पर बहस को लेकर टकराव जारी

हालात जस के तस ▶ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला की अंकुशहीन सदस्यों को सत्रभर के निलंबन की चेतावनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली दंगों पर चर्चा को लेकर संसद के दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। जहां विपक्ष तुरंत चर्चा कराए जाने पर अड़ा है। वहीं सरकार इसे होली के बाद कराना चाहती है। सोमवार को लोकसभा में मारपीट की नौबत के बाद मंगलवार को भी वैसी ही स्थिति की आशंका देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सीट छोड़ कर दूसरी तरफ जाने वाले सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की चेतावनी देनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे के कारण दो बार रुकावट के बाद अंततः उपसभापति को पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा।

दिल्ली के दंगों पर चर्चा को लेकर लोकसभा में लगातार दूसरे दिन सदन की कार्यवाही बाधित रही। स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को आगाह किया कि यदि किसी पक्ष के सदस्य ने अपनी सीट छोड़ दूसरे पक्ष की ओर जाने की कोशिश की तो उसे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार शून्यकाल के दौरान दिल्ली हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। परंतु विपक्ष तुरंत चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़ा रहा।

सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई कांग्रेस, तृणमूल, द्रमुक तथा अन्य विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से खड़े हो गए और जोर-जोर से दिल्ली दंगों पर चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी। द्रमुक नेता टीआर बालू ने कहा कि सरकार ने दिल्ली दंगों पर अभी तक संसद में कोई बयान नहीं दिया। जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तुरंत चर्चा शुरू कराए जाने की मांग रखी। इस पर संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठा सकता है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। परंतु फिलहाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता स्थिति को सामान्य बनाने एवं शांति व्यवस्था कायम करने पर है। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी के साथ प्लेकार्ड दिखाने शुरू कर दिए। स्पीकर के 'सदन में प्लेकार्ड की अनुमति नहीं मिलेगी' बयान पर विपक्षी सदस्य और आक्रामक हो गए। सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों ने इसका विरोध किया और अपनी सीट से उठ खड़े हुए। इस बर्ताव से क्षुब्ध बिरला ने पूछा कि क्या सदस्यों को प्लेकार्ड की अनुमति मिलनी चाहिए? फिर उन्होंने सदन को दोपहर तक स्थगित कर दिया।

विपक्षी सदस्यों का वेल में हंगामा : दो बजे सदन शुरू हुआ तो जरूरी कागजात पटल पर रखवाने के बाद स्पीकर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैंकिंग सुधार से जुड़े बिल पेश करने की इजाजत दी। इस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में चले गए और जब विधेयक हंगामे में ही पारित कराया जाने लगा तब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आग बबूला होकर आसन तक पहुंच गए।

लोकसभा में मंगलवार को बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। एएनआइ

राज्यसभा में अनुराग पर निशाना

राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने जैसे ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को सदन में सूचीबद्ध दस्तावेज रखने की अनुमति दी, विपक्ष ने दिल्ली चुनावों के दौरान उनके कथित 'गोली मारो..' बयान को उन्हें निशाने पर ले हंगामा खड़ा कर दिया। वाणिज्य व रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ठाकुर का बचाव करने की कोशिश की। विपक्षी सदस्य दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे थे। जबकि सत्तापक्ष के सदस्य विपक्ष को जिम्मेदार बता रहे थे। हंगामे के बीच सदन दो बजे तक स्थगित हुआ और जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष तुरंत बहस की मांग पर अड़ा रहा। उपसभापति ने सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया।

संसदीय जवाबदेही से भाग रही सरकार : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली दंगों पर संसद में तत्काल चर्चा के लिए राजी नहीं होने के सरकार के रुख को कांग्रेस ने संसदीय जवाबदेही से भागने का उसका प्रयास करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक दंगों पर संसद में तत्काल चर्चा नहीं किए जाने से लोकतांत्रिक दुनिया में भारत की संसदीय प्रणाली की छवि को नुकसान पहुंचेगा। इस रुख से साफ है कि सरकार को संसद और सांसदों के विवेक पर विश्वास नहीं है।

दंगों पर चर्चा कराने को लेकर संसद में जारी टकराव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देश की राजधानी में बड़ी संख्या में मौत और बर्बादी हुई हो तो भला चर्चा के लिए इससे ज्यादा जरूरी विषय क्या हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत सरकार होली के उपरांत हालात सामान्य होने पर चर्चा की बात कह रही है। संसदीय बहस और विचार-विमर्श को सामान्य स्थिति की बहाली का हवाला देकर नहीं रोका जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि संसदीय जवाबदेही से बचने के लिए सरकार दंगों पर तत्काल चर्चा से भाग रही है और यह संसद की घोर अवहेलना है। उनका कहना था कि संसद देश का सबसे बड़ा महा-आयोग है। ऐसे में इसकी जवाबदेही को झुठलाना संसद और सांसदों के प्रति अविश्वास है। सिंघवी ने कहा कि संसद इतने गैर जिम्मेदार या अशिक्षित नहीं कि सदन में चर्चा के जरिये वे भड़काने का काम करेंगे। जब शहर जल रहा हो तब होली के बाद बहस की बात गले नहीं उतरती। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब राजधानी में खून की होली खेली जा रही है तब सरकार का होली के बाद चर्चा की बात कहना उसकी संवेदनहीनता को दर्शाता है।

... और एकाएक एक्टिव मोड में आ गई संसद की सुरक्षा व्यवस्था

- सांसद की गाड़ी के सुरक्षा बैरियर से टकराने से हुआ अलर्ट
- संसद के प्रवेश द्वार पर जवानों ने संभाल लिया मोर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र: संसद भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मंगलवार को अचानक एक्शन मोड में आ गई। सारे सुरक्षा उपकरण स्वतः एक्टिव हो गए और सुरक्षा बलों ने संसद में प्रवेश करने वाले मुख्य गेट पर मोर्चा संभाल लिया। दरअसल, ये सब हुआ भाजपा सांसद की गाड़ी के संसद भवन परिसर में सुरक्षा बैरियर से टकराने के चलते।

यह हादसा सुबह 9.30 बजे हुए। कौशांबी से भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की गाड़ी संसद भवन परिसर में गेट नंबर एक से प्रवेश करते हुए सुरक्षा बैरियर से हल्की सी टकरा गई। गाड़ी के बैरियर से टकराते ही संसद की सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरण अपने आप सक्रिय हो गए और सुरक्षा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जिस समय यह हादसा हुआ सांसद भी गाड़ी में थे या नहीं।

संसद पर आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त बना दिया है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि संसद भवन परिसर के बाहरी गेट पर किसी गाड़ी के टकराने से आगे लोहे के नुकीले ब्रेकर निकल जाते हैं। इस बार भी सुरक्षा बैरियर से टकराने के बाद सांसद की गाड़ी आगे बढ़ी तो नुकीले ब्रेकर से टकरा गई और उसके टायर फट गए।

संसद भवन परिसर में थोड़ी देर के लिए सारे सुरक्षा मानक अलर्ट मोड में आ गए। सांसद जिस गेट से संसद भवन में प्रवेश करते हैं, वहां सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। बाद में सच्चाई का पता चलने पर सभी ने राहत की सांस ली और सांसद की गाड़ी को खींचकर वहां से हटाया गया।

'देश तोड़ने वालों के खिलाफ डटकर खड़े हों'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की हिंसक घटनाओं के बाद मंगलवार को भाजपा सांसदों से पहली बार रूबरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति, एकता और सद्भाव को विकास की आवश्यक शर्त बताकर पार्टी के बयानवीर नेताओं को नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने 'भारत माता की जय' के नारों पर भी सवाल खड़े कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोगों से सबको सतर्क रहने की जरूरत है।

मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में मोदी के बयान को नसीहत की तरह ही देखा गया। पीएम ने कहा कि सांसदों को समाज में आगे आकर मेलजोल बढ़ाने की जरूरत है। ध्यान रहे कि पिछले कुछ दिनों में भाजपा के कुछ नेताओं के बयानों को लेकर काफी विवाद रहा था। मोदी ने कहा कि दूसरे लोगों के लिए राजनीति पहले हैं, लेकिन भाजपा के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सांसदों को इसी के साथ काम करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 'भारत माता जय' पर दिए गए कथित विवादास्पद बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा 'कुछ नेताओं को वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है।' मोदी ने जोर देकर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। गौरतलब है कि एक कार्यक्रम में मनमोहन ने कहा था कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से उग्र और भावनात्मक समाज बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास ही हमारा मंत्र है, जिसे प्राप्त करने के लिए शांति, सद्भाव और एकता पहली शर्त है। 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के अपने चर्चित नारे का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 'मनसा-वाचा-कर्मणा' एकजुट होना होगा।

नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान (बाएं से) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

मोदी से मिले केजरीवाल, दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से दिल्ली में हुए दंगे को लेकर चर्चा की और दंगा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री से अगले पांच साल दिल्ली का विकास करने और दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनसे सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि वह दिल्ली के विकास में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा की। कोरोना वायरस का एक मामला दिल्ली और एक तेलंगाना में आया है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिल कर काम करेंगे।

> मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि ये दंगे कराने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
> -अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

दिल्ली पुलिस की तारीफ की : केजरीवाल ने अफवाह को रोकने में पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि रविवार यानी 2 मार्च को पूरी दिल्ली के अंदर दंगे की जबरदस्त अफवाहें फैली थीं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और सड़क पर उतर कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की इस कोशिश ने बहुत बड़े हादसे को होने से रोक दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि भविष्य में इस तरह की वारदात कभी न हो इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम सबको मिल कर उठाने चाहिए।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर केंद्र ने राज्यों से की चर्चा

संसद में जवाब

- केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा-इसमें कोई कागज नहीं देने होंगे
- सीएए रोधी प्रदर्शनों में शामिल पांच विदेशी नागरिकों को भारत छोड़ना होगा

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार का कहना है कि वह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के नवीनीकरण की तैयारियों को लेकर राज्य सरकारों से चर्चा कर रही है। एनपीआर की प्रक्रिया एक अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगी। इस कवायद के दौरान लोगों से कोई दस्तावेज जमा नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल पांच विदेशी नागरिकों को वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर भारत छोड़कर जाने को कहा गया है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि एनपीआर की प्रक्रिया जनगणना-2021 के हाउस लिस्टिंग चरण के दौरान ही पूरी की जाएगी। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एनपीआर की तैयारियों को लेकर राज्य सरकारों ने जो चिंता जताई थी, उस संबंध में केंद्र उनसे बातचीत कर रहा है। एनपीआर की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से जनसंख्या संबंधी आंकड़े और अन्य संबंधित जानकारियां जुटाई जाएंगी। इस कवायद के दौरान कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे।

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने इसमें आ रहे गतिरोधों को दूर करने के लिए आपत्ति जताने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत शुरू कर दी है। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे कुछ गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जो एनपीआर को लेकर अपनी आपत्तियां जता चुके हैं। इसी कवायद के तहत रजिस्ट्रार जनरल एं सेंसस कमिश्नर विवेक जोशी ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से सेंसस और एनपीआर की तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया है। केंद्रीय कैबिनेट एनपीआर की कवायद के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है।

घुसपैठियों का केंद्र के पास सटीक डाटा नहीं

लोकसभा में नित्यानंद राय ने बताया कि दिल्ली समेत पूरे देश में अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों का कोई सटीक डाटा केंद्र सरकार के पास नहीं है। चूंकि यह लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के चोरी-छिपे या धोखाधड़ी करके भारत में प्रवेश करते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे विदेशी घुसपैठियों को देश के बाहर प्रत्यर्पित करने के लिए विगत 24 अप्रैल, 2014 और 01 जुलाई, 2019 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे।

महीने बाद लोकपाल से शिकायत का प्रारूप जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने लोकपाल में प्रधानमंत्री समेत लोकसेवकों के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों का प्रारूप जारी किया है। यह प्रारूप लोकपाल संस्था के गठन के 11 माह बाद जारी किया गया है।

कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक सभी शिकायतकर्ताओं को अनिवार्य रूप से इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि अगर कोई झूठी, अर्थहीन अथवा गलत शिकायत की जाती है तो यह कार्य अधिकतम एक साल की कैद और एक लाख तक के जुर्माने की सजा के दायरे में आएगा। शिकायत सामान्य रूप से अंग्रेजी में और लोकपाल संस्था द्वारा तय किए गए तरीके के तहत पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत ई-मेल अथवा ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है, हालांकि इस स्थिति में इसकी एक हार्ड कॉपी 15 दिनों के भीतर संस्था के समक्ष जमा करानी होगी। इलेक्ट्रानिक माध्यम से दर्ज कराई जाने वाली शिकायत यदि हर मानक के अनुकूल है तो लोकपाल इसे लंबित नहीं रख सकते। आदेश के मुताबिक पीएम समेत किसी भी लोकसेवक के खिलाफ की जाने वाली शिकायत में आरोपों का विवरण देना जरूरी होगा। लोकपाल हिंदी, गुजराती, असमी, मराठी समेत 22 भाषाओं में की जाने वाली शिकायतें भी स्वीकार करेंगे। लोकपाल किसी भी शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर करेंगे।

लोकपाल की ओर से शिकायतकर्ता और लोकसेवक की पहचान भी तब तक उजागर नहीं की जाएगी जब तक कि जांच पूरी न हो जाए। हालांकि अगर शिकायतकर्ता ने खुद ही किसी अन्य कार्यालय अथवा प्राधिकरण के समक्ष अपनी पहचान बता दी है तो उसकी पहचान न बताने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

क्या है लोकपाल संस्था

लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों के निस्तारण के लिए बनाई गई सर्वोच्च संस्था है। इसका काम केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की निश्चित समयसीमा के भीतर जांच करना है। लोकपाल संस्था में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों और नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी शिकायत का निपटारा शुरुआती स्तर पर लोकपाल की पूर्ण पीठ करेगी, जिसमें अध्यक्ष के अलावा शेष सभी आठ सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई थी।

जम्मू-कश्मीर में वायस कॉलिंग और एसएमएस पर रोक नहीं

नई दिल्ली, एएनआइ: जम्मू-कश्मीर में पोस्ट-पेड और प्री-पेड मोबाइल सेवाओं के वायस कॉलिंग और एसएमएस सुविधा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में यह जानकारी दी। एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सौंपे गए मामलों में 90 फीसद दोष सिद्धि दर हासिल किया है।

रेड्डी ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में पोस्ट-पेड और प्री-पेड मोबाइल सर्विस के वायस कॉलिंग और एसएमएस सुविधा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ प्रतिबंध के साथ फिक्स्ड-लाइन के माध्यम से मोबाइल डाटा सर्विस और इंटरनेट एक्सेस भी बहाल है।' पिछले साल अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध लगा दिया गया था। केंद्र ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त कर करने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने राज्य का दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन कर दिया।एनआइए पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'शुरू से अभी तक केंद्र सरकार ने एनआइए को जांच के लिए 319 मामले सौंपे हैं। कुल दर्ज मामलों में से 237 में आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। 62 मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है जिनमें से 56 मामलों में दोषी ठहराया गया है। इन मामलों में 276 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। दोषी ठहराने की दर 90.32 फीसद है।'देश में पिछले तीन साल के दौरान कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई है।

दंगों पर केजरीवाल ने भाजपा को दी क्लीनचिट : कांग्रेस

- कांग्रेस नेता सिंघवी ने कहा-पीएम से मुलाकात में इसका जिक्र न करना है सुबूत
- बोले-केजरीवाल अब बी टीम नहीं भाजपा मंत्रिमंडल का हिस्सा दिख रहे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली दंगों के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नरम रुख पर लगातार सवाल उठा रही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में दंगों का मुद्दा नहीं उठाने को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि पीएम से मिलने के बाद केजरीवाल ने एक तरह से दिल्ली दंगों को लेकर केंद्र सरकार को 'क्लीनचिट' दे दी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की घेरेबंदी करते हुए कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाजपा के मंत्रिमंडल के सदस्य दिखाई दे रहे हैं।

संसद में दिल्ली के दंगों पर चर्चा को लेकर जारी टकराव के बीच कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कांफ्रेंस में केजरीवाल पर यह हमला बोला। उनका कहना था कि जब मुख्यमंत्री सूबे के मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो उम्मीद की जाती है कि वे दिल्ली के भयावह दंगों में बड़ी संख्या में हुई लोगों की मौत और बर्बादी के मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही इन दंगों में भाजपा नेताओं की भूमिका खासकर नफरत और भड़काऊ भाषण देकर आग में घी डालने वाले कपिल मिश्रा सरीखे उनके नेताओं पर एफआइआर दर्ज नहीं किए जाने पर पीएम से सवाल करेंगे।

सिंघवी ने कहा कि सवाल करना तो दूर मुख्यमंत्री खुद ही एलान करते हैं कि दंगों पर पीएम से उनकी कोई सीधी बात नहीं हुई और इससे साफ है कि केजरीवाल भाजपा की बी टीम नहीं बल्कि उसका हिस्सा हैं। दंगे में हुई मौत और बर्बादी सूबे का इस समय सबसे बड़ा है मगर सीएम जब प्रधानमंत्री से मुलाकात में इसकी चर्चा तक नही करते तो साफ है कि केजरीवाल केंद्र सरकार और गृहमंत्री को क्लीनचिट दे रहे हैं। मौत का आंकड़ा करीब 50 पहुंचने वाला है और ऐसी गंभीर स्थिति से जुड़े मसलों पर पीएम से सवाल नहीं करना हैरान करने वाला है। सिंघवी ने सीएम को घेरते हुए सवाल उठाया कि आखिर चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच नई दोस्ती का राज क्या है? आप की कौन सी कमजोर नस की चाभी केंद्र के पास है जिसके कारण केजरीवाल सरकार ने घुटने टेक दिए हैं।

दो टूक

ईरान के विदेश मंत्री ने सोमवार को दिल्ली हिंसा पर दिया था बयान, भारत ने ईरान के राजदूत को समन कर जताई नाराजगी

दिल्ली हिंसा पर भारत व ईरान के रिश्तों में असहजता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- ईरान के राजदूत को बता दिया गया है कि विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया बयान पूरी तरह से एकतरफा व पक्षपातपूर्ण है
- जनवरी में जरीफ भारत की यात्रा पर आए थे

जावेद जरीफ। फाइल

दिल्ली हिंसा पर तल्खी भरा बयान देने की वजह से भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्तों में भी दरार पड़ती दिख रही है। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने दिल्ली हिंसा पर बेहद सख्त बयान दिया था जिसे भारत ने ना सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि मंगलवार को नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने समन किया और उन्हें भारत की नाराजगी से अवगत कराया।

गौरतलब है कि अमेरिकी दबाव में जब भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया तब भी दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को तल्खी से बचा लिया था। जनवरी, 2020 में विदेश मंत्री जरीफ भारत की यात्रा पर भी आए थे और उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई थी। माना जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत दौरे के दौरान जिस तरह से ईरान के खिलाफ बातें कहीं उसे देखते हुए ही विदेश मंत्री जरीफ ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मंगलवार को कहा, 'ईरान के राजदूत को साफ तौर पर बता दिया गया है कि दिल्ली के बारे में ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया बयान पूरी तरह से एकतरफा व पक्षपातपूर्ण है और यह स्वीकार्य नहीं है। इस तरह के बयान देने से परहेज करना चाहिए।' ईरान के राजदूत अली जेगनी को भारतीय विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था जहां उनसे भारत की प्रतिक्रिया से अवगत कराया गया।

ईरान के विदेश मंत्री जरीफ ने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा था, 'ईरान भारत में मुस्लिमों को लक्ष्य बना कर की गई संगठित हिंसा की निंदा करता है। ईरान सदियों तक भारत का मित्र देश रहा है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चत करे। इस तरह की बेमतलब की हिंसा रोकी जानी चाहिए। शांतिपूर्ण वार्ता और कानून का राज कायम कर ही आगे का रास्ता निकलेगा।'

दिल्ली हिंसा पर पाकिस्तान, इंडोनेशिया समेत कुछ गिने चुने देशों ने ही आधिकारिक स्तर पर अपनी विरोध दर्ज कराया है। अमेरिका व यूरोप के कई राजनीतिक पार्टियों ने संगठन के स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर इस हिंसा को लेकर प्रशासनिक नाकामयाबी पर चिंता जरूर जताई है, लेकिन कुछ बयान देने से दूरी रखी है। ईरान की तरफ से आई टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार खाड़ी के किसी देश ने भी दिल्ली हिंसा को लेकर भारत को घेरने की कोशिश की है। वैसे भारत व ईरान दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अफगानिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित तालिबान का महत्व बढ़ रहा है उसे देखते हुए भारत के लिए ईरान का महत्व बढ़ गया है। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट के निर्माण में अरबों रुपये खर्च कर चुका है और वहां एक आर्थिक क्षेत्र बनाने के साथ ही अफगानिस्तान को उस पोर्ट से रेलवे व सड़क मार्ग से जोड़ने पर भी मोटी रकम खर्च कर रहा है। इसलिए भारत ईरान से संबंध खराब नहीं करना चाहता है। साथ ही ईरान भी भारत से संबंध खराब करने की स्थिति में नहीं है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

4.22 लाख घटनाएं दर्ज हुई हैं 2016 से 2016 के बीच अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध की। ये अपराधी 10 वर्ष में 25 फीसद बढ़े हैं। वर्ष 2016 के 16,654 मामलों में जांच अभी तक जारी है। यह आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 4 मार्च 2020

चुनावी हलफनामा मामले में फड़नवीस पर चलेगा मुकदमा

फैसला ▶ सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की पुनर्विचार याचिका खारिज की, वर्ष 2014 के चुनावी हलफनामे में दो मुकदमों का उल्लेख नहीं करने का आरोप

हाई कोर्ट ने कहा था कि फड़नवीस पर केस चलाने का कोई अधार नहीं बनता

नई दिल्ली, एजेंसियां : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने फड़नवीस की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने चुनावी हलफनामा मामले में ट्रायल चलाने के पिछले आदेश को चुनौती दी थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 के चुनावी हलफनामा मामले में फड़नवीस के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सुनाया था। आरोप है कि फड़नवीस ने हलफनामे में खुद पर चल रहे दो आपराधिक मुकदमों का उल्लेख नहीं किया था।

एक अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट से अलग फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने फड़नवीस को क्लीनचिट देते हुए कहा था कि उन पर जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) के तहत मुकदमा चलाने का कोई अधार नहीं बनता। बांबे

देवेंद्र फड़नवीस फाइल फोटो

हाई कोर्ट के इस फैसले को सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि पिछले साल के फैसले में दखल का कोई आधार नहीं है। पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे। यह फैसला 18 फरवरी को सुनाया गया था, लेकिन शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर इसे मंगलवार को अपलोड किया गया है। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि आरपीए-1951 के तहत हलफनामे में उस आपराधिक मुकदमे का उल्लेख जरूरी नहीं है, जिसमें आरोप गठित नहीं हुआ हो। इसलिए, शीर्ष अदालत को अपने पुराने फैसले पर रोक लगाना चाहिए।

पिछले साल आपराधिक शिकायत पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस फड़नवीस के खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने सतीश की याचिका को स्वीकार कर लिया था। सतीश ने नागपुर के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में फड़नवीस के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) की धारा 125ए के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए आपराधिक शिकायत की थी।

हालांकि, सात सितंबर 2015 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फड़नवीस के खिलाफ सतीश की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सत्र न्यायालय ने फड़नवीस के खिलाफ फैसला दिया था, जिसे उन्होंने तीन मई 2018 को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। फड़नवीस के खिलाफ वर्ष 1996 व 1998 में कथित धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आरोपपत्र दाखिल नहीं हुए हैं। उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125ए के तहत चुनावी हलफनामे में मुकदमा या सजा के संबंध में गलत सूचना देने पर छह महीने जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इससे फड़नवीस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने ब्याज ज्यादा होने पर भी एक्सिस बैंक की एफडी में किया सबसे कम निवेश

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना की नियंत्रण वाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को झटका दिया है। उसने ब्याज ज्यादा होने के बावजूद एक्सिस बैंक के फिक्स डिपॉजिट में सबसे कम निवेश किया। माना जा रहा है कि यह शिवसेना व अमृता फड़नवीस के बीच हुए विवाद का प्रतिफल है। अमृता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी और एक्सिस बैंक की उच्चाधिकारी हैं।

आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, बीएमसी ने जनवरी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में 12-24 महीने तक के लिए 6,300 करोड़ रुपये के 446 फिक्स डिपॉजिट किए। उसने सबसे ज्यादा 7.5 फीसद सलाना ब्याज देने वाले म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक में पांच करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 6.5 फीसद सलाना ब्याज देने वाले एक्सिस बैंक में सिर्फ एक करोड़ रुपये का फिक्स डिपॉजिट किया। दस्तावेज बताते हैं कि एक्सिस बैंक में किया गया निवेश सभी नौ बैंकों में सबसे कम रहा। बीएमसी ने सबसे ज्यादा 329 करोड़ रुपये का फिक्स डिपॉजिट आइसीआइसीआइ बैंक में किया, जो 6.4 फीसद सलाना ब्याज दे रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में मेयर नरेश म्हस्के ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि ठाणे महानगरपालिका के सभी खाते एक्सिस बैंक से हटाकर राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाए जाएं। इसका अमृता फड़नवीस ने विरोध किया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। पिछले सप्ताह ही अमृता ने शिवसेना नेताओं और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को 'कीड़ा' कहा था।

फर्जी प्रमाणपत्र मामले में आजम, अब्दुल्ला व तजीन की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, रामपुर : दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में जेल गए सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। अदालत ने तीनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। इसी मामले में मंगलवार को तीनों को सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया था।

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए हैं। मामले में पुलिस ने सांसद सहित उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हाजिर न होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए थे। इसके बाद ही तीनों ने 26 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था, तब से तीनों जेल में बंद हैं। तीनों की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी लगी थी, जिस पर बहस हुई। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर को पैरवी के लिए लगाया गया था। सरकारी वकीलों ने जमानत प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति जताई। अदालत ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

बिहार चुनाव से पहले फ्रंट फुट पर लोजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **पार्टी के अध्यक्ष चिराग बोले-हमारी तैयारी सभी सीटों पर, विमर्श हिंदू-मुसलमान के बजाय विकास पर हो**
- **कहा-अगर शासन व प्रशासन में खामी है तो उसे सामने रखना जिम्मेदार सहयोगी का कर्तव्य**

बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) की रट ने यूं तो प्रदेश में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है, लेकिन खुद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि वह दरअसल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का ही काम कर रहे हैं। अगर शासन-प्रशासन में कुछ कमी है तो उसे दूर करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक तरह से वह सेफ्टी वाल्व का काम कर रहे हैं। बहरहाल, माना जा रहा है कि हर सीट पर तैयारी के जरिये जहां पिछले चुनाव की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं राजग घटक दलों को यह अहसास भी कराने की कोशिश हो रही है आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा से अलग नहीं होंगे अगर फार्मूले सटीक तैयार हों।

बिहार के सभी जिलों का दौरा करने के बाद लोजपा 14 अप्रैल को पटना में विशाल सम्मेलन करेगी जिसमें बिहार के भविष्य के बारे में रूपरेखा तय होगी। यह एक तरह का मेनिफेस्टो ही होगा। इसी बाबत मंगलवार को दिल्ली में सभी पार्टी सांसदों, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान की मौजूदगी में एक बैठक हुई। उसके बाद चिराग पासवान ने विस्तार से बताया कि उनके दौरे को लेकर भले ही अटकलें चल रही हों, वह राजग के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजबूत बिहार की नींव तो रखी है लेकिन अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। मूलभूत समस्याओं से आगे निकलना है।

इस क्रम में उन्होंने डायल 100 का भी उल्लेख किया और कहा कि कानून व्यवस्था के लिए यह जरूरी उपाय है लेकिन बिहार के कुछ जिलों के अलावा यह कहीं नहीं है। नियोजित शिक्षकों की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब स्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए व्यवस्था है तो नियोजित शिक्षक क्यूं हों।

जाहिर तौर पर ऐसे सवालों के कारण ही बार-बार यह अटकल लग रही है कि चुनाव के वक्त के लिए लोजपा की सोच कुछ और तो नहीं। लेकिन चिराग ने बार-बार इसका खंडन किया और कहा कि पहले बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार में शामिल थी और इसीलिए कुछ सवाल उठाने होते थे तो उसका एक मंच था। लेकिन अब पार्टी सरकार से बाहर है। ऐसे में वह सार्वजनिक तौर पर भी कोई सवाल उठा रहे हैं तो वह राजग और बिहार की सेहत के लिए ही है।

चिराग से साफ किया कि वह हर सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। उम्मीदवार की पहचान का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उम्मीदवारी के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति के कम से कम 25 हजार फालोअर्स हों। चिराग ने यह भी साफ किया कि पार्टी का घोषणापत्र जल्द जारी किया जाएगा। साथ ही, दूसरे दलों से भी अपील कि चुनाव से एक महीने पहले मेनिफेस्टो जारी किए जाएं ताकि विमर्श हिंदू-मुसलमान, जाति संप्रदाय के बजाय विकास पर केंद्रित हो। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए हर सीट पर तैयारी के भी कारण है। सूत्रों के अनुसार पिछले चुनाव के अनुभव से उन्होंने यह सीख ली है। 2015 चुनाव में लोजपा ने जो सीटें मांगी थी उसमें से कई सीटें दूसरे दलों की दे दी गई थीं।

सीएए पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे यूएन मानवाधिकार आयोग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **भारत ने जताया कड़ा ऐतराज, कहा-आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश**
- **कानून बनाना सरकार का अधिकार, बाहरी पक्ष को दखल देने का हक नहीं**

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर पहले तल्ख टिप्पणी करने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने का फैसला किया है। उच्चायुक्त का कहना है कि उनके मन में भारत के सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता व स्वतंत्रता को लेकर काफी इज्जत है और उनका मकसद सीएए के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के बारे में अवगत कराना है। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कई मामले चल रहे हैं और यूएन की इस एजेंसी की कोशिश है कि उसे इनमें एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) के तौर पर शामिल किया जाए। भारत ने इस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत का आतंरिक मामला है और किस तरह का कानून बनाना है यह सरकार का सार्वभौमिक अधिकार है। ऐसे में किसी विदेशी पार्टी को भारत के आतंरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि किसी भी विदेशी पार्टी को भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही नहीं है। सीएए संवैधानिक तौर पर सही कानून है जो हर तरह के संवैधानिक मूल्यों की जरूरतों को पूरा करता है। यह भारत के विभाजन के बाद से उपजे मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों को आदर देने के भारत की पुरानी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून का राज चलता है। हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता पर पूरा भरोसा है और हम इसका पूरा आदर भी करते हैं। हमें उम्मीद है कि कानूनी तौर पर बेहद सुदृढ़ स्थिति माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी सही ठहराई जाएगी।

इसके पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) ने सोमवार शाम को जेनेवा स्थित मुख्यालय में भारत के प्रतिनिधि को इस बारे में जानकारी दी कि वह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने जा रहा है। लेकिन मंगलवार शाम को फिर बताया गया है कि अभी याचिका दायर नहीं की गई है लेकिन जल्द ही कोर्ट के मददगार (एमिकस क्यूरी) के तौर पर आवेदन किया जाएगा। इसका मकसद कोर्ट को यह बताना है कि सीएए जैसे कानूनों को लेकर वैश्विक मान्यता क्या है और मानवाधिकार के वैश्विक मान्य नियमों के लिहाज से यह कितना सही या गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि ओएचसीएचआर को एमिकस क्यूरी बनाया जाए या नहीं। माना जा रहा है कि ओएचसीएचआर पहले से दाखिल देव मुखर्जी के मामले में खुद को एमिकस क्यूरी बनाने का आग्रह करेगा।

ओएचसीएचआर की तरफ से जो आवेदन तैयार किया गया है उसमें वैसे तो सीएए के मूल उद्देश्यों का स्वागत किया गया है और कहा गया है कि सीएए से जिस तरह से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के समक्ष अनिश्चितता की स्थिति खत्म होगी वह स्वागतयोग्य है, लेकिन जिस आधार पर इस कानून में तीन पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है वह उन देशों के दूसरे समुदाय के नागरिकों के लिए भी लागू होना चाहिए। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि इन देशों के हजारा, अहमदिया और शिया मुस्लिमों को भी उसी आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था होनी चाहिए जैसा इन देशों के दूसरे धर्मों के नागरिकों को मिल रही है।

एनपीआर का अध्ययन करेगी त्रिदलीय समिति : उद्धव

राज्य ब्यूरो, मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन विकास अघाड़ी की त्रिदलीय समिति चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधान भवन में पत्रकारों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। सीएए पर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन कर चुके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एनपीआर पर भी लचीला रुख दर्शा चुके हैं, लेकिन मंगलवार को पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार में शामिल तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की समिति विचार करेगी। उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। बता दें कि उद्धव ठाकरे एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध कर चुके हैं। सीएए और एनपीआर के मुद्दे पर कांग्रेस और राकांपा उद्धव पर केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध का दबाव बनाते रहते हैं। उद्धव ने कहा कि वह किसी कीमत पर किसी नागरिक का नुकसान नहीं होने देंगे। बता दें कि कुछ समय पहले उद्धव ने एनआरसी का विरोध करते हुए कहा था कि एनआरसी किसी भी धर्म के नागरिक के लिए उचित नहीं है।

ममता बनर्जी बोलीं, बंगाल में रहने वाले सभी बांग्लादेशी हैं भारतीय नागरिक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- **एक बार फिर दोहराया, सूबे से एक भी व्यक्ति को निकालने नहीं दूंगी**
- **दिल्ली हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना**

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का पुरजोर विरोध कर रहीं बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार को दो-टूक कहा कि बंगाल में रह रहे सभी बांग्लादेशी भारतीय नागरिक हैं। उत्तर बंगाल के दौरे पर पहुंची ममता ने कालियागंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा-'जो लोग बांग्लादेश से आए हैं और यहां मतदान कर रहे हैं, वे भारतीय नागरिक हैं। उन्हें नए सिरे से नागरिकता के लिए आवेदन करने की जरुरत नहीं है। वे ही पीएम और सीएम निर्वाचित करते आ रहे हैं और अब उन्हें ही कहा जा रहा है कि वे इस देश के नागरिक नहीं हैं।' ममता ने के बार फिर दोहराया कि बंगाल में रह रहे किसी भी शरणार्थी को नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। वे बंगाल से एक भी व्यक्ति को निकालने नहीं देंगी।

ममता बनर्जी फाइल फोटो

दिल्ली हिंसा को लेकर बरसीं : मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुई हिंसक वारदातों को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा-'मत भूलिए, यह बंगाल है। दिल्ली में जो हुआ, वो बंगाल में होने नहीं दिया जाएगा। हम बंगाल को दूसरी दिल्ली या उत्तर प्रदेश में बदलते देखना नहीं चाहते।'

...तो बंगाल में हुई हिंसात्मक घटनाओं की भी निंदा कीजिए! : दिल्ली हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रायोजित नरसंहार वाले विवादास्पद बयान पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा-'हर तरह की हिंसा की निंदा की जानी चाहिए। चुनकर हिंसा की किसी घटना की निंदा करना सही नहीं है। इस मामले में राजनीतिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।' धनखड़ हावड़ा में एक कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब थे।

नरसंहार वाले बयान पर बाबुल सुप्रीयो ने तृणमूल प्रमुख पर किया पलटवार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीम ममता बनर्जी के दिल्ली हिंसा को सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने उन पर पलटवार किया है। बाबुल ने कहा कि ममता बनर्जी को नरसंहार का मतलब ही नहीं पता है। उन्हें ऐसे आरोप लगाने से पहले दो बार सोचना चाहिए। ऐसे समय में जब दिल्ली में स्थिति सामान्य हो रही है, उन्हें (ममता) को इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां बंद करनी चाहिए। अगर ममता के पास इस बारे में कोई जानकारी थी या है तो उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को फोन कर बताना चाहिए। बता दें, सोमवार को ममता ने दावा किया था कि दिल्ली हिंसा सुनियोजित नरसंहार है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लोग मारे गए हैं उससे मुझे लगता है कि नरसंहार की योजना बनाई गई थी और बाद में इसे सांप्रदायिक दंगे का रूप दे दिया गया।

बाबुल सुप्रियो की फाइल फोटो। प्रेट्र

गोली मारो... नारे के मामले में एक और भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार : अमित शाह की रविवार को कोलकाता में हुई रैली में जाते समय कथित रूप से 'देश के गद्दारों को, गोली मारो...' नारे लगाने के मामले में कोलकाता पुलिस ने एक और भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को रविवार देर रात ही गिरफ्तार कर लिया था।

योगी ने साफ कहा-गोमाता न लाठी खाएंगी, न कटने जाएंगी

जागरण संवाददाता, मथुरा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को राधारानी के गांव बरसाना पहुंचे। लाडली मंदिर में दर्शन के बाद जनसभा में कहा कि गोमाता को न लाठी खाने देंगे और न कटने के लिए जाने देंगे। उन्होंने गंगा और यमुना की स्थिति बेहतर करने की बात कही। ब्रज क्षेत्र को तीर्थ बनाने के साथ पानी का खारापन दूर करने का गणित भी समझाया। संतों के साथ अर्द्धकुंभ की तैयारी पर उन्होंने चर्चा की। कहा कि ब्रज तीर्थ को शासकीय मान्यता भी मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह ग्यारह बजे यहां पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मांचल पर्वत स्थित लाडलीजी मंदिर में राधारानी के श्रीचरणों में पूजा अर्चना की। वापस राधा बिहारी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में साफ किया कि उनका एजेंडा गाय, गंगा व पवित्र नदियां ही हैं। कहा, हम अच्छे गोआश्रय स्थल बना रहे हैं। हर गाय को जिओ टैग से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। सरकार 4900 से अधिक आश्रय स्थल खोल चुकी है। चार लाख गोवंश की सेवा सरकार कर रही है।

बरसाना के राधा बिहारी इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते योगी आदित्यनाथ जागरण

खाई में गिरने से बची सीएम की कार : लाडली मंदिर से लौट रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि कार की रफ्तार धीमी थी। लाडली मंदिर ब्रह्मांचल पर्वत के शिखर पर है। कार से जाने के लिए घुमावदार रास्ता है। मुख्यमंत्री दोपहर करीब साढ़े 12 बजे लाडली मंदिर से सफारी कार से राधा बिहारी इंटर कॉलेज कार्यक्रम स्थल जा रहे थे। कुछ दूर चलते ही कार यू टर्न पर दीवार से जा टकराई। जिससे कार की हेडलाइट टूट गई है और हल्का डेंट आ गया। मुख्यमंत्री को कोई चोट नहीं आई है।

प्रशांत किशोर को नहीं मिली अग्रिम जमानत, हो सकते हैं गिरफ्तार

जासं, पटना : कंटेंट चोरी व जालसाजी के आरोपित प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रशांत को अग्रिम जमानत देने और उनकी गिरफ्तारी से रोक लगाने इन्कार कर दिया। अदालत ने मुकदमे से संबंधित केस डायरी की मांग की है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए एडीजे 12 की अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन भेज दिया। अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।

अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जिला लोक अभियोजक विजय कुमार सिन्हा ने अपनी दलील में कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। दूसरे के आइडिया को चुराकर आरोपित ने आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त किया है। आरोपित राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली है और पकड़े जाने के डर से इधर-उधर छिप रहा है। अगर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगती है तब वह साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करेगा। मामले में जांच जारी है। आरोपित की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया कि अग्रिम जमानत आवेदन का निष्पादन होने तक कम से कम गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए।

सीएए और एनआरसी नहीं, तृणमूल की नाकामियां होंगी भाजपा का हथियार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल होने वाले निकाय चुनाव में भाजपा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार (एनआरसी) को नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की नाकामियों को अपना हथियार बनाना चाहती है। बंगाल भाजपा सूत्रों के मुताबिक राज्य में सीएए को लेकर मिल रहे कमजोर रिस्पांस को लेकर पार्टी ने यह निर्णय लिया है।

इसके साथ ही भाजपा निकाय चुनाव में सभी वार्डों में एक समीक्षा करना चाहती है, ताकि पता चल सके कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसके बाद भाजपा अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगी। पार्टी सूत्रों का मानना है कि सीएए या एनआरसी पर फोकस नहीं कर तृणमूल की नाकामियों को उजागर करने पर अधिक लाभ होगा। तदनुसार, पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की अध्यक्षता वाली तृणमूल कांग्रेस जिन वादों को पूरा करने में विफल रही है उन सभी को मतदाताओं के सामने पेश करेगी। भाजपा नेता लोगों से उनके विचारों का आदान-प्रदान कर रहे हैं और उन समस्याओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आम लोग ग्रस्त हैं। भाजपा अपने अभियान में लोगों के मुद्दों पर प्रकाश डालेगी।

प्रशांत किशोर फाइल फोटो

पीके ने दिया था सर्वेक्षण पर जोर

बताते चलें कि तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की विफलता को दूर करने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को नियुक्त किया था। उन्होंने जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सर्वेक्षण पर जोर दिया। भाजपा भी इस बार वही रास्ता अपना रही है। वह कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों में सर्वेक्षण कर रही है। भाजपा यह समझने की कोशिश कर रही है कि जनता क्या चाहती है। यह समझना चाहती है कि सीएए-एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं या नहीं।

निकाय चुनाव में सीट समझौते पर वाममोर्चा और कांग्रेस राजी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में आगामी शहरी निकाय चुनाव में सीटों के समझौते पर वामपंथी दलों और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। पहला समझौता कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों को लेकर हुआ है। हालांकि इस पर औपचारिक एलान होना बाकी है। 75 सीटों पर माकपा और महज 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शेष सीटों पर वाम मोर्चा के अन्य घटक दल लड़ेंगे। आगामी कुछ दिनों में हावड़ा नगर निगम को लेकर भी सीटें फाइनल हो सकती है। दूसरी ओर बुधवार को राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारी को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बता दें राज्य सरकार अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक चुनाव कराने के पक्ष में है।

प्रियंका को गुजरात से रास भेजने की पेशकश

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

सियासत

- **गुजरात कांग्रेस देख रही है अपना चुनावी लाभ, चार सीटों के चुनाव के लिए पाला दुरुस्त करने में जुटीं भाजपा-कांग्रेस**

राजस्थान के बाद गुजरात कांग्रेस ने भी आलाकमान से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रदेश से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाने की अपील की है। प्रियंका के गुजरात से राज्यसभा में जाने से कांग्रेस को आगामी चुनावों में लाभ हो सकता है। गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेश धनाणी का कहना है कि प्रदेश इकाई ने पेशकश की है, लेकिन फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है।

गुजरात से राज्यसभा की खाली हो रही चार सीटों के लिए भाजपा-कांग्रेस अपना पाला दुरुस्त करने में जुट गई हैं। भाजपा अपनी तीसरी सीट को बचाने का प्रयास कर रही है तो कांग्रेस सीटों की संख्या बढ़ाने में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष जीतू वाघाणी तथा गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा कांग्रेस विधायकों को पाला बदलने के लिए खुला ऑफर दे रहे हैं। कांग्रेस भी अपने विधायकों को एकजुट करने के साथ पलटवार कर रही है। कांग्रेस विधायक ललित वसोया ने कहा है कि जाने वाले चले गए अब पार्टी में कोई बिकाऊ विधायक नहीं हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा की फाइल फोटो। प्रेट्र

इसी बीच, एसटी प्रमाण पत्र को लेकर विधानसभा से निलंबित विधायक भूपेंद्रसिंह खांट राज्यसभा चुनाव में भाजपा के साथ जाने पर सहमत हैं। खांट अपनी विधानसभा की सदस्यता बचाने व निलंबन खारिज कराने के लिए भाजपा के पाले में जाने को तैयार हैं। खांट पंचमहल की मोरवाहडफ सीट से निर्दलीय विधायक हैं।

गुजरात से राज्यसभा की चार सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। भाजपा की तीन व कांग्रेस की एक सीट खाली होने जा रही है। विधानसभा में भाजपा की सदस्य संख्या 103 है, वहीं कांग्रेस की 73 है। कांग्रेस को एक सीट जीतने के बाद दूसरी सीट के लिए प्रथम मतों की संख्या करीब 36 होती है जबकि भाजपा के दो सीटें जीतने के बाद प्रथम मतों की संख्या करीब 29 होती है। कांग्रेस दूसरी सीट जीतने के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ ही राकांपा, बीटीपी व निर्दलीय जिग्नेश मेवाणी से भी समर्थन की उम्मीद कर रही है। जिग्नेश भाजपा के विरोध में हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर उनका सवाल है कि कांग्रेस को उनके समर्थन की दरकार कहां है। कांग्रेस उन्हें अपने साथ मानकर चल रही है, लेकिन इस संबंध में उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है।

70 देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इससे अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 90 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।

देशों के कोरोना से निपटने के अनोखे उपाय

कोरोना वायरस की गति थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तक 70 देशों में यह खतरनाक वायरस पहुंच चुका है और भारत में भी इसने दस्तक दे दी है। डॉक्टर भी इसके शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में अब रोबोट काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें उनकी बीमारी का अंदाजा नहीं है या वो स्वास्थ्य परीक्षण से होकर नहीं गुजरे हैं और सामान्य जीवन बिता रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने सावधानी को ही इस वायरस से निपटने का सबसे बड़ा उपाय बताया है। दुनियाभर के वैज्ञानिक इससे निपटने का रास्ता तलाश रहे हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाथ धोने के तरीकों के बारे में गाइडलाइन जारी की है, तो फ्रांस समेत कई देशों ने जीवन शैली के तरीकों में बदलाव लाया है।

बदला मुलाकात का परंपरागत तरीका

फ्रांस की सरकार ने संक्रमण से बचने के लिए लोगों से मुलाकात के परंपरागत तरीके (गाल पर चुंबन और हाथ मिलाना) में बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने कहा कि मुलाकात के दौरान किसी भी शारीरिक क्रिया से परहेज किया जा रहा है। हाल ही में जर्मनी के मंत्री होर्स्ट जीहोफर के द्वारा एंजेला मर्केल से हाथ मिलाने से परहेज करने वाला वीडियो काफी वायरल हुआ।

दस्तानों का करें प्रयोग

विज्ञान लेखक लॉरी गैरेट दस्तानों के प्रयोग का सुझाव देती हैं। वो कहती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सामाजिक समूह में रहने के दौरान दस्तानों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इससे किसी भी सामाजिक वस्तु का प्रयोग करने में कोई हानि नहीं होगी। इसी के साथ वो घर और गाड़ी में खिड़की खोलने से परहेज करने को कहती हैं। साफ और सूखे तौलिए का प्रयोग उचित बताती हैं।

एयर हैंडशेक का वीडियो वायरल

ऐसे में एक कार्यक्रम के बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर रिचर्ड मैकन ने वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो एयर हैंडशेक कर रहे हैं।

पांच बार हाथ धोएं

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस से निपटने के लिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा है। इसके लिए हाथों की सफाई को प्रमुखता दी है और दिन में कम से कम पांच बार हाथ धुलने का सुझाव दिया। डब्ल्यूएचओ ने हाथ को कब और कैसे धुलने का तरीका भी बताया है।

कब धोएं
- छींकने और खांसने के बाद।
- बीमार व्यक्ति से मुलाकात के बाद।
- शौचालय के इस्तेमाल के बाद।
- खाने बनाने और खाने के बाद।
- पशुओं को छूने के बाद।

ध्यान रखें
- खांसी या छींकने पर टिशू का प्रयोग करें।
- अगर कोई व्यक्ति आपके बिल्कुल पास में खांसी या छींके तो कुछ सेकेंड तक टुकड़ों में सांस लें।

दरवाजे के हत्थे को संभलकर छुए

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीफ्सवाल्ड के प्रोफेसर गुंटर काम्फ का कहना है कि ठोस धरातल के बार-बार इस्तेमाल से कोरोना वायरस सबसे तेजी से फैलता है। इस स्थिति में किसी धरातल को कोई संक्रमित व्यक्ति इस्तेमाल करता है और उसी को दोबारा कोई स्वस्थ व्यक्ति छूता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। उन्होंने कहा कि दरवाजे के हत्थे समेत ट्रांसपोर्ट के दौरान ऐसी तमाम वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे परहेज करना चाहिए या इस्तेमाल के समय सावधानी बरतनी चाहिए।

लिफ्ट में बटन दबाने के लिए करें पेन का प्रयोग

सिंगापुर के मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर वांग लिन फा के मुताबिक इस वातावरण में लिफ्ट सबसे ज्यादा घातक है क्योंकि उसी बंद लिफ्ट की हवा में कई लोग सांस लेते हैं और बटन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उन्होंने लिफ्ट में बटन दबाने के लिए पेन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने शौचालय का इस्तेमाल करते समय खास सावधानी बरतने को कहा।

चेहरे को छूने से करें परहेज

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थी एलिस्टेयर माइल्स की मानें तो लोगों को बार-बार अपने चेहरे को छूने से बचना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि अपने चेहरे, नाक और आंखों को न छुएं। वो कहते हैं कि यदि आपके हाथ किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित भी हैं तो आप ऐसा करके शरीर के अंदर पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

मास्क कारगर नहीं

डॉ सिमॉन क्लार्के कहते हैं कि दुकानों पर मिलने वाले मास्क कोरोना वायरस से बचाव में कारगर नहीं है क्योंकि इसके वायरस इतने छोटे हैं कि आसानी से मास्क को पार कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आम स्थिति से मास्क पहनना फिर भी बेहतर है।

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचें

इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने भीड़भाड़ से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए फुटबॉल मैच इत्यादि आयोजनों को निरस्त कर दिया गया है।

26 प्रकार के बल्क ड्रग्स के निर्यात पर प्रतिबंध

सख्त रुख ▶ दवाओं की किल्लत की आशंका के चलते सरकार का फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चीन से फैले कोरोना वायरस की वजह से भारत में दवाइयों की किल्लत की आशंका को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को 26 प्रकार के बल्क ड्रग्स (कच्चे माल) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सरकार की इजाजत लेकर निर्यातक इन ड्रग्स का निर्यात कर सकते हैं। दवा कंपनियां इन ड्रग्स के निर्यात पर रोक की मांग कर रहे थे ताकि घरेलू स्तर पर दवा बनाने के लिए कच्चे माल की कमी न हो।

सरकार की तरफ से पिछले सप्ताह 54 प्रकार की दवाओं से जुड़े बल्क ड्रग्स की समीक्षा की गई थी। इनमें से 34 प्रकार के बल्क ड्रग्स को अति आवश्यक श्रेणी में रखा गया था। इनके निर्यात पर सरकार लगातार नजर रख रही है। फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के कार्यकारी सचिव सुदेश कुमार के मुताबिक कच्चे माल की कमी होने से पिछले 15 दिनों में दवा निर्माण की लागत 30-40 फीसद तक बढ़ चुकी है। लेकिन दवा के दाम पर सरकारी नियंत्रण होने की वजह से फिलहाल आम उपभोक्ताओं को बढ़ी कीमत नहीं देनी पड़ रही है। भारत दवा निर्माण के लिए 70 फीसद बल्क ड्रग्स का आयात चीन से करता है। लेकिन चीन से फिलहाल सप्लाई बंद है। घरेलू स्तर पर भी जो बल्क ड्रग्स बन रहे थे, उनका निर्यात किया जा रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से मंगलवार को 26 बल्क ड्रग्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें पैरासिटामॉल भी शामिल है। चीन से बल्क ड्रग्स की सप्लाई रुक जाने के बाद से 250 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाले पैरासिटामॉल की कीमत 415 रुपये के स्तर पर पहुंच गई थी। एजिथ्रोमाइसिन की कीमत 30,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 55,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। ऐसे ही, अन्य प्रकार के कई बल्क ड्रग्स की कीमत में 50 फीसद तक का इजाफा हो चुका है। सरकार के आदेश के बाद भारत से बल्क ड्रग्स निर्यात करने वाले निर्यातकों को पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। अभी कारोबारी सरकारी इजाजत के बिना बल्क ड्रग्स का निर्यात कर सकते थे। हिमाचल प्रदेश फार्मा मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर सतीश सिंघल ने बताया कि चीन भारत समेत विश्व के कई देशों को बल्क ड्रग्स की सप्लाई करता है। फिलहाल वहां से सप्लाई रूकने की वजह से यूरोपीय देश भारत से बल्क ड्रग्स मंगा रहे थे। भारत का सालाना बल्क ड्रग्स का आयात 3.5 अरब डॉलर का है। भारत सालाना 22.5 करोड़ डॉलर के बल्क ड्रग्स का निर्यात करता है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को मास्क पहनकर ताजमहल परिसर का भ्रमण करते पर्यटक। आगरा में छह लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। प्रेट्र

इटली, ईरान, द. कोरिया और जापान से आने पर लगा प्रतिबंध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चीन के बाद चार और देशों से आने के लिए जारी वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त
- भारतीयों को भी ऐसे देशों की यात्रा न करने की सलाह, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई

कोरोना संक्रमण के नए मामले आने आने के बाद केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान से आने के लिए जारी वीजा को रद कर दिया है। इससे पहले सरकार ने पांच फरवरी को ऐसी ही एडवाइजरी जारी कर चीन से आने के लिए जारी वीजा को भी रद कर दिया था। इन देशों के यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है। अगर किसी के लिए भारत आना बहुत जरूरी हो तो उसे नए सिरे से वीजा का आवेदन करने को कहा गया है।

चीन के बाद अब दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के प्रसार को देखते हुए सरकार ने भारतीय नागरिकों को भी विदेश यात्राओं से बचने की हिदायत दी है। खासकर वायरस की चपेट में आ चुके देशों की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। हालांकि सरकार ने इन प्रतिबंधों से राजनयिकों, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, अनिवासी भारतीय (ओसीआइ) कार्ड होल्डर और विमान के क्रू मेंबर आदि को अलग रखा है, लेकिन उन्हें भी चिकित्सीय जांच से गुजरना होगा।

यात्रियों से हवाई अड्डों पर भरवाया जाएगा घोषणा पत्र: इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले प्रत्येक यात्री से हवाई अड्डों पर एक घोषणा पत्र भराया जा रहा है, जिसमें फोन नंबर, भारत में रहने के दौरान पता और तीन मार्च के पहले की गई यात्रा का विवरण मांगा जा रहा है। इन दौरान सबसे पैनी नजर पर्यटकों पर रखी जा रही है। इनमें वे भी शामिल हैं, जो सीधे या कोरोना प्रभावित देशों से घूमते-फिरते भारत आए हैं। सरकार ने ऐसे पर्यटकों की पहचान कर इनका मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं।

नोएडा में कोरोना की दस्तक की आशंका से हड़कंप

- सेक्टर-135 स्थित श्री राम मिलेनियम स्कूल में 3 बच्चों सहित छह लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए
- दो परिवारों के सदस्यों को आइसोलेट कर रखी जा रही निगरानी, संबंधित स्कूल तीन दिन के लिए बंद

जागरण संवाददाता, नोएडा : कोरोना वायरस ने अब दिल्ली-एनसीआर में भी दस्तक दे दी है। मंगलवार को नोएडा से छह लोगों के सैंपल कोरोना वायरस की जांच के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को भेजे गए हैं, जिसमें से तीन सैंपल नोएडा सेक्टर-135 स्थित श्री राम मिलेनियम स्कूल के बच्चों के हैं। स्कूल को छह मार्च तक बंद कर दिया गया है। स्कूल में आइसीएसई बोर्ड की 10वीं व आइएससी की 12वीं की बोर्ड परीक्षा ग्रेटर नोएडा के सेंट जोसेफ स्कूल में स्थानांतरित कर दी गई है और आंतरिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। श्री राम मिलेनियम स्कूल को छह मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं, शिव नाडर स्कूल और बिलबोंग स्कूल ने सतर्कता के चलते छह मार्च तक स्कूल बंद कर दिए हैं।

श्री राम मिलेनियम स्कूल के तीन बच्चे अपने परिजनों के साथ शुक्रवार को दिल्ली के मयूर विहार में एक समारोह में गए थे। सोमवार को बच्चा अपने दोस्तों के साथ स्कूल में गया था। इस बीच दिल्ली में उसके पिता की स्वास्थ्य जांच में उन्हें कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई। उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य विभाग की सूचना पर नोएडा के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार रात में ही पीड़ित व्यक्ति सहित दोनों परिवारों के घर आइसोलेट कर उनके सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। मंगलवार को जब स्कूल प्रबंधन और वहां पढ़ रहे बच्चों को इस बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया। जानकारी पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल पहुंचकर उसे खाली करवाया और वहां सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया।

बुधवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अगली कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को जिले के सभी स्कूलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ डॉ. अनुराग भार्गव ने बताया कि संदिग्धों के घरों को आइसोलेट किया गया और वहीं से उनके सैंपल लिए गए हैं। स्कूल को सैनिटाइज किया गया है।

कोरोना वायरस की हर कड़ी पर पैनी निगाह

नीलू रंजन, नई दिल्ली

चूक की गुंजाइश नहीं

- संक्रमित या संदिग्ध के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर निगरानी का पुख्ता प्रबंध
- साथ सफर करने वाले यात्रियों व विमान के चालक दल पर भी रखी जा रही है नजर

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा-देश के भीतर नहीं फैला संक्रमण

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी तक भारत के भीतर कोरोना से किसी के ग्रसित होने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोरोना से ग्रसित सभी छह व्यक्ति विदेशी धरती पर वायरस से ग्रसित होने के बाद भारत में आए थे। केरल में जो तीन व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, उनके संपर्क में आने वालों पर भी ऐसी ही निगरानी रखी गई थी और वायरस को फैलने से पूरी तरह रोकने में सफलता मिली थी।

देश में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने के बाद सरकार इसे फैलने से रोकने की हरसंभव कोशिश में जुटी है। इसके तहत वायरस से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति और फिर उन व्यक्तियों के संपर्क में आने वालों तक पर निगरानी रखी जा रही है। उनमें से किसी में भी वायरस से संक्रमण की आशंका पाए जाने पर उन्हें विशेष वार्ड में निगरानी में रखा जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर जिला व स्थानीय प्रशासन तक की इकाई को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि निगरानी में कोई कड़ी ना छूटे।

सतर्कता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में इससे ग्रसित व्यक्ति के अलावा उसके व उसके परिवार के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की तत्काल पहचान कर उन पर निगरानी शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि 20 फरवरी को इटली से आने वाले संक्रमित व्यक्ति ने दिल्ली के फाइव स्टार होटल में अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी दी थी, जिसमें आगरा के छह लोग भी शामिल हुए थे।

इसके साथ ही नोएडा के दो स्कूलों में पढ़ने वाले पांच बच्चे भी पार्टी में शामिल थे। पार्टी में शामिल आगरा के सभी लोगों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विशेष निगरानी में रखा गया है। नोएडा के दोनों स्कूलों में जिला चिकित्सा अधिकारियों ने दौरा कर हालात का मुआयना किया और इसके बाद इनको वायरस मुक्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया गया। स्कूलों ने अपने यहां पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों को स्वच्छता पर ध्यान देने और सर्दी-जुकाम व बुखार की स्थिति में डॉक्टरों से संपर्क करने का सुझाव दिया है। कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले एक अकाउंटेंट को भी विशेष निगरानी में रखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आगरा के जिन छह लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है, उनके परिवार के सदस्यों व उनके साथ संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को दी गई है। इनमें से किसी को भी सर्दी-जुकाम और बुखार होने की स्थिति में आइसोलेट कर जांच और इलाज की व्यवस्था की जाएगी।

होटल में भी सतर्कता : जिस हयात होटल में पार्टी दी गई थी, उसने पार्टी के स्थान को वायरस मुक्त करने के लिए विशेष सफाई के साथ-साथ पार्टी के दौरान वहां मौजूद सभी स्टाफ को 14 दिनों के लिए आइसोलेट करने की व्यवस्था की है। दुबई से आए तेलंगाना के वायरस ग्रसित व्यक्ति से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों पर ऐसी ही निगरानी शुरू कर दी गई है।

विमान के क्रू मेंबर भी निगरानी में : कोरोना से ग्रसित व्यक्ति जिन विमानों से भारत आए थे, उनके क्रू-मेंबर को भी विशेष निगरानी में रखा गया है। विमान में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से संपर्क कर उन्हें बता दिया गया है कि उनके साथ आने वाला एक व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, इस कारण उन्हें 14 दिनों तक अपना विशेष ध्यान रखना है। इस बीच सर्दी-जुकाम और बुखार होने की स्थिति में वे तत्काल सूचित करें। इनमें कई लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने अपना निजी नंबर दे दिया है।

जयपुर के मरीज से जुड़े लोग भी दायरे में : जयपुर में कोरोना से ग्रसित इटली के नागरिक के संपर्क में आने वालों की भी पहचान कर उन्हें अलग किया जा रहा है। उनके साथ यात्रा करने वाले इटली के अन्य 19 पर्यटकों व उन्हें सफर कराने वाले बस ड्राइवर, क्लीनर व गाइड को आइटीबीपी के चावला कैंप में रखा गया है। इसके साथ ही ये पर्यटक जिन-जिन होटल में रुके थे, उन्हें अपने स्टाफ पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।

हवाई अड्डों पर वायरस से बचाव के सख्त उपाय लागू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए विमान सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों के बचाव एवं सुरक्षा के बाबत एयरपोर्ट ऑपरेटरों तथा एयरलाइनों को निर्देश जारी किए हैं। इनमें ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, क्रू मेंबर, एयरपोर्ट तथा एयरलाइनों से जुड़े सभी कर्मचारी शामिल हैं।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को विशेष सफाई एवं बचाव के उपाय अपनाने होंगे। इनमें सर्जिकल मास्क, दस्ताने, डिस्पोजेबल शू कवर जैसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) का इस्तेमाल शामिल है। विमानों की सफाई करने वाले सभी कर्मचारियों को पीपीई का उपयोग करने को कहा गया है। हर विमान को सफाई के साथ-साथ अल्कोहल आधारित डिसइंफेक्टैंट के जरिये विसंक्रमित करना होगा। भारत आने व अगली उड़ान पर रवाना होने से पहले हर अंतरराष्ट्रीय विमान व उसके यात्रियों को विसंक्रमण की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

दक्षिण कोरिया, जापान तथा इटली से भारत आने वाले विमानों पर खास नजर रहेगी। भारत आने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को अगली उड़ान से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। नॉन एयरोब्रिज बे के अलावा यात्रियों को बे से टर्मिनल बिल्डिंग तक लाने वाले वाहनों तथा कोरोना से संक्रमित संदिग्ध यात्री वाली व्हील चेयर्स को भी विसंक्रमित किया जाएगा। इस्तेमाल के बाद सभी पीपीई को उचित तरीके से डिस्पोज करने की सलाह भी दी गई है। सभी क्रू सदस्यों को व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देने तथा पीपीई का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, चेक-इन काउंटर आदि पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अनिवार्य रूप से पीपीई प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उन्हें उद्घोषणाओं, बैनर, पोस्टर आदि के जरिये संक्रमण से बचाव की जानकारी देनी होगी। उन्हें हाथ स्वच्छ रखने के लिए चेक-इन काउंटर, टर्मिनल एक्जिट एरिया, थर्मल स्क्रीनिंग वाले स्थानों पर हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। विमानों के भीतर पर्याप्त मात्रा में हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।

हरियाणा विधानसभा में गर्माई सियासत

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़ : कोरोना वायरस को लेकर मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में सियासत गर्मा गई। दरअसल, विधायकों को विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बजट भाषण का सार जिन टैब में बांटा गया, वह चीन की कंपनी में निर्मित हैं। यही वजह रही कि कुछ विधायकों ने इनको खोलकर देखा तो कुछ ने कोरोना वायरस के डर से इनका इस्तेमाल ही नहीं किया। विधानसभा में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किया कि कहीं इन टैब में कोरोना वायरस तो नहीं है। उधर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि विधायक हाथ न मिलाएं। उन्होंने इससे बचने की सलाह दी।

इस बीच, हयिाणा सरकार ने टैब में कोरोना वायरस की आशंका को पूरी तरह से खारिज कर दिया फिर भी इस मुद्दे पर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने एकजुटता के साथ मनोहर लाल सरकार को घेरा तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने समूचे सदन को हाथ न मिलाने का सुझाव दे डाला। विज ने कहा कि कोरोना से बचने का सबसे आसान फार्मूला है कि हाथ मिलाने की बजाय आपस में एक-दूसरे को नमस्ते करें।

अभय चौटाला के यह कहने पर कि चीन से दवाओं का साल्ट आ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में जानकारी दी कि चीन से आने वाले साल्ट की खरीद को रोक दी गई है। सरकार के पास दवाओं का पूरा स्टॉक उपलब्ध है। इसके बावजूद आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत की जा रही है।

हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने मंगलवार को एक ट्वीट और पत्र के जरिये पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ स्टाफ को मास्क व दस्ताने पहनकर ड्यूटी करने को कहें। सभी पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस महानिरीक्षकों व उप महानिरीक्षकों के साथ अन्य अधिकारियों से कहा गया है कि वे सरकार के इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें।

मंथन

भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा कई विकल्पों पर विचार, मंदी से लड़ने के लिए प्रोत्साहन की भी हो रही तैयारी

आरबीआइ सतर्क, ब्याज दरों में कटौती मुमकिन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के धीरे धीरे 70 देशों में फैलने की खबर से सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) भी बेहद सतर्क हो गया है। आरबीआइ व वित्त मंत्रालय की तरफ से इस वायरस से इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को लेकर लगातार मंथन जारी है। आरबीआइ इसके आर्थिक दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है और संकेत हैं कि जिस तरह से वर्ष 2008-09 के वैश्विक मंदी से लड़ने के लिए उद्योग जगत को कई तरह के प्रोत्साहन दिए गए थे उसी तरह के कदम इस बार भी उठाए जाएंगे। कर्ज की दरों में और कटौती करने का विकल्प भी सरकार के सामने है।

आरबीआइ ने शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि केंद्रीय बैंक वैश्विक व घरेलू स्थितियों पर नजर रखे हुए है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'हम सतर्क हैं और वित्तीय स्थायित्व , निवेशकों का भरोसा और बाजार का संचालन दुरुस्त बनाए रखने के लिए यथोचित कदम उठाने को तैयार हैं।' आरबीआइ गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने मीडिया को बताया कि भारतीय इकोनोमी पर कोरोना वायरस की वजह से दो तरह से असर पड़ने के आसार हैं। पहला यह कि हम चीन के बड़े साझेदार है जहां इस वायरस का सबसे ज्यादा असर है। दूसरा इसकी वजह से वैश्विक मंदी की संभावना गहरा रही है जो भारत पर असर डाल सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि वैसे तो महंगाई दर व ब्याज दरों को लेकर आगामी फैसला तीन अप्रैल से मौद्रिक नीति समिति की बैठक में होगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय बैंक पहले भी उपायों की घोषणा कर सकता है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि ब्याज दरों में कटौती भी संभव है।

भारतीय रिजर्व बैंक। फाइल

गौरतलब है कि पिछले महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान आरबीआइ ने सीधे तौर पर रेपो रेट घटा कर ब्याज दरों को नीचे लाने का उपाय नहीं किया था लेकिन ब्याज दरों में नरमी के लिए कुछ दूसरे उपायों का एलान किया था। साथ ही यह भी संकेत दिया था कि रेपो रेट में कटौती की संभावनाएं अभी बनी हुई है। आरबीआइ की तरफ से यह बयान देने के पीछे एक बड़ा मकसद भारत के शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे विदेशी संस्थागत निवेशकों को भी आश्वस्त करना है जो पिछले एक हफ्ते से अपना निवेश निकालने में लगे हुए हैं। कई वैश्विक एजेंसियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक विकास दर को लेकर नई अनिश्चितता पैदा हो गई है। आरबीआइ का यह आश्वासन तब आया है जब दुनिया के कई विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच भी कोरोना वायरस के आर्थिक असर को थामने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है।

नौसैनिक अभ्यास 'मिलन 2020' टला

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए नौसेना ने एहतियात के तौर पर बहु-राष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास 'मिलन 2020' को टाल दिया है। देशभर में कोरोना के करीब 8 मामले अब तक सामने आ चुके हैं।

विशाखापत्तनम के तट पर होने वाला इस बहु-राष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को अभी टाल दिया गया है। मिलन नौसैनिक अभ्यास 18 से 28 मार्च के बीच होना तय था। इस नौसैनिक अभ्यास में 40 देशों के भाग लेने की उम्मीद थी। अधिकारियों ने बताया, 'सभी हिस्सेदारों की सुरक्षा और कोविड-19 के फैलने से लगे यात्रा प्रतिबंधों' को ध्यान में रखते हुए नौसैनिक अभ्यास को अभी स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 'मिलन 2020' को बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी। दुनियाभर की नौसेना ने इस अभ्यास में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में यह अभ्यास करेगी।

19 लाख से ज्यादा लोगों को (जो असम में एनआरसी से बाहर रखे गए हैं) 20 मार्च से रिजेक्शन स्लिप जारी करने की योजना बनाई जा रही है। यह जानकारी असम सरकार ने दी है। इस स्लिप में संबंधित व्यक्ति को एनआरसी से बाहर रखने के कारण बताए जाएंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 4 मार्च 2020

छह युवकों को आतंकी बनने से रोका

राज्य ब्यूरो श्रीनगर

- पुलिस ने काउंसिलिंग के बाद युवकों को परिजनों के हवाले किया
- कश्मीर में दो माह में 22 लड़कों को आतंकी संगठनों के चंगुल से बचाया गया

आतंकी संगठनों में स्थानीय युवकों की भर्ती पर रोक लगाने के अपने अभियान को जारी रखते हुए पुलिस ने बड़गाम में छह और युवकों को समय रहते बचा लिया। इन युवकों को काउंसिलिंग के बाद उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पिछले दो महीने में पुलिस ने कश्मीर में करीब 22 लड़कों को आतंकी संगठनों के चंगुल में जाने से बचाया है।

सूत्रों ने बताया कि जिला बड़गाम के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले छह युवक बीते कुछ दिनों से लगातार आतंकी संगठनों के हैंडलरों के साथ संपर्क में थे। इनमें से कुछ लड़के आइएस और अल कायदा की विचारधारा से भी प्रभावित थे। ये सभी लड़के आतंकी संगठनों में सक्रिय होने के लिए अपने-अपने घरों से निकल रहे थे। इस बीच, पुलिस को अपने तंत्र से इनके बारे में पता चला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ लिया। इन युवकों की गिरफ्तारी में इनके परिजनों की भूमिका भी अहम रही। उन्होंने भी अपने संसाधनों से पुलिस को पूरा सहयोग किया। इन युवकों के खिलाफ पुलिस ने किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया है।

इन युवकों को काउंसलिंग प्रदान करते हुए उन सभी कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया है, जिनसे प्रभावित होकर ये जिहादी संगठनों का हिस्सा बन रहे थे। इन युवकों से पुलिस को सोशल मीडिया व अन्य तरीकों से सक्रिय आतंकी संगठनों में भर्ती करने वाले उनके ओवरग्राउंड वर्करों के काम करने का तरीका भी पता चला है।

पुलिस प्रवक्ता ने बड़गाम में छह युवकों के आतंकियों के जाल में फंसने से बचाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां अपने नेटवर्क के जरिए आतंकी संगठनों के लिए नयी भर्ती में जुटे तत्वों की लगातार निगरानी कर रही हैं। बीते दिनों के दौरान ऐसे कई तत्व पकड़े गए हैं। इसके अलावा जिहादी संगठनों में स्थानीय युवकों की भर्ती रोकने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इन्हीं उपायों के चलते 22 लड़कों को जिहादी बनने से बचाया गया है।

अब कश्मीर में गूंजेंगे एक भारत के नारे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर घाटी में पथराव और गोलियों की शांत होने के बाद अब यहां नए भारत के नारे गूंजेंगे। देश के विभिन्न राज्यों से करीब 250 युवा एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाने के लिए बुधवार को जमा हो रहे हैं। राष्ट्रीय एकता शिविर के तहत यह नौजवान पांच दिनों तक वादी में ही रहेंगे। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू 6 मार्च को आएंगे और शिविर में नौजवानों से सीधा संवाद करेंगे।

जम्मू-कश्मीर विशेषकर कश्मीर घाटी में बीते एक दशक में यह अपनी तरह का पहला शिविर है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, असम, गुजरात और मध्यप्रदेश के युवा हिस्सा ले रहे हैं। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च तक चलने वाले इस शिविर में युवाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनके ठहरने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था के साथ ही आयोजन स्थल पर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए आवश्यक स्टाफ भी नियुक्त किया गया है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन श्रीनगर के एक अधिकारी गुलजार अहमद ने बताया कि हमने सभी तैयारियां कर ली हैं। फिजिकल एजुकेशन कॉलेज गदूरा, गांदरबल के परिसर में हो रहे इस राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेने वाले नौजवान अपने राज्यों की कला, संस्कृति पर भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। शिविर में नौजवानों के अलग-अलग समूह बनाकर उनमें देश की एकता, अखंडता और सौहार्द को मजबूत बनाने की भावना से जुड़े मुद्दों पर भी संवाद कराया जाएगा। यह युवा सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे।

केंद्र के अधिकारी ने बताया कि यह शिविर पूरे देश में एकता, शांति व सौहार्द का संदेश देगा। इसमें भाग लेने वाले नौजवान अपने घरों में जाएंगे तो कश्मीर के शांतिदूत बनकर जाएंगे। इनकी आमद कश्मीर में जहां हालात सामान्य होने की पुष्टि कर रही है, वहीं देश के हर हिस्से में इनका पैगाम कश्मीर की तरक्की व खुशहाली का जरिया बनेगा। कश्मीर में जो अलगाववाद और आतंकवाद को लेकर चर्चा होती है, वह खत्म होगा।

श्वान को बचाने में जान गंवाने वाले मेजर का झांसी में अंतिम संस्कार

नईदुनिया, झांसी : जम्मू-कश्मीर में तैनाती के दौरान श्वान (कुत्ते) को बचाते समय जान गंवाने वाले झांसी के मेजर अंकित बुद्धिराजा का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 35 वर्षीय मेजर अंकित के पिता विजय कुमार बुद्धिराजा एल्डिगो कॉलोनी में रहते हैं। वे बीएचईएल से सेवानिवृत अधिकारी हैं। मेजर का विवाह साढ़े चार वर्ष पहले भोपाल निवासी अनुभूमि से हुआ था।

मेजर अंकित जम्मू-कश्मीर में तैनात थे। वे वहां मैस में रुके थे। 29 फरवरी की रात आग लग गई थी। उनके साथ डॉग स्क्वॉयड के दो श्वान थे। एक श्वान उनके कमरे में ही था, जिसे उन्होंने सुरक्षित बचा लिया। दूसरे श्वान को बचाने के दौरान वह आग में घिर गए। 90 फीसद जल गए मेजर की मौके पर ही मौत हो गई थी।

पुलवामा हमले की साजिश में शामिल रहे बाप-बेटी गिरफ्तार

सफलता ▶ कई जैश कमांडरों का ठिकाना रहा है इनका घर

हमलावर आदिल डार ने इन्हीं के घर में शूट किया था वीडियो

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सोशल मीडिया से संपर्क में थी इंशा

सूत्रों ने बताया कि इंशा 14 फरवरी 2019 तक आदिल डार और मोहम्मद उमैर उर्फ उमर के साथ उनके टेलीफोन, वाट्सएप व सोशल मीडिया के अन्य एप्स से लगातार संपर्क में थी। एनआइए को उसके और उमर के फोन से अहम सुराग मिले। शाकिर ने भी कई अहम जानकारियां उगली हैं। आइईडी विशेषज्ञ आतंकी कमांडर मोहम्मद उमर फारूक मुठभेड़ में मारे जाने तक उससे संपर्क में था। तारिक ने कथित तौर पर कई बार आतंकियों को टिप्पर के जरिए पुलवामा में उनके ठिकानों पर पहुंचाया है।

पुलवामा हमले की साजिश की कड़ियां जुड़ने लगी हैं। एनआइए जांच में सामने आया है कि आत्मघाती हमलावर आदिल डार ने पुलवामा के एक टिप्पर चालक के घर में वीडियो शूट किया था। इतना ही नहीं यह घर हमले से पूर्व कई जैश कमांडरों का ठिकाना रहा है और उसी घर में कई साजिशें रची गईं। ऐसे में एनआइए ने पुलवामा के हकरीपोरा निवासी टिप्पर चालक तारिक अहमद शाह व उसकी बेटी इंशा तारिक को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पिता आतंकियों को ले जाने में सहयोग करता था और बेटी ठहरने की व्यवस्था के साथ आतंकियों को सुरक्षा बलों से बचाने में मदद करती थी। इतना ही नहीं युवती 14 फरवरी 2019 तक आत्मघाती हमलावर और उसके हैंडलर से संपर्क में थी। बता दें कि पुलवामा हमले में किसी महिला की यह पहली गिरफ्तारी है। साजिश में लिप्त अब तक तीन लोग पकड़े जा चुके हैं।

शाकिर से पूछताछ में मिले सुराग : बाप-बेटी के बारे में सुराग 28 फरवरी को पकड़े गए जैश के ओवरग्राउंड वर्कर शाकिर अहमद मागरे से पूछताछ में मिले। इसके अलावा मारे जा चुके पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद उमैर उर्फ उमर के फोन से भी कुछ सुराग मिले थे।

साजिश के खुलासे में अहम है गिरफ्तारी : श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर 14 फरवरी 2019 को जैश ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। हमले की साजिश में लिप्त सभी प्रमुख आतंकी कमांडर अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए थे। ऐसे में हमले की साजिश के खुलासे में जांच एजेंसी को दिक्कतें आ रही थीं। तारिक और उसकी बेटी की गिरफ्तारी को जांच में बहुत अहम माना जा रहा है। जैश के ओवरग्राउंड वर्कर शाकिर की गिरफ्तारी के बाद एनआइए के लिए यह दूसरी बड़ी कामयाबी है।

कई बार आतंकियों ने घर में ली शरण : अधिकारिक तौर पर संबधित अधिकारियों ने बाप-बेटी की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के संदर्भ में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि तारिक के मकान में ही आत्मघाती हमलावर आदिल डार ने वीडियो शूट किया था। आदिल का यही वीडियो हमले के चंद ही मिनटों बाद जैश-ए-मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर जारी किया था। उन्होंने बताया कि तारिक के घर में वर्ष 2018 से लेकर 14 फरवरी 2019 तक जैश के आतंकियों ने करीब 15 बार शरण ली और हर बार दो से चार दिन तक जमे रहे।

अभी समीर अहमद डार बचा है : तारिक ने पूछताछ में कथित तौर पर माना है कि उसके मकान में आत्मघाती आदिल और दो पाकिस्तानी आतंकियों मोहम्मद उमैर फारूक उर्फ उमर और कामरान के अलावा समीर अहमद डार व मोहम्मद इस्माईल उर्फ इब्राहिम का ठिकाना था। इब्राहिम, आदिल, उमर और कामरान मारे जा चुके हैं। समीर अहमद डार अभी जिंदा है। जम्मू टोल पर 31 जनवरी को सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में मारे गए तीन आतंकियों को ट्रक चालक समीर उसके पास ही पहुंचाने वाला था। ट्रक चालक समीर और जैश कमांडर समीर आपस में रिश्तेदार भी हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू-कश्मीर दौरा हुआ स्थगित

राजनाथ सिंह। (फाइल)

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू-कश्मीर का पांच मार्च को प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। वह गुरुवार को ऊधमपुर स्थित सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय में आने वाले थे। रक्षा मंत्री बनने के बाद यह जम्मू कश्मीर में उनका पहला प्रस्तावित दौरा था, जो आज स्थगित हो गया है। उन्होंने इस दौरे में जम्मू कश्मीर के मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का एक उच्चस्तरीय बैठक में जायजा लेने के अलावा सेना के वरिष्ठ कमांडरों के साथ सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना था। इसके अलावा उन्होंने उत्तरी कमान में स्थित सेना के ध्रुव आडिटोरियम में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करना था।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव नवनीत ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पांच मार्च को नहीं आ रहे हैं। उनका यह कार्यक्रम फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया है। उन्होंने रक्षामंत्री के दौरे के स्थगित होने का कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि संसद सत्र में व्यस्त होने के कारण ही रक्षा मंत्री ने अपना दौरा स्थगित किया है।

छापेमारी से पहले ही पांच बैग भरकर फाइलें पहुंचा दी गई थीं सीएम हाउस

- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्य चौरसिया के वाहन चालक से पूछताछ का वीडियो वायरल
- चालक कह रहा-कार्रवाई से पहले फाइलें ले गए थे, विपक्ष घेराबंदी की तैयारी में

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय आयकर विभाग की छापेमारी से हलचल मची हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्य चौरसिया के यहां छापेमारी से पहले पांच बैग भरकर फाइलें सीएम हाउस पहुंचाने की बात सामने आई है। दरअसल, सोमवार देर रात एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया के वाहन चालक से आयकर अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। इसमें चालक कह रहा है कि सौम्या के घर पर छापेमारी से पहले शुक्रवार को पांच बैग भरकर फाइलों को सीएम हाउस लेकर गया था। इस वीडियो से जहां शासन में खलबली मच गई है वहीं, विपक्ष आक्रामक घेराबंदी की तैयारी में है। वीडियो सार्वजनिक हो जाने के बाद मंगलवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने चालक से फिर घंटों पूछताछ की। इस बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने छापेमारी में अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति मिलने का दावा किया है।

गौरतलब कि छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की टीमों ने 28 फरवरी को छापेमारी शुरू की थी। पूर्व मुख्य सचिव व छत्तीसगढ़ रेरा के चेयरमैन विवेक ढांड, प्रमुख सचिव अनिल टुटेजा, उनकी पत्नी मीनाक्षी टुटेजा, आबकारी विभाग के ओएसडी एपी त्रिपाठी, सौम्या चौरसिया, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, कारोबारी गुरुचरण होरा, आबकारी ठेकेदार संजय दीवान, शराब ठेके पर मैनपावर सप्लाई करने वाले सिद्धार्थ सिंघानिया और विकास अग्रवाल आदि के ठिकानों पर छापेमारी से सियासत गरम है। इस बीच सौम्या चौरसिया के यहां जब टीम जांच करने पहुंची तो उनके नहीं मिलने पर वह वहां कई घंटे डेरा डाल कर रही थी। इसके बाद में उनका आवास सील कर दिया था। आवास सील होने के बाद दूसरे दिन सौम्या सामने आईं और टीम को बुलाकर घर की जांच शुरू कराई थी। इसी दौरान सरकारी गाड़ी चलाने वाले उनके ड्राइवर पन्नालाल से आयकर अधिकारियों ने पूछताछ की। वायरल वीडियो कथित तौर पर इसी पूछताछ का बताया जा रहा है। इससे हड़कंप मच गया है।

सीएम हाउस मार्ग की पड़ताल : सूत्रों को अनुसार मंगलवार को सौम्या के घर जेवरात मिले हैं, जिसकी जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। इस बीच आयकर टीम ने फिर वाहन चालक पन्नालाल को उसके घर से उठाया और घंटों पूछताछ की। अधिकारियों ने पन्नालाल के साथ सौम्या के आवास से सीएम हाउस तक के उस मार्ग को भी देखा जिस से पांच बैग में भरकर फाइलें ले जाने की बात कही जा रही है।

छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन पर मुकदमा

आयकर की छापेमारी के विरोध में कांग्रेस प्रदेश संगठन की अपील पर रविवार को कांग्रेसी सड़क पर उतरे थे। इसी दिन रायगढ़ में विरोध प्रदर्शन और पुलिस ने धक्का-मुक्की का एक वीडियो वायरल हुआ है। विडियो में दिख रहा है कि प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पांडेय के धक्का देने पर आरक्षक विजय ध्रुव जमीन पर गिर पड़े, तभी भीड़ उन पर टूट पड़ी। इसी वीडियो के आधार पर एसपी संतोष कुमार सिंह के केस दर्ज करने का निर्देश दिया। केस दर्ज होने के विरोध में मंगलवार को रायगढ़ में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर मुकदमा वापस लेने की मांग की।

28 प्लॉट की जानकारी खंगाल रही टीम

आयकर विभाग के पास एक शिकायत और कुछ दस्तावेज भी हैं। इसमें सौम्या की मां शांति देवी चौरसिया और सास आशा मणि मोदी के नाम पर कुल 28 प्लॉट का जिक्र है। टीम उस जमीन से जुड़े दस्तावेजों को भौतिक और सॉफ्टवेयर की मदद से खंगाल रही है। इसके अलावा सौम्या के बंगले और मां के फ्लैट को खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई राशि के संबंध में जानकारी मांगी गई है।

डिजिटल लेआउट कराएगा मंदिर निर्माण से पहले परिसर का दर्शन

प्रवीण तिवारी, अयोध्या

- भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी के स्विच ऑन करते ही सार्वजनिक हो जाएगा परिसर का विहंगम दृश्य
- प्रवेश द्वार सहित पूरे परिसर के आवागमन का मार्ग, म्यूजियम व अन्य सभी प्रखंड होंगे प्रदर्शित

राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण से पहले ही श्रद्धालु इस परिसर का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। इसके लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति ने परिसर का लेआउट तैयार कराने का फैसला किया है। इसे डिजिटल मोड में भी तैयार किया जाएगा।

लेआउट ऐसा बनाया जाएगा, जिसमें राम जन्मभूमि स्थल पर बनने वाले मंदिर की दो मंजिला इमारत के साथ अन्य निर्माणों का विवरण होगा। कौन कलाकृति किस स्थान और किस दिशा में होगी, इसका चित्रण व सभी स्थलों तक जाने का रास्ता भी रेखांकित होगा। इसकी मदद से श्रद्धालु वैकल्पिक गर्भगृह में विराजमान रामलला का दर्शन-पूजन करने के अलावा अन्य सभी प्रखंडों का अच्छी तरह से दीदार कर सकेंगे। इसे परिसर के बाहर बड़ी स्क्रीन पर भी चलाने की योजना है। पहले मैन्युअल लेआउट बनाया जाएगा, बाद में इसका डिजिटलाइजेशन होगा। लेआउट 25 मार्च तक पूरा किया जाना है। इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन के लिए आने की संभावना है।

पीएम भूमि पूजन करने के बाद इसी लेआउट को श्रद्धालुओं के लिए समर्पित करेंगे। उनके स्विच ऑन करने के बाद पूरा परिसर वर्णित होने लगेगा। लेआउट बनाने के लिए तीन एजेंसियों के नाम पर विचार चल रहा है।

> परिसर में भव्य राम मंदिर के अलावा भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर वास्तुशिल्प विकसित करने की योजना है। पर अभी परिसर में क्या-क्या होगा, इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राममंदिर निर्माण का कार्य शुरू कराना प्राथमिकता है।
>
> -डॉ. अनिल मिश्र, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य

गत दिनों श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इसकी तैयारी करने को कहा है। उन्होंने आला वास्तुविदों व ट्रस्ट के सदस्यों से इस कार्य को पूरा करने के लिए कहा है। परिसर में राम मंदिर के अतिरिक्त, म्यूजियम, वैदिक पाठशाला, स्टॉफ भवन निर्मित करने का प्रस्ताव है।

खस्ता है कश्मीर की पहचान डल झील का हाल

दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक कश्मीर की डल झील भू-माफिया, बढ़ती आबादी और सरकारी उदासीनता के कारण लगातार सिकुड़ती जा रही है। झील का क्षेत्रफल कभी 22 वर्ग किलोमीटर था जो अब महज 11 किलोमीटर रह गया है। हाउस बोट, होटलों और घरों से निकलने वाली गंदगी का अधिकांश हिस्सा झील में समाने के कारण इसका पानी पीने लायक नही रह गया है। अदालत के हस्तक्षेप के बाद अब झील के भीतरी और बाहरी क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण का पता लगाने के लिए प्रशासन ड्रोन से हवाई सर्वे करने के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है। कामरान राशीद बट

पाक सेना ने एलओसी से लेकर आइबी तक की गोलाबारी, जवान घायल

जेएनएन, राजौरी/हीरानगर

पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा (एलओसी) से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) तक भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के साथ रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रही है। जम्मू संभाग के नौशहरा के झंगड़ सेक्टर में पाक सेना ने सोमवार देर रात भारी गोलाबारी की, जिसमें सेना का जवान घायल हो गया। चॉपर की मदद से जवान को कमान अस्पताल ऊधमपुर रेफर कर दिया गया।

पाक सेना ने सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक पुंछ के मनकोट व बालाकोट सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों में गोलाबारी की। पाक सेना गोलाबारी की आड़ में आतंकियों के दल को घुसपैठ कराने की फिराक में है। वहीं, कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाक रेंजर्स ने दस दिन की शांति के बाद सोमवार रात करीब पौने बारह बजे बीका चक पोस्ट से भारतीय क्षेत्र में मोर्टार व छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जो मंगलवार सुबह पांच बजे तक रुक-रुक कर जारी रही। सीमा सुरक्षाबल के जवानों ने भी पाक गोलाबारी का करारा जवाब दिया। गोलीबारी से भारतीय क्षेत्र में जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को बंकरों में रात गुजारनी पड़ी।

नियंत्रण रेखा पार कर सेना की अग्रिम चौकियों के पास पहुंची आग

संवाद सहयोगी, पुंछ : मेंढर के बाद पुंछ में भी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई आग मंगलवार दोपहर बाद नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के पास पहुंच गई। पुंछ जिला के देगवार सेक्टर में पाकिस्तान के नकरकोट गांव के सिडीया इलाके से नियंत्रण रेखा के नजदीकी इलाकों में आग लगाई गई थी, जो दोपहर बाद पुंछ जिला के देगवार सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी लंगूर पोस्ट के अलावा कई छोटी पोस्टों के नजदीक पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए भारतीय सेना के जवान जुटे हुए हैं। आग के कारण घुसपैठ को रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगों में विस्फोट की आवाज भी सुनाई दे रही है।

इससे पूर्व पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिला के मेंढर के मनकोट में नियंत्रण रेखा पर आग लगाकर बारूदी सुंरगों और निगरानी के लिए लगाए गए उपकरणों को नष्ट करने का प्रयास किया था। इस माह तीसरी बार पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर आग लगाने की घटना को अंजाम दिया है। पहले दो बार लगाई गई आग को भारतीय सेना के जवानों ने बुझा दिया था।

बारूदी सुरंग विस्फोट में जवान घायल

जागरण संवाददाता, राजौरी

नौशहरा के झंगड़ क्षेत्र में सीमा पर बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का जवान घायल हो गया। घायल जवान को सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेना के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान जवान का पांव घुसपैठ को रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंग के ऊपर पड़ गया। तभी धमाके के साथ बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया, जिससे गश्त कर रहा जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को नजदीक के सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सेना की 150 जनरल अस्पताल राजौरी रेफर कर दिया गया।

मोस्ट वांटेड गोगी चार साथियों के साथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मोबाइल का नहीं करते थे इस्तेमाल

पूछताछ में पता चला कि गत चार वर्ष से आरोपित दिल्ली सहित हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में छुपकर रह रहे थे। वहीं, वे अपने गिरोह के साथियों को निर्देश देकर वारदात करवा रहे थे। पुलिस व अन्य को उनकी जानकारी और ठिकाने का पता न चले इसके लिए वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल तक नहीं करते थे। बदमाशों ने फर्जी नाम से अपने कई फेसबुक अकाउंट बना रखे थे। उसमें वे समय-समय पर हथियार के साथ अपना फोटो पोस्ट करते रहते थे। ताकि विरोधी गुट को उनकी ताकत का पता चलता रहे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के मोस्ट वांटेड बदमाश जितेंद्र उर्फ गोगी और उसके चार साथियों को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपित गुरुग्राम सेक्टर-82 के एक अपार्टमेंट में छिपे हुए थे। जितेंद्र के साथ सेल ने कुलदीप मान उर्फ फज्जा, रोहित मोई और कपिल उर्फ गौरव को भी दबोच लिया गया। गोगी हरियाणवी गायिका हर्षिता दहिया व बसपा नेता वीरेंद्र मान की हत्या में वांछित था। इन पर एक दर्जन से ज्यादा हत्या, उगाही व कार लूट आदि के मुकदमे दर्ज हैं। चार वर्ष से दिल्ली और हरियाणा की पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इन सभी बदमाशों पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस की तरफ से 10.30 लाख रुपये का इनाम था। अकेले गोगी पर दिल्ली पुलिस की तरफ से चार लाख और हरियाणा में 2 लाख का इनाम था। गोगी गिरोह जिसे निशाना बनाता था, उसे दर्जनों गोलियां मार मौके पर ही मौत के घाट उतार देता था।

स्पेशल सेल के डीसीपी मनिषी चंद्रा ने बताया कि स्पेशल सेल की टीम आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन महीने से प्रयास कर रही थी। दो मार्च को सूचना मिली कि गोगी साथियों के साथ गुरुग्राम में छिपा हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम दहिया की टीम स्वाट टीम के साथ वहां पहुंची। पुलिस ने बदमाशों को बाहर निकलने के लिए कहा। करीब 20 मिनट तक वे फ्लैट से नहीं निकले। भागने का कोई मौका न मिलने पर उन्होंने उन्होंने दरवाजा खोला। जिसके बाद पुलिस की टीम ने तीन बदमाश जितेंद्र, कुलदीप और रोहित मोई को धर दबोचा। वहीं, उसके साथी कपिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

उधर, घटना से पहले गोगी ने सोशल मीडिया पर अपनी आत्मसमर्पण का वीडियो पोस्ट कर दिया। तलाशी में बदमाशों के पास से छह विदेशी पिस्टल, 70 कारतूस और एक कार बरामद की गई। कार उन्होंने पश्चिम विहार इलाके से चुराई थी। दिल्ली के अलीपुर गांव निवासी गोगी, दिल्ली के नया बास का रहने वाला कुलदीप और हरियाणा के सोनीपत निवासी रोहित कुख्यात बदमाश हैं।

एमएलए हॉस्टल में कैद बिलाल सुल्तान हुए डिप्रेशन का शिकार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सबजेल एमएलए हॉस्टल में एहतियातन हिरासत में रखे अवामी इत्तेहाद पार्टी के वरिष्ठ नेता बिलाल सुल्तान की तबीयत बिगड़ गई। इस कारण सुल्तान को उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। गृह विभाग और पुलिस ने इस विषय में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया है। वर्ष 2019 में श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से डॉ. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बिलाल सुल्तान को पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की घोषणा करने के साथ ही प्रशासन ने एहतियातन अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हिरासत में लिया था। संबंधित सूत्रों ने बताया कि वह अकेलेपन के कारण डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। उन्हें उपचार के लिए रैनावारी स्थित अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने आवश्यक उपचार देने के बाद उन्हें वापस भेज दिया।

सुल्तान की पत्नी मुजम्मिल ने तबीयत खराब होने की पुष्टि करते हुए कहा कि सबेजल एमएलए हॉस्टल में उन्हें खराब हालात में रखा जा रहा है। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई है। प्रशासन को उन्हें जल्द रिहा करना चाहिए, ताकि उनका उपचार करवाया जा सके।

उन्होंने बताया कि पति की रिहाई के लिए वह दो बार अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। अदालत ने पहले अक्टूबर के दौरान उनकी जमानत मंजूर की थी। पुलिस ने रिहा होते ही उन्हें दोबारा हिरासत में लिया था। इसके बाद दिसंबर में दोबारा जमानत मिली, लेकिन पुलिस ने फिर से उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया।

31 मार्च तक पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करवाने पर आयकर विभाग 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है। 31 मार्च के बाद बिना लिंक किए पैन निष्क्रिय हो जाएंगे।

सामूहिक दुष्कर्म-हत्या के मामले में चार दिन सुनवाई कर तीन को फांसी की सजा

फैसला ▶ दुमका में रिश्ते के चाचा ने दो साथियों के साथ भतीजी से दुष्कर्म कर उसकी कर दी थी हत्या

जागरण संवाददाता, दुमका

झारखंड के दुमका जिले के रामगढ़ की छह साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में मंगलवार को स्थानीय जिला अदालत ने बच्ची के चचेरे चाचा समेत तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। देश का यह पहला मामला है, जहां अदालत ने चार दिन में ट्रायल पूरा कर दोषियों को सजा सुनाई। इस दौरान रात में भी अदालत चली। मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कई गंभीर टिप्पणियां कीं और कहा कि दरिंदों के लिए मौत से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन ने बच्ची को लिटिल एंजिल नाम देते हुए कहा कि यह पूरे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है कि आज चाचा के हाथ भी भतीजी सुरक्षित नहीं है। अदालत ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना और आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत अभियुक्तों को ताउम्र जेल में रहने की भी सजा भी सुनाई।

प्रतीकात्मक

'इन्हें जीने का हक नहीं, जिंदा छोड़ा तो गलत संदेश जाएगा'

मंगलवार की सुबह 10 बजे ही सभी अभियुक्तों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया। 12 बजे सभी को कोर्ट में पेश किया गया। उनके सामने ही बचाव पक्ष के वकील राजेंद्र प्रसाद और एपीपी रामकिंकर पांडेय ने बहस की। आधे घंटे की बहस के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया। तीन बजे फिर सभी अभियुक्तों को अदालत लाया गया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर अभियुक्तों को जिंदा छोड़ दिया जाता है तो समाज के गलत संदेश जाएगा। इनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। हत्या, प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौनाचार में तीनों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। इन सभी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक दम नहीं निकल जाए।

यह है मामला : दुमका के रामगढ़ में रहने वाली छह साल की मासूम बच्ची पांच फरवरी को घर से 10 किलोमीटर दूर नाना के घर सरस्वती पूजा का मेला देखने आई थी। गांव में रहने वाला रिश्ते का चाचा उसे बिस्किट दिलाने के बहाने साथ ले गया। चाचा ने मेला में ही मिले दो दोस्तों अशोक राय व पंकज मोहली के साथ शराब पी। इस बीच रात हो गई। घर लौटने के क्रम में एक खेत में ले जाकर बच्ची के साथ तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में ही दफना दिया। सात फरवरी को पुलिस ने शव बरामद कर पिता के बयान पर चाचा के खिलाफ मामला दर्ज किया। 11 फरवरी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुबंई पुलिस के सहयोग से कल्याण से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर गोडडा के पोड़ैयाहाट में रहने वाले बाकी दोनों आरोपितों को भी गिरफ्तार कर 12 फरवरी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। 26 फरवरी को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया तो इस मामले में 27 फरवरी को अदालत ने आरोप गठन कर संज्ञान लिया। इसके बाद लगातार चार दिन तक दिन-रात सुनवाई कर तीन मार्च को मामले पर फैसला सुनाया।

पुरुष के स्पर्श से महिला भांप जाती है उसकी मंशा : हाई कोर्ट

▶ पूर्व अभिनेत्री से छेड़छाड़ मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने की टिप्पणी

मुंबई, प्रेट्र : एक महिला भले ही कम पढ़ी-लिखी हो, लेकिन जब कोई पुरुष उसे स्पर्श करता है या उसकी तरफ देखता है तो उसकी भावना और मंशा को वह बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है। बांबे हाई कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी की सजा को निलंबित करते हुए उक्त टिप्पणी की।

जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण व्यवसायी विकास सचदेवा की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सचदेवा को दिसंबर, 2017 में दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान फ्लाइट में पूर्व अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ के मामले में सजा हुई है। 15 जनवरी, 2020 को सत्र अदालत ने सचदेवा को तीन साल की सजा सुनाई थी। सत्र अदालत ने सचदेवा को उसी दिन जमानत देते हुए सजा को तीन महीने के लिए निलंबित भी कर दिया था, ताकि वो आगे अपील कर सके। सजा के खिलाफ सचदेवा की अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला होने तक सजा को निलंबित रखने का आदेश दिया।सचदेवा के वकील अनिकेत निकाम ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से सजा हुई है और यदि उसका पैर अभिनेत्री से स्पर्श भी कर गया होगा तो निश्चित रूप से ऐसा गलती से हुआ होगा। इस पर जस्टिस चव्हाण ने कहा, सचदेवा प्लेन के बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे थे, जिसमें दो सीटों के बीच अच्छी जगह होती है। ऐसे में उन्होंने अपने आगे की सीट के हत्थे पर अपने पैर क्यों फैलाए थे। जज ने कहा, 'एक महिला भले ही कम जानती हो, लेकिन वह ज्यादा समझती है। यह एक प्राकृतिक उपहार...स्पर्श...नजर...को एक पुरुष नहीं समझेगा, लेकिन एक महिला उसके पीछे के इरादे को समझ जाती है।' पीड़िता ही आरोपित की मंशा के बारे में बता सकती है। आरोपित कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने जानबूझ कर उसे स्पर्श किया। निकाम ने कहा कि पीड़िता ने विमान में किसी से कोई शिकायत नहीं की, विमान से भी वह मुस्कुराते हुए बाहर निकली थी। इस पर अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर महिलाओं को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। यह कोई गणित नहीं है। इसका कोई स्थापित सूत्र नहीं है कि इस तरह की स्थिति आने पर महिला को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। फिल्मों को अलविदा कह चुकी अभिनेत्री ने विमान से उतरने के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपनी आपबीती सुनाई थी। उसके बाद सचदेवा की गिरफ्तारी हुई थी। घटना के वक्त अभिनेत्री की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए सचदेवा को पॉक्सो कानून के तहत भी सजा सुनाई गई है।

परीक्षा से पहले जांच के नाम पर सिख छात्र की पगड़ी उतरवाई

नईदुनिया, धार : मध्य प्रदेश में धार जिले के धामनोद में 12वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान जांच के दौरान सिख छात्र की पगड़ी उतरवाने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना से सिख समाज में रोष है। समाजजनों ने कहा कि जांच करनी थी तो अलग कक्ष में ले जाना चाहिए था। सार्वजनिक रूप से पगड़ी व केश को छेड़ना गलत है।

धामनोद का ही छात्र हरपालसिंह सरस्वती शिशु मंदिर में अध्ययनरत है। वह सोमवार सुबह नौ बजे हिंदी का पेपर देने परीक्षा केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गया था। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व करीब पौने नौ बजे यहां तैनात शिक्षिका और शिक्षक ने शासन के परीक्षा संबंधी नियमों का हवाला देते हुए जांच के लिए उसकी पगड़ी उतरवाई। इससे हरपालसिंह आहत हुआ। परीक्षा के बाद उसने यह बात परिजन को बताई तो उन्होंने इसे समाज के प्रमुख लोगों के समक्ष रखा। समाजजन ने विरोध दर्ज कराते हुए संबंधित अधिकारियों से बात की। उन्होंने देश के प्रति सिख समाज के बलिदान की याद दिलाई और बालक के अपमान की निंदा की। आरोपित शिक्षक एमडी वर्मा और ममता चौरसिया ने सिख समाज के लोगों के सामने माफी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। सामान्य जांच की गई थी।

न्यूज गैलरी

अमृतसर से करतारपुर कॉरिडोर तक फ्री एसी बस सेवा शुरू

अमृतसर: गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन को जाने वाली संगत के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की ओर अमृतसर से डेरा बाबा नानक स्थित कॉरिडोर तक फ्री बस सेवा शुरू की गई है। मंगलवार को इस बस सेवा का शुभारंभ एसजीपीसी के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने किया। यह बस रोजाना सुबह आठ बजे सारागढ़ी सराय के बाहर से संगत को लेकर रवाना होगी और शाम को वापस भी लेकर आएगी। बस पूरी तरह से एसी है। (जासं)

बहू की प्रताड़ना के मामले में फंसे राकांपा एमएलसी

मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद के राकांपा सदस्य विद्या चव्हाण और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुंबई के विले पार्ले थाने में अपनी बहू की प्रताड़ना के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। राकांपा नेता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आइपीसी की धारा 498 ए, 354, 323, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चव्हाण ने बहू पर कई लोगों से अफेयर होने का आरोप लगाया है। राकांपा नेता ने कहा, 'मेरी बहू का कई लोगों से अफेयर है। मेरे बेटे को इन अफेयर्स के बारे में पता चल गया। बाद में उसने बहू को तलाक का मेल भेजा, लेकिन बहू ने तलाक देने से इनकार कर दिया और तीन करोड़ रुपये की मांग की। हमने उसे पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने मुझे बदनाम करने के लिए यह सब किया है।' पुलिस ने इस मामले में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। (एएनआइ)

टूटा विमान की कॉकपिट का शीशा, बाल-बाल बचे 150 यात्री

कोलकाता: कोलकाता में मंगलवार शाम अचानक हुई ओलावृष्टि से उड़ान भर रहे एक विमान की कॉकपिट का शीशा टूट गया। विमान की तुरंत कोलकाता एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई, जिससे राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास समेत 150 यात्रियों की जान बच गई। एयर एशिया का यह विमान मंगलवार शाम कोलकाता से उत्तर बंगाल के बागडोगरा जा रहा था। उड़ान भरने के 10 मिनट के अंदर ही अचानक से शुरू हुई ओलावृष्टि से विमान की कॉकपिट का एक शीशा टूट गया। खतरे को भांपकर पायलट ने तुरंत कोलकाता एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया और विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई। खेल मंत्री ने कहा कि इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है, मानो उनका पुनर्जन्म हुआ है। (राब्यू)

सुप्रीम कोर्ट में चिन्मयानंद की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ मामले को उप्र से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग पर शीर्ष अदालत ने चिन्मयानंद को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत को चुनौती देने वाली पीड़िता के पिता की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने दुष्कर्म का मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार और चिन्मयानंद को नोटिस जारी किया है।

पूर्व मंत्री चिन्मयानंद पर उन्हीं के ट्रस्ट संचालित कॉलेज में कानून की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। चिन्मयानंद को इन आरोपों में गत वर्ष सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। गत तीन फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत दे दी थी। पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर चिन्मयानंद को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक स्थानांतरण याचिका दाखिल कर चिन्मयानंद के खिलाफ लंबित दुष्कर्म का मुकदमा उत्तर प्रदेश की अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है।

जस्टिस अशोक भूषण व जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने मंगलवार को पीड़िता के पिता की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश दिए। कोर्ट ने जमानत रद करने की मांग ठुकराते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत देते हुए अपने आदेश में कारण दर्ज किए हैं और इस कोर्ट को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं लगती। इससे पहले पीड़िता के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने हाई कोर्ट से चिन्मयानंद को मिली जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि आरोपित प्रभावी व्यक्ति है। इस पर पीठ ने कहा कि लेकिन हाई कोर्ट ने इन आशंकाओं पर ध्यान दिया है और इसीलिए जमानत देते समय शर्तें लगाई गई हैं। पीठ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है और उसमें दखल देने की जरूरत नहीं लगती। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इस पर गोंजाल्विस का कहना था कि इसके बावजूद भी खतरा है।

दूसरी तरफ चिन्मयानंद के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने गोंजाल्विस की दलीलों को विरोध करते हुए कहा कि ये आधी बात कोर्ट को बता रहे हैं। यह नहीं बता रहे कि पीड़िता के खिलाफ भी उगाही का मामला दर्ज है। इस पर गोंजाल्विस ने कहा कि पहले पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दूसरी प्राथमिकी बाद में दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि पीड़िता पर एसआइटी ने हमला किया आखिर वह कहां जाए। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने इस बारे में मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई शिकायत दाखिल की। वकील ने कहा कि हमें धमकाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब आपने इस बारे में मजिस्ट्रेट को शिकायत नहीं की तो कोर्ट कैसे जाने कि ऐसा हुआ था।

यह मामला उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर का है। पिछले वर्ष कानून की छात्रा ने वीडियो क्लिप जारी कर चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया और उसके बाद छात्रा लापता हो गई थी। तभी कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर छात्रा को ढूंढकर पेश करने की मांग की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था। इसके बाद छात्रा और उसके दोस्तों के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज हुआ जिसमें उन लोगों पर चिन्मयानंद से पैसे की उगाही करने का आरोप लगाया गया था। हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत देते हुए टिप्पणी की थी कि दोनों पक्षों ने अपनी सीमाएं लांघी हैं। इस समय यह कह पाना मुश्किल है कि किसने किसका शोषण किया। दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया।

भारत छोड़ने के आदेश को पोलैंड के छात्र ने हाई कोर्ट में दी चुनौती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : भारत छोड़ने के आदेश को पोलैंड के छात्र ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय अधीन वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के बांग्ला विभाग में पोलैंड निवासी छात्र को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल उक्त छात्र ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोध आंदोलन में शामिल हुआ था। इसी को लेकर उसे नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। मामले में बुधवार को सुनवाई हो सकती है। इस छात्र पर आरोप है कि दिसंबर में दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उस विरोध कई तस्वीरें उसने सोशल मीडिया पर भारत सरकार के खिलाफ पोस्ट किया था।

उन्हें बीते फरवरी में भारत में विदेशी पंजीकरण पंजीकरण कार्यालय द्वारा बुलाया गया था। उससे तस्वीरें भी जमा ली गई थी। तब उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। मंगलवार को न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य की अदालत में छात्र की ओर से अधिवक्ता जयंत मित्रा ने अपील की तो पीठ ने मामले पर सुनवाई बुधवार को करने की बात कही। इसी तरह विश्वभारती विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बांग्लादेश की एक छात्रा को भी देश छोड़ने को कहा गया है। उक्त छात्रा की ओर से भी हाई कोर्ट में अपील करने की बात वहां के वामपंथी छात्र संगठन की ओर से कही गई है।

खरीद-फरोख्त का आरोप लगाने वाली कांग्रेस बोली- भाजपा विधायक हमारे संपर्क में

नईदुनिया, भोपाल

▶ मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भाजपा पर हमलावर रहे कांग्रेस नेता

विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी तापमान लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी गर्म रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि भाजपा ने कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी के विधायकों को दिल्ली लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बसपा से निलंबित विधायक रामबाई का उल्लेख करते हुए पूछा कि क्या भाजपा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चार्टर फ्लाइट में उन्हें दिल्ली नहीं ले गए? उधर, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय के आरोपों से सहमति जताते हुए भाजपा को सतर्क किया कि उसके अनेक विधायक हमारे भी संपर्क में हैं।

राज्यसभा चुनाव और विधानसभा सत्र के ठीक पहले सूबे की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप-प्रत्यारोप से खलबली मची हुई है। सोमवार को दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाकर इसको हवा दी थी। मंगलवार को भी उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमें रामबाई पर पूरा भरोसा है। वे कमलनाथ जी की प्रशंसक हैं और उनका समर्थन करती रहेंगी। उनके पति गोविंद ने दमोह में मीडिया को बताया कि रामबाई दिल्ली जरूर गई हैं, लेकिन अपनी बीमार बेटी से मिलने। बेटी दिल्ली में पढ़ती है। मामले में कमलनाथ ने कहा कि वे दिग्विजय सिंह के आरोपों से सहमत हैं। अलबत्ता, भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के भी संपर्क में है। कमलनाथ ने चुटकी ली-'हमारे विधायक बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत पैसा दे रही है, मैंने अपने विधायकों से कहा कि उनके पास मुफ्त का बहुत पैसा है, देते हैं तो आराम से ले लेना।'

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह और गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी हॉर्स ट्रेडिंग का इनपुट होने का दावा किया है। उधर, सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाह ने आरोप लगाया कि उन्हें भी भाजपा के नेताओं ने 25 करोड़ रुपये देने और मंत्री बनाने का ऑफर दिया था।

वचन-पत्र को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कहकर हलचल मचाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को सरकार का बचाव करते नजर आए। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं हैं। दिग्विजय द्वारा लगाए गए आरोपों पर सिंधिया ने कहा कि इन तथ्यों की मुझे कोई जानकारी नहीं है। करैरा में सिंधिया ने मंत्रियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के 28 मंत्रियों को मंत्रालय में कम, गांव की चौपाल में ज्यादा बैठना चाहिए। सरकार के स्तर की समस्याएं ऊपर से सुनी जाएं, यदि ऐसा नहीं होता तो हमें ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं।

गुड्डू की वापसी को लेकर बवाल : विधानसभा चुनाव 2018 में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को लेकर बवाल मचा हुआ है। गुड्डू ने कहा है कि जब भी वे कांग्रेस में वापसी करना चाहेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। उधर, मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने कहा है कि प्रेमचंद गुड्डू जैसे तत्वों की पार्टी में वापसी की जरूरत नहीं है।

तोड़फोड़ रोकने को भाजपा सतर्क : विधायक दल में तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए भाजपा ने चाकचौबंद व्यवस्था की है। मंगलवार को भाजपा ने रीवा-शहडोल, सागर और जबलपुर संभाग की तीन अलग-अलग बैठकें बुलाकर सभी विधायकों से बातचीत की। हालांकि, बैठक में उसके दो विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल की गैरमौजूदगी ने पार्टी को चिंता में डाल दिया है। त्रिपाठी और कोल की विश्वसनीयता को लेकर भाजपा को संदेह है। दोनों ही विधायकों ने 2019 में विधानसभा में एक विधेयक पर हुए मतदान में कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। सूत्रों का यह भी दावा है कि एक विधायक को तोड़ने के लिए हनी ट्रैप का सहारा भी लिया जा रहा है। इस बीच, बीना से भाजपा विधायक महेश राय ने दावा किया है कि दो कांग्रेस विधायक अब भी उनके संपर्क में हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कांग्रेस द्वारा भाजपा विधायकों से संपर्क के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इनके पास पांच-छह पार्षद भी नहीं होंगे, विधायकों की बात करते हैं।

फर्जी गन लाइसेंस मामले में गिरफ्तार आइएएस अधिकारी निलंबित

राज्य ब्यूरो, जम्मू : फर्जी गन लाइसेंस बनाने के मामले में सीबीआइ की हिरासत में चल रहे आइएएस कुमार राजीव रंजन को मंगलवार नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। दो दिन पहले रविवार को सीबीआइ की टीम ने रंजन को गिरफ्तार किया था। रंजन मेट्रोपालिटन रेगुलेटरी अथारिटी जम्मू के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। उनके पास जम्मू विकास प्राधिकरण के वाइस चांसलर का अतिरिक्त प्रभार था। मंगलवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम 3(2) के तहत 29 फरवरी से रंजन को निलंबित किया जा रहा है। इसी दिन सीबीआइ चंडीगढ़ की टीम ने रंजन को हिरासत में लिया था। इस मामले में सीबीआइ ने पूर्व केएएस अधिकारी इतरत रफीकी को भी हिरासत में लिया है। दोनों को दस दिनों की रिमांड पर लिया गया है।

मप्र में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, तृणमूल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सहित दस गिरफ्तार

नईदुनिया, भोपाल

▶ एक महिला डॉक्टर ने क्लीनिक को ही बना दिया था देह व्यापार का अड्डा

▶ महिलाओं ने डीजीपी से शिकायत की तो क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप बरखेड़ी इलाके की घनी आबादी के बीच एक क्लीनिक में संचालित सेक्स रैकेट का क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को छापा मारकर भंडाफोड़ कर दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मध्य प्रदेश अध्यक्ष, बिल्डर, पूर्व सरपंच और छात्र समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें क्लीनिक की संचालक डॉक्टर और उसकी तीन महिला साथी भी शामिल हैं। डॉक्टर इस रैकेट की सरगना है। वह दो साल से यह रैकेट चला रही थी, लेकिन पुलिस को भनक नहीं लगी। आसपास की महिलाओं ने जब डीजीपी से शिकायत की तो क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की।

क्राइम ब्रांच की डीएसपी अदिती भावसान के अनुसार, डीजीपी वीके सिंह से की गई शिकायत के बाद सोमवार रात क्लीनिक में एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर भेजा गया। ग्राहकों के अंदर आते ही डॉक्टर दरवाजा बंद कर देती थी। उसकी मर्जी के बाद ग्राहक को बाहर जाने दिया जाता था। सिपाही के अंदर जाने के बाद डॉक्टर दरवाजा बंद करना भूल गई। इसलिए सिपाही अपने साथियों को इशारा कर पाया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर तीन महिलाओं और छह पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। डॉक्टर खुद भी देह व्यापार में लिप्त थी। पकड़े गए अन्य आरोपितों में से एक सचिन सिंह चौहान टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष है। वह बिल्डर भी है। इसके अलावा अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी भावसार का कहना है कि महिला डॉक्टर गुप्त रोग और बवासीर का इलाज करती है। उसके पति की मृत्यु बीस साल पहले हो गई थी। डॉक्टर की तीन बेटियां हैं। उनकी शादी हो चुकी है। महिला के पास बीयूएमएस (यूनानी चिकित्सा) की डिग्री मिली है। इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। महिला का पति भी डॉक्टर था। महिला का कहना है कि दो साल से वह इसमें लिप्त हुई।

> डॉक्टर, उसकी तीन महिला साथी और छह पुरुषों समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों में एक टीएमसी का नेता और एक पूर्व सरपंच भी है। क्राइम ब्रांच ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है।
> -निश्चल झारिया, एएसपी, क्राइम ब्रांच

पेंटिंग की नीलामी रुकवाने को भगोड़े नीरव मोदी का बेटा पहुंचा हाई कोर्ट

मुंबई, प्रेट्र : करीब 14,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपित व भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बेटे ने कीमती पेंटिंग की नीलामी को रुकवाने के लिए बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दावा किया गया है कि दिग्गज कलाकारों की जिन पेंटिंग को ईडी ने जब्त किया था वे रोहिन ट्रस्ट की हैं। नीरव के बेटे रोहिन मोदी ने याचिका में मांग की है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नीलामीकर्ता कंपनी सैफरनआर्ट को छह मार्च को इन पेंटिंग की नीलामी रोकने का निर्देश दिया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस एनआर बोरकर की पीठ इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि जिन पेंटिंग को नीलामी के लिए रखा गया है, उनका लाभार्थी रोहिन है। इन 15 पेंटिंग के अलावा हीरे की कई घड़ियां, कीमती हैंडबैग व लक्जरी कारें आदि भी नीलामी के लिए रखी गई हैं।

महिलाओं के हाथों मालगाड़ी की कमान

▶ रेलवे में महिला दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया अभियान

▶ यह पहला मौका था, जब रतलाम में मालगाड़ी ले जाने से झंडी दिखाने तक पूरा स्टाफ महिलाओं का ही था

मध्य प्रदेश के रतलाम में मालगाड़ी में सवार होने जाती लोको पायलट। नईदुनिया

नईदुनिया, रतलाम

पश्चिम रेलवे में एक मार्च से शुरू हुए 10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कैंपेन (अभियान) के तहत रतलाम रेल मंडल में मंगलवार को रतलाम से गोधरा जाने वाली मालगाड़ी की कमान महिलाओं को सौंपी गई। मालगाड़ी (आरटीएमडीसीसी पावर नंबर 28622) को महिला स्पेशल नाम दिया गया है। लोको पायलट बीना मुरलीधरन, सहायक लोको पायलट पूजा बौरासी और गार्ड दीपिका बैरागी ट्रेन लेकर रवाना हुईं। सुबह 9.10 बजे स्टेशन मास्टर माया यादव ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। यह पहला मौका था, जब रतलाम में मालगाड़ी ले जाने से झंडी दिखाने तक पूरा स्टाफ महिलाओं का ही था। गौरतलब है कि महिला कर्मचारी के साथ एक पुरुष कर्मचारी अनिवार्य रूप से रहता है। रतलाम रेल मंडल में अभी 10 महिला लोको पायलट हैं। रेलवे ने गत वर्ष राजेंद्र नगर स्टेशन पर महिला दिवस के दिन सभी कार्यों के लिए महिला कर्मचारियों को ही तैनात किया था।

हरियाणा बोर्ड परीक्षा : सोनीपत के सिसाणा में 12वीं हिंदी के पर्चे लीक

जागरण संवाददाता, भिवानी

▶ पूरे स्टाफ को हटाया गया, पेपर को रद किया गया

▶ पानीपत में 15 मिनट, अन्य जगहों पर एक घंटे बाद वायरल हुआ पेपर

बोर्ड चेयरमैन का यह तर्क भी जानिए

बोर्ड के चैयरमैन डॉ. जगबीर सिंह का कहना है कि जिस जगह से पेपर लीक हुआ, वहां परीक्षा रद कर दी गई है। अन्य जगहों पर परीक्षा रद करने का औचित्य इसलिए नहीं है, क्योंकि यहां परीक्षा शुरू होने के काफी बाद पेपर वायरल हुआ। हालांकि, तत्काल केंद्र के पूरे स्टाफ को कार्यभार मुक्त कर दिया है। शिक्षा विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।

हरियाणा बोर्ड के नकल रहित परीक्षा के इंतजाम पहले ही दिन दम तोड़ गए। सोनीपत के सिसाणा के राजकीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं के हिंदी के दो कोड (बी व डी) के प्रश्नपत्र 15 मिनट बाद ही नकलचियों के हाथों में पहुंच गए। हालांकि, बाद में शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सिसाणा परीक्षा केंद्र पर तैनात पूरे स्टाफ को कार्यभार मुक्त करते हुए पेपर रद कर दिया। अब इस स्कूल के परीक्षार्थियों को खरखौदा में परीक्षा देनी होगी।

मंगलवार दोपहर साढ़े बारह बजे हिंदी के पेपर की परीक्षा शुरू होते ही दो कोड के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पानीपत के इसराना और मतलौड़ा में केंद्रों के बाहर 15 मिनट बाद ही युवकों ने इसी के जरिये नकल करानी शुरू कर दी। देखते ही देखते अन्य जिलों में भी पेपर वायरल हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल पेपर को दैनिक जागरण ने हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. जगबीर सिंह व सचिव राजीव प्रसाद को वाट्सएप पर दोपहर डेढ़ बजे उपलब्ध करवाए। अधिकारियों ने प्रश्नपत्र असली होने की पुष्टि भी की। जांच शुरू हुई तो पता चला कि सोनीपत के सिसाणा से प्रश्नपत्र लीक हुआ था।

अलग-अलग मोबाइल से खींचे गए थे प्रश्नपत्रों के फोटो: पेपर लीक के बाद हुई जांच में पता चला है कि वायरल हुए प्रश्नपत्र के फोटो अलग-अलग मोबाइल से खींचे गए हैं। एक प्रश्नपत्र रेडमी नोट 5 प्रो से खींचा गया है, जबकि दूसरा अन्य मोबाइल से खींचा गया है।

दैनिक जागरण

शुरुआत किसी भी कार्य का सबसे मुश्किल पड़ाव है

सतर्कता बढ़ाने का समय

देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ना चिंताजनक अवश्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। यदि हवाई अड्डों पर पर्याप्त सतर्कता बरती जाती तो शायद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान समय रहते हो जाती। यह सतर्कता क्यों नहीं बरती जा सकी, इसकी तह में जाने और साथ ही ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है कि कम से कम अब उन सभी की जांच अवश्य हो जो विदेश से भारत आ रहे हैं। चूंकि कोरोना वायरस दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है और मौजूदा माहौल में कोई भी उससे संक्रमित हो सकता है इसलिए कहीं अधिक सावधानी का परिचय देना समय की मांग है। विदेश से आने वालों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे हवाई अड्डों पर जरूरी जांच-पड़ताल में सहयोग करें। इसी के साथ आम लोगों में यह जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है कि जुकाम-खांसी से पीड़ित होने का मतलब कोरोना वायरस की चपेट में आना नहीं है और इस वायरस से संक्रमित लोगों का उपचार संभव है। आखिर यह एक तथ्य है कि केरल में इस वायरस से संक्रमित पाए गए लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। चीन में भी कोरोना वायरस से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ रही है।

हालांकि ईरान, इटली आदि में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा चिंतित करने वाला है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कहीं कम लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त मिले हैं। माना जा रहा है कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे-वैसे इस वायरस का प्रकोप कम होगा। इसके बावजूद चौकसी में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। वैसे भी खतरा अभी टला नहीं है। चूंकि कोरोना वायरस का संक्रमण मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा बनकर उभरा है इसलिए सभी देशों को मिलकर उससे निपटने के प्रयासों को गति देनी चाहिए। कोशिश इसकी भी होनी चाहिए कि इस वायरस को निष्प्रभावी करने वाला टीका जल्द तैयार हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सेहत के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह सही समय है जब राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य तंत्र की समीक्षा के साथ यह सुनिश्चित करें कि कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की निगरानी और उपचार सही तरह से हो। केंद्र सरकार को भी हर हाल में यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी दवाओं और उपकरणों की कमी न होने पाए। उचित होगा कि वह यह देखे कि उसके निर्देशों पर सही तरह अमल हो रहा है या नहीं?

अराजक तत्वों का हौसला

पंजाब में खाकी का खौफ खाने वाले अब खाकी पर ही हावी होने लगे हैं। लोगों की सुरक्षा का दंभ भरने वाली पुलिस पर ही आए दिन हमले हो रहे हैं। लोग थानों में घुसकर हंगामा कर रहे हैं और वहां पर भी पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। सोमवार को बठिंडा जिले के तहत आते गांव गोसपुरा में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर अराजक तत्वों ने हमला बोल दिया। पुलिस वालों को तो पीटा ही, साथ ही उनके वाहन भी तोड़ डाले। यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले लुधियाना के थाना फोकल प्वाइंट के तहत आती ढंडारी चौकी में किन्नरों ने खूब हंगामा किया था। वहां के प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल की पिटाई तक कर दी थी। किन्नर दुष्कर्म के मामले में पकड़े गए एक चालक को छोड़ने की मांग कर रहे थे। अभी दो दिन पहले मोगा में भी ऐसा ही हुआ। दुष्कर्म के मामले में आरोपित एक पुलिस के ही जवान को जब पुलिस की टीम उसके गांव झंडेआना सरकी में पकड़ने गई तो उसके स्वजनों और गांव वालों ने पुलिस वालों को घेर लिया। इन्हें डंडों से जमकर पीटा। पिटाई में बुरी तरह घायल एक एसआइ को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस तरह के हमले राज्य में खाकी की घटती साख के कारण हो रहे हैं। यह कहना भी कतई गलत नहीं होगा कि साख भी पुलिस की अपनी वजह से ही कम हुई है। जब पुलिस वाले नशा तस्करों से लेकर गलत धंधे करने वालों का साथ देंगे और उनके साथ बैठकर हमप्याला बनेंगे तो फिर खाकी का खौफ कहां रह जाएगा। पहले लोग थाने का नाम लेने से भी डरते थे। गांव में पुलिस के आते ही दहशत फैल जाती थी, लेकिन अब हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अराजक तत्व छापामारी करने गई पुलिस को तो निशाना बना ही रहे हैं थानों में भी असुरक्षा का माहौल है। ऐसे हालात देखकर हैरानी होती है कि क्या यह वही पंजाब पुलिस है जिसके नाम से ही आतंक के काले दौर में खतरनाक मुजरिम थर-थर कांपते थे। सरकार और पुलिस के उच्चाधिकारियों को खाकी की ऐसी हालत पर चिंतन-मंथन करना चाहिए और अपनी छवि सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।

ऐसे हालात देखकर हैरानी होती है कि क्या यह वही पंजाब पुलिस है जिसके नाम से ही आतंक के काले दौर में खतरनाक मुजरिम थर-थर कांपते थे

दिल्ली दंगों के सबक

प्रकाश सिंह

भविष्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पुलिस को संबल प्रदान किया जाए और उसके दैनिक कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो

अवधेश राजपूत

राजधानी दिल्ली के दंगे नियंत्रण में तो आ गए, परंतु एक भारी कीमत चुकाने के बाद। 45 से अधिक व्यक्ति इन दंगों की भेंट चढ़ गए और कितने ही लोगों की संपत्ति और कारोबार का नुकसान हुआ। कुछ को पलायन भी करना पड़ा। पुलिस ने अब तक नौ सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और 254 एफआइआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 41 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत है। इतने बड़े पैमाने पर दंगा होना दिल्ली और भारत सरकार दोनों के लिए ही शर्म की बात है। सबसे ज्यादा किरकिरी तो दिल्ली पुलिस की हुई। इन दंगों पर बहुत कुछ कहा-लिखा जा चुका है। मैं तीन खास पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पहला तो यह कि दंगे क्यों हुए? दूसरा, दंगों के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है और तीसरा क्या इसकी तुलना 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से करना उचित होगा?

सांप्रदायिक दंगे भारत के इतिहास से जुड़े हैं। समय-समय पर, अलग-अलग क्षेत्रों में किन्हीं कारणों से चिंगारी जब-तब सुलग ही जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली दंगों के बीज हाल में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान पड़े थे। सभी पार्टियों के नेताओं ने गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए या यूं कहिए कि खुलकर जहर उगला। राजनीति का स्तर और वह भी दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं कितना गिर सकता है, यह जमकर देखने को मिला। चुनाव आयोग से यह आशा की जाती है कि वह ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करे। हालांकि कुछ कार्रवाई अवश्य हुई, परंतु वह दिखावटी थी। उसे प्रभावी नहीं कहा जा सकता।

अपने देश में 'हेट स्पीच' देना फैशन जैसा हो गया है। एक केंद्रीय मंत्री हैं जो आए दिन अनाप-शनाप बोलते रहते हैं, उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं हैं। नेतृत्व से चेतावनी के बाद भी उन पर कोई असर नहीं होता। एक साध्वी हैं जो मूर्खतापूर्ण बयान देने से बाज नहीं आतीं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी बड़बोले नेता भरे पड़े हैं। वे हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते रहते हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर भी अजीब-अजीब बयान सुनने को मिलते हैं। एक मुख्यमंत्री ने जामिया में पुलिस कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग से कर दी थी। एक अन्य मुख्यमंत्री ने अभी हाल में ही कहा कि इस देश में वही लोग रह सकते हैं जो 'भारत माता की जय' बोलें। इन लोगों के मुंह पर पार्टी नेताओं को टेप चिपकाने की जरूरत है। और भी अच्छा होगा यदि इन्हें एक साल के लिए किसी विपश्यना जैसे केंद्र में भेज दिया जाए। इन सभी लोगों के बयानों ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा।

अब रही जिम्मेदारी की बात। पुलिस की जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि पुलिस ने शुरू में हीलाहवाली की, जिसकी वजह से सांप्रदायिक चिंगारी ने दावानल का रूप ले लिया, परंतु बाकी संस्थाओं की जिम्मेदारी का उल्लेख भी आवश्यक है। उपराज्यपाल महोदय, जो गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या भूमिका निभाई? दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो भारी बहुमत से जीतकर आए हैं, उनसे और उनकी पार्टी के नेताओं से उम्मीद थी कि वे लोग सड़क पर उतरकर लोगों को शांत करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। सरकारी खजाने से धनराशि तो कोई भी बांट सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और उनके इस्तीफे की भी मांग हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि अंततोगत्वा जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की ही बनती है, परंतु यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गृह मंत्रालय केवल नीतिगत निर्देश देता है। रोजाना के कामकाज में आशा यही की जाती है कि वह दखल नहीं देगा। यहां यह कहा जा सकता है कि उनके आदेश के अनुपालन में पुलिस निष्क्रिय हो गई थी। हालांकि सोचने की बात यह है कि कोई गृहमंत्री, अपने होशोहवास में और वह भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में हों तब ऐसी कोई घटना क्यों घटित होते देखना चाहेगा जिससे देश को शर्मसार होना पड़े?

यदि पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया जाए तो गंभीर घटनाएं 23 और 24 फरवरी को हुई थीं। उन्हीं दिनों शाहदरा के डीसीपी अमित मिश्रा को दंगाइयों ने पीटा, खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या की गई और हेड कांस्टेबल रतन लाल को गोली मार दी गई। एक दंगाई को पुलिस के एक जवान पर पिस्तौल तानकर धमकाते हुए पूरे देश ने देखा। वह बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया जा सका। इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार था, इस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह यह भी लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने भी दंगे में प्रतिक्रियास्वरूप हिस्सा लिया। सरकारी सूत्रों से बार-बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआइ की भूमिका पर भी सवाल उठाया जा रहा है। यह तो स्पष्ट है कि जिस पैमाने पर दंगे हुए, उनकी तैयारी बड़े सुनियोजित ढंग से हुई थी। इसके लिए कौन व्यक्ति, पार्टी या संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता है। उचित होगा यदि इस प्रकरण में एक न्यायिक जांच बैठाई जाए ताकि सही तथ्य सामने आ सकें, अन्यथा आरोप-प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर चलता रहेगा।

कुछ लोग इन हालिया दंगों की तुलना वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से भी कर रहे हैं। मेरे विचार से यह उनके सीमित ज्ञान का परिचायक है। 1984 में सांप्रदायिक नरसंहार हुआ था, हमले एकतरफा थे। इसके विपरीत 2020 में सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्रहार किया। भविष्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पुलिस को संबल प्रदान किया जाए, उसके दैनंदिन कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। शाहीन बाग से धरना खत्म हो जाना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए महिला पुलिस द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएएए की संवैधानिकता पर तत्काल विचार करे और यदि उसमें किसी तरह का कोई विलंब हो तो इस कानून पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी जाए। इस समय अंतरराष्ट्रीय माहौल भारत के विपरीत होता जा रहा है, उसे संभालने की जरूरत है। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकी एवं कट्टरपंथी संगठन इस माहौल का लाभ उठाकर आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर सकते हैं।

(लेखक उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं)

response@jagran.com

जेएनयू देशद्रोह मामले में सस्ती राजनीति

दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा देशद्रोह के चार साल पुराने मामले में मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दिए जाने के साथ जो विवाद पैदा हुआ उसे स्वाभाविक माना जाना चाहिए। जेएनयू में देशद्रोही नारे के साथ हुई कानूनी कार्रवाई के बाद राजनीतिक दलों ने जैसा हंगामा किया था और छात्रों के समर्थन में जैसी सभाएं हुई थीं उन्हें याद करिए तो मौजूदा विवाद कुछ नहीं है। जब गैर भाजपा दलों के ज्यादातर नेताओं ने नारा लगाने वालों के पक्ष में एकजुटता दिखाई, सरकार को फासीवादी से लेकर और न जाने क्या-क्या कहा तो वे इन पर मुकदमा चलाने की अनुमति का समर्थन कैसे कर सकते हैं? पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली सरकार की समझ भी राजद्रोह कानून को लेकर केंद्र सरकार से कम नहीं है। कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और 120बी के तहत राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का मैं कड़ा विरोध करता हूं। दूसरी पार्टियां कह रहीं हैं कि भाजपा और आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक केजरीवाल सरकार फाइल पर चुपचाप बैठी थी तब तक वह सही थी, लेकिन जैसे ही उसने अनुमति दी वह खलनायक हो गई। क्या मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने वाली फाइल पर कोई निर्णय होना ही नहीं चाहिए था?

चिदंबरम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें देशद्रोह कानून खत्म करने का वायदा किया गया था। अगर आप एक वर्ष में न्यायिक कार्रवाई को देखें तो न्यायालय ने बार-बार पूछा कि अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? जिन लोगों को न्यायालय पर विश्वास है उनको तो मांग करनी चाहिए थी कि दिल्ली सरकार मुकदमा चलाने वाली फाइल का निस्तारण करे। आखिर न्यायालय बिना तथ्यों के किसी को सजा तो दे नहीं सकता। जांच एजेंसियों को राजद्रोह के मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है। दिल्ली सरकार के रवैये को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी 2019 को पटियाला हाउस की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अगली तारीख पर न्यायालय ने दस दिनों में मंजूरी लाने का समय दिया। कायदे से 24 जनवरी को इसकी अनुमति मिल जानी चाहिए थी। 20 जनवरी 2019 को न्यायालय ने दिल्ली के विधि विभाग से बिना अनुमति लिए आरोप पत्र दाखिल करने पर दिल्ली पुलिस से सवाल भी किए। पुलिस ने अदालत से कहा कि वह दस दिनों में विधि विभाग और अन्य संबंधित विभागों से मंजूरी ले लेगी। 6 फरवरी 2019 को न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे फाइल दबाकर बैठ नहीं सकते। इसके बाद यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि किस तरह दिल्ली सरकार ने एक औपचारिकता पूरी करने के नाम पर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित रखा।

14 जनवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल किया उस पर नजर डालना आवश्यक है। जेएनयू परिसर में 9 फरवरी 2016 को जिस तरह के नारे लगे उन्हें देश हजारों बार सुन चुका है। यह कार्यक्रम संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की बरसी पर आयोजित किया गया था। 1200 पृष्ठों के आरोप पत्र में कन्हैया, उमर खालिद अनिर्बान भट्टाचार्य, शेहला रशीद, अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन आदि के नाम शामिल हैं। 36 अन्य के नाम आरोप पत्र के कॉलम संख्या 12 में हैं। इनके खिलाफ सबूतों को अपर्याप्त बताया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के अलावा अन्य कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन धाराओं को लेकर दो मत हो सकते हैं, किंतु पुलिस ने काफी प्रमाण और तथ्य पेश किए हैं। इन आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लेकर आने के लिए कहा गया था। वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई गई और सही साबित होने के बाद आरोप पत्र में शामिल किया गया।

पुलिस के साक्ष्य एवं गवाह कहां तक ठहरते हैं, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। आरोप पत्र में कहा गया है कि 9 फरवरी 2016 की गतिविधि के लिए अनुमति भी नहीं ली गई थी। प्रदर्शनकारियों को रोका गया। तब कन्हैया आगे आए और सुरक्षा अधिकारी के साथ बहस करने लगे और भीड़ में मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कन्हैया ने स्वयं नारे लगाए या नहीं या जिन लोगों ने नारे लगाए उनको समर्थन दिया या नहीं, इसे साबित करना आसान नहीं होगा। फैसला जो भी हो, लेकिन जो नारे लगे उन्हें देश विरोधी मानने में किसी को संकोच नहीं हो सकता। नारों पर ध्यान दीजिए, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम क्या चाहें आजादी, कहकर लेंगे आजादी। कश्मीर मांगे आजादी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी..। इन नारों से पूरे देश का खून खौल गया था। जेएनयू में कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके पोस्टर पर छोटे अक्षरों में लिखा था- लोकतांत्रिक अधिकार..आत्मनिर्णय के समर्थन के लिए, कश्मीरी लोगों के संघर्ष के साथ एकजुटता में। पोस्टर की ये पंक्तियां भी देश विरोधी थीं।

कोई भारत की बर्बादी का, भारत को तोड़ने का नारा लगाए और जिन्हें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी उसे न्यायिक हत्या कहे तो उसे भारत विरोधी नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? अफजल और मकबूल के अरमानों को पूरा करने के संकल्प का अर्थ क्या है? यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा मामला भी राजनीतिक विकृति का शिकार हो गया। इसके दोषियों को चिन्हित कर अब तक सजा मिल जानी चाहिए थी। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की औपचारिकता में इतनी देरी दिल दहलाने वाली है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

अवधेश कुमार

फैसला जो भी हो, लेकिन जो नारे लगे उन्हें देश विरोधी मानने में किसी को संकोच नहीं हो सकता

ऊर्जा

निरंतरता की महत्ता

व्यक्ति जो कार्य करता है उसका प्रभाव समय विशेष तक ही रहता है और कुछ समय के बाद उसका प्रभाव क्षीण पड़ने लगता है। इसलिए जो लोग किसी प्रभाव विशेष को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं उन्हें अपेक्षित कार्य पुनः और बार-बार करना होता है। सामान्य तौर पर कही गई यह बात हमारे दैनंदिन सांसारिक कार्यों के साथ-साथ धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रमों पर भी ठीक इसी रूप मे लागू होती है। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए निरंतर पौष्टिक भोजन और व्यायाम की आवश्यकता होती है। जैसे प्रियजनों से संबंधों को बनाए रखने के लिए उनसे निरंतर संपर्क मे रहना होता है। ठीक उसी प्रकार अपने इष्ट देव की कृपा स्वयं पर बनाए रखने के लिए उनकी अराधना करनी होती है। कोई अपने इष्टदेव के कृपालु स्वभाव का यह मतलब निकाले कि उनकी तो अपनी सुविधानुसार पूजा-अर्चना या ध्यान मात्र से कृपा पाई जा सकती है तो ऐसे महानुभाव को सबसे पहले यह बात स्वयं पर लागू करके देखनी चाहिए कि क्या वह ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न रहेंगे जो अपनी सुविधा से उनसे संबंध रखता है।

इसलिए अपने इष्ट देव का कृपापात्र बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी प्राणी को पूरी निष्ठा से उनकी शरण में जाना होता है। जब सांसारिक जीवन में ही किसी से कुछ पाने की इच्छा के लिए सामने वाले के समक्ष विनम्रता एवं आत्मीयता से पेश आना होता है तो धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में यह सिद्धि इनके बिना कैसे प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोगों की सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में टोकने मात्र से या औपचारिकता भर से भले ही कभी-कभार दाल गल जाए, लेकिन ईश्वरीय विधान में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहां ऐसे लोगों को निराश होना पड़ता है। संबंधों की गहराई और निरंतरता सामाजिक जीवन में जितनी जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में भी उतनी ही आवश्यक है।

डॉ. महेश भारद्वाज

मददगार बनेगी वैज्ञानिक सोच

डॉ. मोनिका शर्मा

भारतीय महिलाओं के जीवन से जुड़ी कई समस्याओं की जड़ें रूढ़िवादी और अवैज्ञानिक सोच में गहराई से समाई हुई हैं

विज्ञान के क्षेत्र में स्त्रियों की बढ़ती भागीदारी सामाजिक-पारिवारिक स्तर बड़ा बदलाव ला सकती है। वैज्ञानिक चेतना और तकनीकी जागरूकता स्त्री जीवन से जुड़ी कई रूढ़ियों से मुक्ति दिला सकती है। इतना ही नहीं इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा लेने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और देश की उपलब्धियां बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। हालिया बरसों में विज्ञान की दुनिया में अहम भूमिकाएं निभाई हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व संभालकर महिला वैज्ञानिकों ने उपलब्धियां हासिल की हैं। यह सकारात्मक और संबल देने वाला पहलू है कि कभी महिलाओं के न के बराबर दखल वाले इस क्षेत्र में अब स्त्रियों का अहम योगदान देखने को मिल रहा है। साथ ही उच्च शिक्षित महिलाओं के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। युवतियां विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों में भी डिग्रियां ले रही हैं। नतीजतन धीमी गति से ही सही पर ऐसे क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। सरकारी आकंड़ों के अनुसार अनुसंधान और विकास गतिविधियों में कार्यरत कुल 2.82 लाख लोगों में से 14 प्रतिशत महिलाएं हैं। समय के साथ इस हिस्सेदारी के आंकड़ों में हो रहा इजाफा भी महिलाओं के जीवन के दूसरे पहलुओं को बेहतर बना रहा है। बावजूद इसके एक कटु सच यह भी है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में महिलाएं आज भी दोयम दर्जे पर हैं। यूनेस्को के साल 2014 से 2016 के बीच के आंकड़ों के मुताबिक उच्च शिक्षा के लिए 30 प्रतिशत छात्राएं ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में प्रवेश लेती हैं। एक शोध यह भी बताता है कि स्कूल में गणित और विज्ञान के विषयों में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहता है, लेकिन आगे की पढ़ाई में इन विषयों के आधार पर भविष्य बनाने के मामले में लड़कियां पीछे रह जाती हैं। ऐसे में पढ़ाई से लेकर कामकाजी बनने तक इन क्षेत्रों में उनकी भागीदारी अभी और बढ़ाए जाने की दरकार है। इसके लिए समानता और सहयोग का परिवेश बनाना होगा।

दरअसल वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच कई समस्याओं का हल सुझाने में सक्षम होती है। कहना गलत नहीं होगा कि हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री जीवन से जुड़े कई मिथक और उलझनें रूढ़िवादी और अतार्किक सोच की वजह से ही फल फूल रही हैं। अंधविश्वासों की बुनियाद पर कई कुरीतियां अपनी जड़ें जमाए हैं। ऐसी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ अवैज्ञानिक सोच और तर्कहीन समझ के बल पर ही पोषण पा रही हैं। यहां तक कि लैंगिक भेदभाव की जड़ भी कहीं न कहीं यह अवैज्ञानिक सोच ही है। कई बार तो स्वयं महिलाएं भी ऐसी बातों की अंध समर्थक बन जाती हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमारे समाज और परिवार में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

संवाद किससे, सहायता किसको?

आसान नहीं अफगानिस्तान की राह शीर्षक से लिखे अपने आलेख में विवेक काटजू ने लिखा है कि अमेरिका-तालिबान समझौते की राह मुश्किलों से भरी है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि इसमें एक पक्ष यानी तालिबान बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। इस बात को समझते हुए ट्रंप ने कह भी दिया है कि यदि तालिबान ने कुछ भी गड़बड़ की तो अमेरिका पुनः लौटेगा। फिर भी लेखक संवाद बनाए रखने की अपील कर रहे हैं! 2001 में जब इन लोगों ने बामियान की बुद्ध प्रतिमा को तोड़ने की घोषणा की थी तो जापान, कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर श्रीलंका, म्यांमार आदि बौद्ध देशों ने प्रस्ताव दिया कि उस मूर्ति के बदले तालिबान जो चाहे ले ले, पर उसे छोड़ दे, किंतु बर्बर उग्रवादियों ने इस प्रस्ताव को बौद्ध देशों की दुर्बलता मानते हुए प्रतिमा का ध्वंस करने से पूर्व 100 गायों का बेरहमी से कत्ल और करने का फरमान सुना दिया। यह हश्र हुआ उस संवाद का। भारत तो अब याद करे 2003 तक के उस मंजर को जब अहमदशाह मसूद के उत्तरी गठबंधन को हमने भारी सैन्य सहायता देकर उसे इस पाशविक ताकत से भिड़ाए रखा था। उन्हीं लोगों में तालिबान का फन कुचलने की कुछ कुव्वत है। अब भारत को और सतर्क रहना होगा।

अजय मित्तल, मेरठ

संसद में कोहराम

पहले दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर सुनियोजित दंगा फसाद, फिर दंगा ग्रस्त इलाकों में नेताओं का दौर, इसके बाद दिल्ली में अफवाहों का दौर और अब बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ही संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा और दोनो सदनों की संसदीय कार्यवाही स्थगित। मतलब पहले दंगों में हजारों करोड़ की आर्थिक हानि समेत मानवता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिससे देश का नाम भी बदनाम हुआ और अब संसद में घायल मानवीय संवेदनाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की बजाय राजनीतिक खिलवाड़ के साथ बेवजह सांसदों द्वारा संसद में ही हाथापाई की नौबत आना कौन से शिष्टाचार की श्रेणी में आता है? सांसदों को इसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बिल, पोस्टर लेकर प्रदर्शन करना, संसद वेल में जाकर बवाल काटना, संसदीय कार्यवाही को रोक कर माननीय सांसद देश दुनिया को कौन सा संदेश देना चाहते हैं?

दीपक गौतम, सोनीपत

मेलबाक्स

डिजिटल अपराध पर लगे लगाम

वर्तमान युग में लेनदेन की सारी चीजें डिजिटल हो गई है ताकि लोगों के लेनदेन को सुरक्षित किया जा सके। लोग भी अपने लेनदेन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेटीएम, यूपीआइ, गूगल पे जैसे कई डिजिटल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने लगे, लेकिन यहां भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। आखिर लोग सुरक्षित तरीके से लेनदेन करें तो कैसे करें? क्या कभी हमने इससे अपनी पुख्ता सुरक्षा की चिंता की? क्या कहीं इस धोखाधड़ी के बढ़ते चलन पर कोई विशेष कदम उठाने की बात सुनी या फिर कोई डिजिटल अपराध को रोकने से संबंधित किसी नियामक के गठन की बात सुनी। इस पर ध्यान देने की दरकार है।

विनीत, आंबेडकर कॉलेज

शांति से हो बात

दिल्ली में जिस प्रकार से दंगे भड़के और अशांति का माहौल बना उसमें सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक रोटियां सेकी। मामला चाहे कोई भी हो राजनैतिक दल राजनीति करने से बाज नहीं आते। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी यही हुआ है। शांति के माध्यम से देश में अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन जिस तरह से दंगा भड़का कर लोगों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है वह कतई ठीक नहीं है। संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर विभिन्न प्रकार की बातें तो कर रहे हैं उनके बीच नोक-झोंक भी हुई लेकिन कोई भी स्पष्ट बात नहीं कर रहा है कि होना क्या चाहिए।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल

जीवाश्म ईंधन से बढ़ता वायु प्रदूषण

विश्वभर में वायु प्रदूषण के सबसे खराब स्तर वाले शहरों की सालाना सूची में भारत के शहर एक बार फिर शीर्ष पर हैं। यह स्थिति तब है जब भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में कानून, नियम और दिशानिर्देश मौजूद हैं। जाहिर है कि असली समस्या इन्हें ईमानदारी से लागू नहीं करा पाने की है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और लोग अपने कर्तव्यों के प्रति समय रहते जागरूक हो जाएं

देवेंद्रराज सुथार
स्वतंत्र टिप्पणीकार

पर्यावरणीय अनुसंधान समूह सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) और ग्रीनपीस साउथ ईस्ट एशिया ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले वायु प्रदूषण से दुनिया को प्रतिदिन करीब आठ अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। यह लागत वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.3 प्रतिशत है। समूह ने रिपोर्ट में तेल, गैस और कोयले से होने वाले वायु प्रदूषण के नुकसान का आकलन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण से चीन में प्रतिवर्ष होने वाले नुकसान की लागत 900 अरब डॉलर, अमेरिका में 600 अरब डॉलर और भारत में 150 अरब डॉलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने बताया है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की चपेट में प्रतिवर्ष दुनियाभर में 45 लाख लोगों की मौत होती है। चीन में जहां 18 लाख तो भारत में 10 लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है।

अधिकतर मौतें हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और तीव्र श्वसन संक्रमण से होती हैं। हाल के अध्ययनों में यह सामने आया था कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में रहने का मतलब 10 सिगरेट के बराबर धुआं ग्रहण करना है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि पीएम 2.5 की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह से प्रतिवर्ष दुनिया में दो ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है। पीएम 2.5 की वजह से पांच साल से कम उम्र वाले 40,000 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। करीब 20 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले होता है। पीएम 2.5 कण फेफड़ों में गहराई से प्रवेश करते हैं और रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं, जिससे हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। डब्ल्यूएचओ ने इन्हें कैंसर के कारक के रूप में पाया है। वायु प्रदूषण का प्रभाव विकसित से लेकर विकासशील देशों में एक जैसा ही है। इसकी वजह से सालाना जहां यूरोपीय यूनियन के देशों में 3,98,000 लोगों की मौत तो अमेरिका में 2,30,000 लोगों की मौत होती है। वहीं बांग्लादेश में 96,000 तो इंडोनेशिया में 44,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।

हालांकि भारत में सरकार द्वारा महिलाओं को लकड़ी इकट्ठा करने और उससे होने वाले धुएं से राहत देने के उद्देश्य से चलाई जा रही उज्ज्वला योजना से कई गांवों में फायदा हुआ है, लेकिन अभी तक यह योजना पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुई है। भारत में आज भी अधिकतर ग्रामीण परिवार चूल्हे पर भोजन पकाने को मजबूर हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पैसनेट इकोनॉमिक्स (आरआइसीई) के एक नए अध्ययन से पता चला है कि पैसे की कमी की वजह से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में 85 फीसद उज्ज्वला लाभार्थी अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन यानी कि मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं। आरआइसीई के सर्वेक्षण के मुताबिक इन राज्यों के 76 फीसद परिवारों के पास अब एलपीजी कनेक्शन है। हालांकि इनमें से 98 फीसद से अधिक घरों में मिट्टी का चूल्हा भी है। केवल 27 फीसद घरों में विशेष रूप से गैस के चूल्हे का उपयोग किया जाता है। वहीं 37 फीसद लोग मिट्टी का चूल्हा और गैस चूल्हा दोनों का उपयोग करते हैं, जबकि 36 फीसद लोग सिर्फ मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाते हैं। उज्ज्वला लाभार्थियों की स्थिति ज्यादा खराब है। सर्वेक्षण में पता चला है कि जिन लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है उसमें से 53 फीसद लोग सिर्फ मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, वहीं 32 फीसद लोग चूल्हा और गैस स्टोव, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों ने खुद अपने घर में एलपीजी कनेक्शन की व्यवस्था की है, उनके मुकाबले उज्ज्वला लाभार्थी काफी गरीब हैं। अगर ऐसे लोग सिलेंडर दोबारा भरवाते हैं तो उनके घर की आय का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। इस वजह से ये परिवार सिलेंडर के खत्म होते ही दोबारा इसे भरवाने में असमर्थ होते हैं।

देश में हर साल घरेलू वायु प्रदूषण से 5,27,700 लोगों की मौत हो जाती है। भारतीय शहरों में घरों में होने वाला प्रदूषण बाहरी प्रदूषण की तुलना में 10 गुना ज्यादा होता है। ईंधन का उपयोग करने वाले 0.2 बिलियन लोगों में से 49 प्रतिशत लकड़ी, 8.9 प्रतिशत गाय के गोबर, 1.5 प्रतिशत कोयला, लिग्नाइट या चारकोल, 2.9 प्रतिशत केरोसिन, 28.6 प्रतिशत द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, 0.4 प्रतिशत बायोगैस तथा 0.5 प्रतिशत अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। लैंगिक असमानता इन सबमें एक मुख्य भूमिका निभाती है। सर्वेक्षणकर्ताओं ने पाया है कि लगभग 70 फीसद परिवार ठोस ईंधन पर कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। दरअसल सब्सिडी दर पर भी सिलेंडर भराने की लागत ठोस ईंधन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत (जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम या खनिज तेल, प्राकृतिक गैस) के अधिक उपयोग होने के कारण पर्यावरण जगत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साफ है आधुनिक वाहनों एवं कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। प्रदूषण के इस विकराल रूप से मानव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जीवाश्म ईंधन से होने वाला वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक तंत्र के लिए भी खतरा है। इससे लाखों लोगों की जान जा रही है, लेकिन यह ऐसी समस्या नहीं है जिससे निजात नहीं पाया जा सकता है। ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन को छोड़कर नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना होगा। अतः आवश्यकता है कि उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी की अधिकाधिक राहत प्रदान कर उन्हें चूल्हे की जगह गैस के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करें। चूल्हे के प्रदूषण से मुक्ति की दिशा में सौर ऊर्जा भी एक बेहतरीन विकल्प है। सौर ऊर्जा के उपयोग को लेकर लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए, ताकि घरेलू प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सके।

मिलकर लड़ने से ही बदलेगी स्थिति

रवि शंकर

विश्वभर में वायु प्रदूषण के सबसे खराब स्तर वाले शहरों की सालाना सूची में भारत के शहर एक बार फिर शीर्ष पर हैं। शीर्ष दस में छह और शीर्ष तीस में कुल 21 शहर भी भारत के ही हैं। दिल्ली से सटा गाजियाबाद दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2019 का यह डाटा आइक्यूएआइआर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। हर साल यह रिपोर्ट तैयार होती है। 2018 की रिपोर्ट में शीर्ष तीस प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल थे। वहीं वायु प्रदूषण में दक्षिण एशिया के 30 में से 27 शहर शामिल हैं। इनमें भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहर भी शामिल हैं। इसके उलट पड़ोसी देश चीन की राजधानी बीजिंग ने साल 2019 में वायु गुणवत्ता में सुधार किया है। बीजिंग दुनिया के 200 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर हो गया है। दरअसल भारत में प्रदूषण के लिए वाहनों का दबाव, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र, निर्माण संबंधी गतिविधियां, औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाया जाना प्रमुख कारण हैं, जिनके विकल्प नहीं तलाशे जा सके हैं।

आंकड़ों के मुताबिक भीतरी और बाहरी वायु प्रदूषण से विश्व में हर साल 70 लाख से ज्यादा लोग वक्त से पहले काल के गाल में समा रहे हैं। वहीं दुनिया के 90 फीसद से भी ज्यादा बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। साफ है, भारत में बड़े शहरों से इतर अब छोटे-छोटे शहरों में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। उसमें घुला जहर लोगों को न सिर्फ धीरे-धीरे बीमार कर रहा है, बल्कि उनकी मौत की वजह भी बन रहा है। हवा जहरीली और प्रदूषित होने का मतलब है वायु में पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में वृद्धि होना। हवा में पीएम 2.5 की मात्रा 60 और पीएम 10 की मात्रा 100 होने पर इसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इससे ज्यादा हो तो वह बेहद ही नुकसानदेह माना जाता है।

सवाल उठता है कि आखिर हमारी सरकार कर क्या रही है? लगता है सरकार का पूरा जोर केवल चुनाव लड़ने से सरकार बनाने तक ही सीमित है। देश में बढ़ते प्रदूषण का मिजाज इसी तरह से बना रहा तो आने वाले दिनों में मानव सभ्यता का ही विनाश हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान भारत का ही होने वाला है। लिहाजा भारत को अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हुए तत्काल ही कुछ सार्थक एवं ठोस उपाय करना होंगे। हालांकि थोड़े-बहुत प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन वे बेअसर साबित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें जनता सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बन रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए अच्छे से अच्छे कदम भी नाकाम हो जा रहे हैं। फिर भी अगर समस्या का स्थायी इलाज ढूंढना हो तो भारत कई दूसरे देशों से सबक ले सकता है। दरअसल कई अन्य देश भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। उन देशों में प्रदूषण से निपटने के कई तरीके अपनाए गए हैं, जिनसे उन्हें कुछ सफलताएं भी हासिल हुई हैं। ऐसे में आर्तकित होने के बजाय प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई तेज करने की जरूरत है।

देखा जाए तो वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसे बिना आपसी सहमति और ईमानदार प्रयास के हल नहीं किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम सभी नागरिकों और संगठनों से लेकर निजी कंपनियों और सरकारों तक को एक साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में कानून, नियम और दिशानिर्देश हैं। समस्या यह है कि ये कहीं भी उतनी सख्ती से नहीं लागू किए गए, जितनी जरूरत थी। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार के साथ-साथ लोग भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, लेकिन अफसोस की बात है कि हम चेत नहीं रहे हैं।

खरी-खरी

समस्याओं के खेत में वार्ताकारों की चिड़ियाएं

जगदीश ज्वलंत

विवश तंत्र ने तय किया कि समस्या वास्तव में गंभीर है। इसका हल सिर्फ वार्ता द्वारा ही संभव है। यह निर्णय लेते हुए न्याय शिरोमणि ने समस्या की घंटी को वार्ताकारों के गले में बांधना ही उचित समझा। घंटी वार्ताकारों के वार्ताकार होने का प्रमाण थी। गेंद अब उनके पाले में थी।

समस्याओं को पहले ही पता था कि वार्ता से उनका हल नहीं होगा। वार्ताकार भी जानते थे कि वार्ताएं कभी हल नहीं चाहतीं। जिसे तीनों स्थापित पालिकाओं ने पाला पोसा, उसका हल भला चौथा मनोनित कैसे कर पाएगा? किंतु दिल बहलाने को गालिब तमाम ख्याल अच्छे ही होते हैं। वार्ताकारों का एक गैंगनुमा समूह हुआ करता है, जो वार्ताओं की संभावनाओं का सूंघकर पता लगा लेता है। वार्ता उनके पाले में आनी ही है। समस्याओं को भ्रम होता है कि उनका हल वार्ताकारों की मुट्ठी में है, जबकि उनकी मुट्ठी में सिर्फ लिफाफे ही होते हैं। हल न निकाल पाने वाली वार्ताएं ही सफल मानी जाती हैं। सफल वार्ताकार समस्या की जड़ों में ही उलझा रहता है। उनमें हल के फल आने ही नहीं देता। वार्ताकार पानी पी-पीकर वार्ता को प्रवाहमयी बनाता है। न उसका पानी मरता है, न वह पानी-पानी होता है।

वार्ताएं ही उन्हें अगली वार्ता के अवसर प्रदान करती हैं। यही अवसर उनके बने रहने का, पहचाने जाने का और रोजगार पाने का कारण भी हैं। और परिणाम भी। सफल वार्ताकार घर से वार्ता के असफल होने की मंगलकामना करके ही चलता है। सभी वार्ताकार आपस में मौसेरे भाई हुआ करते हैं। वे आपस में सदैव विरोधपूर्ण सहयोग, द्वेषपूर्ण सद्भाव बनाए रखते हैं। उनमें सदैव असहमतिपूर्ण सहमति हुआ करती है। हद तो तब हो गई जब एक नव प्रवेशी उत्साही वार्ताकार ने एक ही वार्ता में समस्या का हल निकाल दिया। हल के साथ ही उसे भी निकाल दिया गया। वार्ताकार का बुद्धिमान होना भी एक समस्या ही है। अब वह स्वयं की बुद्धिहीनता के प्रमाण देकर स्वयं को पुनः वार्ताकारों की सूची में जोड़ने हेतु याचना कर रहा है। किंतु अब पछताए होत क्या? समस्याओं के खेत को चुगने के लिए वार्ताकारों की चिड़ियाएं क्या कम हैं?

ट्वीट-ट्वीट

भारत सरकार को चाहिए कि वह अनिवार्य रूप से विदेश से आने वाले प्रत्येक मुसाफिर की थर्मल स्कैनिंग कराए। अभी यह सिर्फ उन देशों से आने वाले यात्रियों का कराया जा रहा है जहां कोरोना का ज्यादा खतरा है। सिंगापुर, थाईलैंड और तुर्की जैसे तमाम देश प्रत्येक विदेशी की थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं।

सुमंत रमन@sumanthraman

यह देखना कितना दुखद एवं त्रासदपूर्ण है कि कुछ बुद्धिजीवी इस आकलन में लगे हैं कि दिल्ली हिंसा में हिंदू अधिक मारे गए या मुसलमान। हिंदू और मुस्लिम में से किस तबके की संपत्ति अधिक स्वाहा हुई? स्पष्ट है कि उनके लिए अपने एजेंडे के आगे मानवीय जीवन का कोई मोल नहीं।

ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, लेकिन क्या तिब्बत और झिनझियांग पर चीन, कैदियों की प्रताड़ना और हत्या के मामले में ईरान या आतंक-जनसंहार को लेकर पाकिस्तान से जवाब तलब किया गया? मानवीय आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को मदद देने वाले कानून का विरोध करने में कोई शर्म बची है कि नहीं? आखिर पाखंड की भी कोई सीमा होती है?

बैजयंत जय पांडा@PandaJay

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दिल्ली हिंसा के लिए कुछ दलों द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना उचित है?

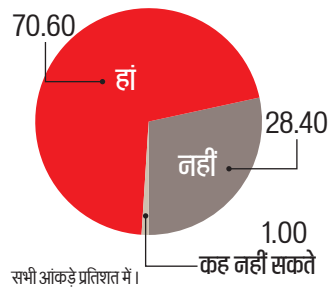

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भारत कोरोना जैसे वायरस से लड़ने में सक्षम है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'सामाजिक' है नाम पर फैलाए विषबेल,
ऐसा 'सोशल मीडिया' बेहतर बेचे तेल।
बेहतर बेचे तेल दूर ही रहना अच्छा,
जिसके कारण आज बिगड़ता बच्चा-बच्चा।
बिगड़ रहे संबंध होय अपनों से झिक झिक,
तो तजना ही ठीक मंच ऐसा सामाजिक!

– ओमप्रकाश तिवारी

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
समाचार संपादक, पानीपत

हरियाणा डायरी

आम आदमी की सेहत और शिक्षा की चिंता

मुख्यमंत्री (सीएम) मनोहर लाल ने दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री (एफएम) के रूप में अपना पहला बजट शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों पर केंद्रित किया है। बीते शुक्रवार सीएम का अर्थ कॉमन मैन (आम आदमी) बताते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा की कार्य संस्कृति में बदलाव के संकेत दिए हैं। नौकरशाहों और सलाहकारों के घेरेबंदी से बाहर निकलते हुए दृढ़ निश्चयी नेता के रूप में कदम बढ़ाया है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एफएम को फेल मैन कहे जाने को किसी ने ज्यादा भाव नहीं दिया। हुड्डा सिर्फ बयानबाजी तक सिमट गए।

आम आदमी की आवाज को बजट में स्थान देने का मुख्यमंत्री का अभिनव एवं दृढ़ प्रयास आनेवाले वर्षों में अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हो सकता है। राज्यव्यापी योजनाओं की कमियों तक पहुंचकर सुधार करने तथा नई योजनाओं को तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बैठकें कर बजट पूर्व सुझाव लिए थे। उन सुझावों को इस बजट का हिस्सा बनाया है। बजट भाषण में मनोहर लाल ने साफ शब्दों में बताया कि अफसरों और सलाहकारों ने विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक करने और उनसे सलाह लेने से रोकने की भरसक कोशिश की। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों से सलाह लेने के उनके सुझाव को भी शुरुआती दौर में नौकरशाही नहीं पचा पा रही थी। इसके बाद भी दृढ़संकल्प के साथ मनोहर लाल ने 150 से अधिक संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। बजट तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण विधायकों से प्राप्त 620 सुझाव रहे। मनोहर लाल ने सदन को बताया कि विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों और लिखित सुझावों में से 70 फीसद को बजट का हिस्सा बनाया गया

है। इसे ही हरियाणा बजट तैयार करने की प्रक्रिया में ताकत के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा के बजट में 28 फीसद वृद्धि सुझावों के परिणाम के रूप में सामने आई। उम्मीद की जानी चाहिए कि अंग्रेजी माध्यम के 1,000 प्राथमिक स्कूल, तीन से पांच वर्ष के बच्चों के लिए 4,000 प्ले वे स्कूल और 24 आदर्श आइटीआइ की परिकल्पना को पंख लगेंगे। इसी तरह आठवीं कक्षा के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था गुणवत्ता सुधार में कारगर साबित होगी।

खिलाड़ी खेल मंत्री के फायदे : खेल राज्य मंत्री के रूप में ओलंपियन संदीप सिंह ने टेंडरों के खेल पर लगाम लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बजट सत्र के दौरान पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ने साफ कर दिया कि खिलाड़ी ही उनकी प्राथमिकता हैं। खेल विभाग के ढांचागत सुविधाओं के विकास के नाम पर ठेकेदारों की जेब भरने की जगह खिलाड़ियों पर खर्च होंगे। यही कारण है कि चार हजार से अधिक खिलाड़ियों का खुराक भत्ता प्रतिदिन 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है। यह आम धारणा बन चुकी है कि नेताओं, नौकरशाहों और ठेकेदारों की साठगांठ से कई बार अनावश्यक निर्माण कार्य कराए जाते हैं। खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं नहीं मिल पातीं। सही तरीके से भोजन तक नहीं मिलता। समय से खेल उपकरणों की खरीद नहीं होती। सदन में विधायकों ने ढांचागत सुविधाओं के लिए फंड उपलब्ध कराने पर ही जोर डाला, परंतु खेल मंत्री ने साफ कर दिया कि उन्हें पता है कि खिलाड़ियों को किन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खुराक पर खर्च किए जाएंगे, ताकि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ी धमाल मचा सकें।

कर्ण की सगाई में नहीं पहुंचे भाई : चौटाला परिवार में बधाई की एक और पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक वारिस अजय चौटाला के पुत्र कर्ण चौटाला की रविवार को सगाई हो गई। राजस्थान के मूल निवासी दिल्ली के बिजनेसमैन जसविंदर संधू की लंदन में पढ़ी बेटी ऐश्वर्या संधू अब चौटाला परिवार की बहू होंगी। आयोजन में आशीर्वाद देने पहुंचने वालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी शामिल रहे, पर लोग अभय चौटाला के बड़े भाई डॉ. अजय चौटाला और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ढूंढते रहे। कोई भी यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं था कि उन्हें आयोजन में बुलाया नहीं गया या वे खुद आए ही नहीं। निगाहें पूछती रहीं, राजनीतिक लड़ाई कहां तक बढ़ गई है कि कर्ण की सगाई में भाई भी नहीं पहुंचे।

सरोगेसी संशोधन बिल

बंद होगा कोख का कारोबार

कृत्रिम रूप से संतान-जनन की सरोगेसी तकनीक उन दंपतियों के लिए आशा की अंतिम किरण साबित हुई है, जिन्हें किसी कारणवश जीवन में संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता

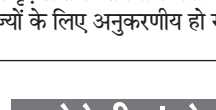

सुधीर कुमार
अध्येता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सरोगेसी बिल से जुड़े उन बदलावों को मंजूरी दे दी, जिसकी सिफारिश राज्यसभा की 23 सदस्यीय प्रवर समिति ने सरोगेसी नियमन विधेयक-2019 के संबंध में की थी। गौरतलब है कि इस विधेयक को लोकसभा ने अगस्त, 2019 में ही पारित कर दिया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति के चलते उक्त विधेयक को राज्यसभा ने सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया था। नए बिल में समिति द्वारा सुझाए गए सभी प्रमुख 15 सिफारिशों को शामिल किया गया है।

मसलन पुराने विधेयक में केवल नजदीकी महिला रिश्तेदारों को ही सेरोगेट मदर बनने की इजाजत दी गई थी। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी को हतोत्साहित करना तथा परोपकारी सरोगेसी को बढ़ावा देना था, लेकिन तब इस प्रावधान को लेकर सवाल उठा कि अगर कोई महिला रिश्तेदार सरोगेट मां बनने के लिए तैयार नहीं होती है तो फिर दंपती के पास क्या उपाय होंगे? इसका समाधान करते हुए नए बिल में अब किसी भी महिला की रजामंदी से उसकी कोख का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। इसके लिए महिला रिश्तेदारों पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

संशोधित सरोगेसी बिल के जरिये केंद्र सरकार ने निःसंतान जोड़ों के अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी सरोगेसी के जरिये मां बनने का अधिकार देने का फैसला किया है। पहले के विधेयक में पति के गुजरने या तलाक के बाद महिलाओं को सरोगेसी का अधिकार नहीं था। केवल निःसंतान दंपती ही सरोगेसी प्रक्रिया को अपना सकते थे, लेकिन अब विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी सरोगेसी के द्वारा मां बन सकती हैं और अपनी सूनी गोद भर सकती हैं। सरोगेसी (नियमन) विधेयक-2020

में शादी के बाद सरोगेसी की इजाजत की सीमा को भी पूर्व निर्धारित पांच साल से हटा लिया गया है। दरअसल पुराने बिल के मुताबिक सरोगेसी के जरिये बच्चे को जन्म देने की इच्छा रखने वाले दंपतियों को शादी के बाद कम से कम पांच साल तक इंतजार करना था। तब इस प्रावधान को लेकर सवाल इस रूप में उठा कि अगर विवाह के एकाध साल में ही किसी दंपती को मालूम पड़ जाए कि उनमें से कोई एक या दोनों बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं और ऐसे दंपती के पास इससे जुड़ा मेडिकल सर्टिफिकेट भी हो तो वह बेवजह पांच वर्ष पूरे होने का इंतजार क्यों करे? बिल में सरकार ने इस हिस्से में सुधार किया है और प्रस्तावित कानून में समय-सीमा के बंधन से इसे मुक्त करते हुए दंपती को किसी भी वक्त सरोगेसी अपनाने का अधिकार दिया है। हालांकि पहले के प्रावधान की तरह ऐसे दंपती के पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा, जिससे यह स्पष्ट हो कि वे प्राकृतिक रूप से माता-पिता नहीं बन सकते हैं।

उक्त महत्वपूर्ण सुधारों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से उम्मीद जगी है कि जल्द ही सरोगेसी नियमन विधेयक-2020 कानून का स्वरूप लेगा, जिसमें सरोगेसी के नियमों को तय करने, व्यावसायिक सरोगेसी को नियंत्रित करने तथा सरोगेट माताओं के शोषण को रोकने के साथ उनके हितों की रक्षा करने संबंधी अनेक प्रावधान किए गए हैं। कानून बनने के बाद भारत जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जहां व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबंधित है। दरअसल कृत्रिम रूप से संतान-जनन की सरोगेसी तकनीक उन दंपतियों के लिए आशा की अंतिम किरण साबित हुई है, जिन्हें किसी कारणवश जीवन में संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। भारत में सरोगेसी का प्रचलन 2002 से है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहली बार कानूनी मान्यता दी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि केवल डेढ़ दशक में ही भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में सरोगेसी का बड़ा केंद्र बन गया। भारत में सरोगेसी तकनीक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत में होने वाली सरोगेसी का लगभग आधा हिस्सा विदेशी दंपतियों का होता है! दरअसल भारत में सरोगेसी तकनीक दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पांच से दस गुना तक सस्ती है और यहां अच्छे डॉक्टरों से लैस विश्व स्तर के आइवीएफ सेंटर भी हैं। वहीं देश में गर्भधारण करने के लिए कमजोर वर्ग की असहाय महिलाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं और यहां इस संबंध में कठोर कानून के न होने की वजह से सरोगेसी के प्रति विदेशियों में गजब का आकर्षण बना हुआ है। विदेशी भारत में सरोगेसी को चिकित्सा पर्यटन के तौर पर देखते रहे हैं, लेकिन अन्य देशों की तरह अब यहां भी विदेशियों के लिए सरोगेसी अपनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनने की तैयारी है। इससे भारत को सरोगेसी का हब बनने से रोका जा सकेगा और सरोगेट माताओं के शोषण पर भी रोक लग सकेगी।

विडंबना है कि अपना कोख बेचकर दूसरों को संतान सुख देने वाली महिलाओं को इसके एवज में उचित पारिश्रमिक भी नहीं दी जाती है। पहले महिलाओं की कोख का संतान जनन के लिए प्राकृतिक इस्तेमाल होता था, लेकिन सरोगेसी तकनीक ने इस प्रक्रिया को भी व्यवसाय का स्वरूप दे दिया था। सरोगेट माताओं के शोषण को रोकने तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस कानून का बनना बेहद जरूरी है।

3 विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संरक्षण संधि के तहत नामित किया है। ये हैं एशियाई हाथी, गोडावण पक्षीऔर बंगाल पेलिकन। भारत के इस प्रस्ताव ने पहली बाधा पार कर ली है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 4 मार्च 2020

उत्तराखंड

अधूरी न रहें चारधाम यात्रा की तैयारियां

चारधाम यात्रा 26 अप्रैल से आरंभ होनी है, यानी मात्र दो माह का समय शेष है। तैयारियों के लिहाज से यह समय पर्याप्त नहीं है। आमतौर पर धामों के कपाट मई में खुलते थे तो प्रशासन को काफी समय मिल जाता था। मई तक बर्फ भी पिघल जाती है। इस बार जिस तरह से मौसम के तेवर हैं, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि चुनौती गंभीर है। उच्च हिमालय में नवंबर से बर्फबारी जारी है। धाम भी बर्फ से लकदक हैं। यहां तक कि केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर कई जगह 20 फीट तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। यही हाल बदरीनाथ का भी है, हनुमानचट्टी के आगे पूरा रास्ता बर्फ से ढका है। यमुनोत्री में बर्फबारी से खासा नुकसान हुआ है। यहां भी स्थिति बदरीनाथ जैसी है। रास्ता बर्फ से पटा होने के कारण धाम तक पहुंचना आसान नहीं है।

धामों में विशेषकर बिजली की लाइनें, पाइप लाइनें और भवनों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा चार धाम यात्रा मार्गों को दुरस्त भी किया जाना है। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह कह चुके हैं कि यात्रा के दौरान सड़क का कटिंग कार्य बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ी चुनौती बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों पर उभरे नए भूस्खलन जोन हैं। चिंता का पहलू यह भी है कि पहले से ही इन मार्गों पर भूस्खलन जोन सक्रिय हैं, लेकिन लंबा अरसा बीतने के बावजूद इस पर काम नहीं किया गया। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ के पास सक्रिय भूस्खलन जोन करीब एक दशक से यात्रियों की परीक्षा ले रहा है, इसके लिए तमाम बार योजनाएं बन चुकी हैं, बावजूद इसके अभी तक स्थिति जहां की तहां है।

चारधाम यात्रा आरंभ होने में दो माह का समय शेष है। मौसम के तेवर तल्ख हैं और धाम बर्फ से पटे हुए। ऐसे में इस बार यात्रा आयोजकों व यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी

यमुनोत्री हाईवे पर बड़कोट के पास डाबरकोट भूस्खलन जोन नासूर बनता जा रहा है। आलम यह है कि पिछले साल भी ज्यादातर समय इस जोन के कारण यमुनोत्री धाम में यात्रा प्रभावित रही। वैज्ञानिक इस जोन का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन अभी इसके ट्रीटमेंट को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। पिछले साल प्रशासन ने यहां पर एक वैकल्पिक मार्ग बनाया, लेकिन यह प्रयास भी बहुत सफल नहीं रहा। केदारनाथ और गंगोत्री हाईवे पर हालात कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन इन सड़कों पर भी कुछ इसी तरह की समस्याएं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शासन प्रशासन के स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बैठकों में यात्रा की तैयारियों पर मंथन चल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए है कि इस बार यात्रा की तैयारियों में इन सभी पहलूओं का ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड में तीर्थाटन व पर्यटन में इजाफा होने से आर्थिकी को संबल मिलेगा तो पलायन को थामने में भी मदद मिलेगी। साथ ही सामरिक लिहाज से भी सहूलियतें बढ़ जाएंगी। यही नहीं लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तो उत्तराखंड के उत्पादों की दूसरे राज्यों के लोगों में मांग भी बढ़ेगी।

हिमाचल प्रदेश

बजट में पर्यटन को प्रोत्साहन की दरकार

तमाम अन्य पर्वतीय राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में भी पर्यटन उद्योग की अहम भूमिका है। इसे राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिर भी इस क्षेत्र की तमाम संभावनाओं को अपेक्षित रूप से भुना पाना अभी शेष है। इन संभावनओं को पूरी तरह से भुनाने के लिए धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ राज्य में शैक्षिक पर्यटन की तरफ भी कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है। हर साल देश-विदेश से लाखों पर्यटक प्रदेश की वादियों में आते हैं, लेकिन जिस गति से यहां पर्यटन उद्योग का विस्तार होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया है। नए पर्यटन स्थल विकसित नहीं हो पाए हैं जबकि विख्यात पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं की कमी हमेशा अखरती रही है।

मैदानी राज्यों में जब प्रदूषण बढ़ जाता है, उन दिनों में भी राज्य में स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन अब प्रदेश की वादियां भी प्रदूषण मुक्त नहीं रही हैं। यहां भी बिगड़ती आबोहवा की तपिश अपना असर दिखाने लगी है। रोहतांग व ऐसे अन्य अनेक क्षेत्र, जहां पर्यटक बर्फ की सफेद चादर देखने पहुंचते थे, वहां पर अब कार्बन के काले धब्बे दिखने लगे हैं। ऐसे दूरदराज के क्षेत्र, जो लोगों से दूर होते थे, वहां भी अब लोगों की चहल-पहल देखी जा रही है। सबसे दुखद पहलू यह है कि पर्यटन स्थलों में पॉलिथीन व प्लास्टिक की बोतलों के ढेर लग रहे हैं। इससे भी बड़ी विडंबना यही है कि जागरूकता बढ़ाने के तमाम अभियान चलाने के बावजूद यह स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। यह सही है कि कुछ समाजसेवी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी हैं। यहां पर पर्यटकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाना बहुत जरूरी है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन सर्पीली सड़कों की हालत संतोषजनक नहीं है। तंग सड़कें व इन पर पड़े गड्ढे पर्यटकों का सफर मुश्किल बनाते हैं जिससे वे अच्छा अनुभव लेकर वापस नहीं लौटते। हवाई व रेल यातायात सीमित होने के कारण पर्यटकों को सड़क माध्यम पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है। एक बार हिचकोले खाते सैलानी यहां आते हैं, लेकिन वे दोबारा यहां पर नहीं आना चाहते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पार्किंग की दिक्कत तो है ही पर्यटकों को स्तरीय सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। धार्मिक पर्यटन की तरफ भी ध्यान दिए जाने जरूरत है। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

राज्य में पर्यटन क्षेत्र के दिन तभी बहुरेंगे, जब यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी

प्रतीकात्मक फोटो

छह मार्च को राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें सरकार को पर्यटन क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के अलावा पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाने होंगे। प्रदेश में कई ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक स्थल हैं, लेकिन समुचित प्रचार न होने के कारण वे पर्यटकों से दूर ही रहे हैं। इसके लिए भी सरकार को इस बजट में ध्यान देना होगा। उम्मीद है कि सरकार बजट में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास करेगी। ऐसा न होने पर हम उन दुर्लभ अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे जो प्रकृति विरले ही किसी को प्रदान करती है।

हरियाणा

तीस हजार शिक्षकों की भर्ती से सुधरेगी स्थिति

प्रदेश सरकार ने बजट में शिक्षा पर पंद्रह फीसद व्यय का प्रस्ताव करने के साथ ही इस दिशा में कार्य भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में करीब 30 हजार पदों पर भर्ती होगी। कुछ पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जिनकी प्रक्रिया अगले तीन महीने में पूरी हो जाएगी और शेष पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम अगले दो महीने में भर लिए जाएंगे। तात्पर्य यह कि अगले पांच महीने में स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में शिक्षकों के लगभग सवा लाख पद हैं, उनमें से लगभग तीस हजार पद खाली हैं। स्पष्ट है कि तीन चौथाई पद रिक्त होने पर शत-प्रतिशत परिणाम हासिल नहीं किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा किसी भी बच्चे के विकास में मुख्य भूमिका में होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो स्कूली शिक्षा के बाद अन्यान्य कारणों से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। इसी लिए स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होता है कि यदि विद्यार्थी उच्च शिक्षा न भी प्राप्त कर सके तो भी एक तरह से उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए और उसे देश-दुनिया का और जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त हो जाए। वैसे भी अब स्कूली शिक्षा के बाद बच्चे रोजगारपरक पढ़ाई की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, इसलिए स्कूली शिक्षा का मजबूत होना आवश्यक है। वह ही बच्चे के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। उसके बाद तो पढ़ाई लक्ष्य केंद्रित हो जाती है। प्रदेश सरकार को स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के साथ ही उच्चशिक्षा और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भी काम शुरू कर देना चाहिए।

हरियाणा सरकार स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रही है, वे नितांत आवश्यक हैं

प्रतीकात्मक फोटो

इसके लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यह देखा जाना चाहिए कि सृजित पद कितने हैं? रिक्त पद कितने हैं? रिक्त पदों पर तो भर्ती की ही जानी चाहिए, साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि यदि आवश्यकता सृजित पदों से अधिक की है तो और पद सृजित कर भर्ती की जानी चाहिए। फिलहाल तो स्कूलों में सरकार जो तीस हजार शिक्षकों की भर्ती कर रही है, उसके लिए तो वह साधुवाद की पात्र है ही। इसमें कोई दोराय नहीं कि शिक्षकों की कमी से पठन-पाठन कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। एक शिक्षक पर अनुपात से अधिक बच्चों को पढ़ाने का बोझ होने से वह उन्हें पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाता है। इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उम्मीद है शिक्षकों की भर्ती से प्रदेश में यह स्थिति अब सुधरेगी।

उत्तर प्रदेश

पुलिस बल को मिली और ताकत

उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सोमवार का दिन बेहद खास रहा और युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 49568 पदों पर सिपाही भर्ती का परिणाम घोषित किया, जो अब तक की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही जल्द उनका प्रशिक्षण शुरू कराए जाने का निर्देश दिया है। योगी सरकार में अब तक पुलिस में 137253 पदों पर भर्ती हो चुकी है।

जाहिर है राज्य पुलिस बल को करीब 50 हजार नए सिपाही मिलने से कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण अभियान को ताकत मिलना तय है। ये नियुक्तियां जिस पारदर्शी और पवित्र प्रक्रिया के आधार पर की गई हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की जानी चाहिए। इससे पहले कुछ दशकों में शायद ही कोई भर्ती हुई होगी जिसमें भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप न लगे हों। उम्मीद की जानी चाहिए कि 50 हजार सिपाही जुड़ने से यूपी पुलिस की छवि में ताजगी और पेशेवर स्मार्टनेस बढ़ेगी। इन सिपाहियों को पुलिस बल में तैनाती से पहले उनकी सेवा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लंबी सेवा शुरू करने से पहले यह प्रशिक्षण अवधि इन सिपाहियों के लिए अहम होगी। इस दौरान उन्हें न सिर्फ शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जो उन्हें सेवाकाल के दौरान ईमानदारी, नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रेरित करता रहे।

उम्मीद की जानी चाहिए कि 50 हजार सिपाही जुड़ने से यूपी पुलिस की छवि में ताजगी और पेशेवर स्मार्टनेस बढ़ेगी। साथ ही कानून व्यवस्था को ताकत मिलेगी

पुलिस सेवा को अन्य सेवाओं की तरह नहीं आंका जा सकता। पुलिस अधिकारियों को विधि व्यवस्था के तहत बाकी सेवाओं से भिन्न वर्दी, बैज और अस्त्र उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि यह बल किसी भी परिस्थिति का न सिर्फ मुकाबला कर सके, बल्कि आमजन को सुरक्षा का अहसास भी कराए। इससे शायद ही कोई असहमत हो कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रदेश पुलिस की छवि अलोकप्रिय, दागदार और गैर-पेशेवर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे बदलने के लिए प्रयासरत दिखते हैं यद्यपि यह आसान नहीं है। इसके लिए उच्चाधिकारियों को अपने मातहतों के समक्ष श्रेष्ठ, पारदर्शी, ईमानदार और पेशेवर कार्यशैली के उदाहरण पेश करने होंगे। शासन स्तर पर ईमानदार पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात किए जाने और उनकी ईमानदारी को सम्मानित किए जाने की पहल की जा सकती है।

पिछले तीन साल में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों के मन में खौफ पैदा किया है जिसका प्रभाव कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में दिखता है। संख्याबल बढ़ने से पुलिस की ताकत बढ़ेगी यद्यपि बेहतरीन उपलब्धियों के लिए पुलिसबल को आवश्यक सुविधाओं से भी लैस किया जाना चाहिए। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द ही पुलिस को ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।

बच्चों की जान लेने वाली खांसी-जुकाम की दवा का सैंपल फेल, मामला दर्ज

कार्रवाई ▶ हिमाचल में बनी दवा पीने से जम्मू में हुई थी 12 बच्चों की मौत, 36 की हुई थी किडनी खराब

दवा कंपनी को सील कर सस्पेंड किया लाइसेंस, जल्द होंगी गिरफ्तारियां

राजन पुंडीर, नाहन

हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब स्थित डिजिटल विजन दवा कंपनी में बनी खांसी और जुकाम की दवा के सैंपल फेल हो गए हैं। कोल्ड बेस्ट सीरप दवा में डाई एथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला पदार्थ पाया गया है। सोमवार को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के स्टेट ड्रग कंट्रोलर की सैंपल की रिपोर्ट आई है। इसके आधार पर हिमाचल स्टेट ड्रग कंट्रोलर की टीम ने सोमवार देर रात ही कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ कालाअंब पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। दवा कंपनी को सील करने का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और हिमाचल स्टेट ड्रग कंट्रोलर की टीम ने 15 से 18 फरवरी तक डिजिटल विजन कंपनी से सैंपल भरे थे। इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। साथ ही कंपनी का सारा रिकॉर्ड भी जब्त किया था। जांच टीम ने पाया था कि कच्चा माल चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से अंबाला और अंबाला से कालाअंब में डीलरों द्वारा पहुंचाया गया था। इसके बाद कालाअंब में दवा का उत्पादन किया गया। इस बैच की 5500 बोतलों का उत्पादन सितंबर 2019 में किया गया। इसकी सप्लाई 10 राज्यों में की गई।

क्या है मामला: दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में जम्मू व उधमपुर में खांसी जुकाम की दवा का सेवन करने से 12 बच्चों की मौत हो गई थी। जबकि करीब 36 बच्चों की किडनी खराब होने के मामले सामने आए। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने हिमाचल को इस उद्योग पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। कालाअंब में 15 फरवरी को उद्योग पर ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की। 17 फरवरी को सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया व स्टेट ड्रग कंट्रोलर की टीम ने कंपनी में बन रही सभी दवाओं के सैंपल भरे। पांच सैंपल केंद्र की चंडीगढ़ स्थित आरडीटीएल प्रयोगशाला को भेजे थे, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

- हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में सैंपल की रिपोर्ट फेल आने के बाद उद्योग प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर कंपनी को सील कर दिया गया है। -डॉ. नरेश कुमार लट्ठ, निदेशक, हिमाचल प्रदेश हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेटी विभाग
- दवा उद्योग का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। जो सैंपल हमारी टीम ने भरे थे। अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। 17 फरवरी से ही उद्योग में उत्पादन बंद है। -नवनीत मरवाह, राज्य दवा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश
- उद्योग प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। -अजय कृष्ण शर्मा, पुलिस अधीक्षक, जिला सिरमौर

सेहत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे : जयराम

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में बताया कि इसमें मिलावट पाई गई है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से कंपनी का लाइसेंस रद कर दिया है। कंपनी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि किसी भी दवा कंपनी को लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो मार्च को चंडीगढ़ की ओर से हरियाणा व जम्मू-कश्मीर में कोल्ड बेस्ड पीसी के लिए गए सैंपलों में मिलावट सामने आई है। प्रदेश में भी जो सैंपल लिए गए थे, उनमें 34 प्रतिशत ज्यादा मिलावट पाई गई है। इस प्रकार की लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अमरनाथ यात्रा में बाधा नहीं बन पाएगा मौसम

नवीन नवाज, श्रीनगर

22 जून से शुरू हो रही श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान मौसम भले ही बिगड़ जाए, लेकिन वह यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाधा नहीं बन पाएगा। मौसम विभाग ने इस बार यात्रा के दौरान मौसम का पूर्वानुमान लगाने के अलावा उसके असर पर आधारित स्टीक भविष्यवाणी करने के लिए अत्याधुनिक एक्स बैंड डाप्लर रडार लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दोनों यात्रा मार्गों (पहलगाम व बालटाल) पर भी अत्याधुनिक मोबाइल मौसम पूर्वानुमान उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बालटाल और पहलगाम में मौसम विभाग के दो विशेषज्ञ भी तैनात रहेंगे।

समुद्रतल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा इस बार 43 दिन की होगी। यात्रा के दौरान अक्सर मौसम खराब रहने से बारिश होती है। हाईवे पर भूस्खलन के कारण कई बार श्रद्धालुओं की जान पर भी बन आती है और रास्ता बंद करना पड़ता है। इसी तरह पहलगाम से पवित्र गुफा और बालटाल से गुफा के रास्ते पर भी बादल फटने, अचानक बारिश, हिमपात और हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं। मौसम खराब होने पर तीर्थयात्रा को कई बार तीन से चार दिनों तक रोकना पड़ता है, जिससे कई तरह की प्रशासनिक दिक्कतें भी पैदा होती हैं।

बनिहाल और सोनमर्ग में स्थापित किया जाएगा डाप्लर रडार

सोनम लोटस ने बताया कि हम इस साल एक्सबैंड डाप्लर रडार प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। इसे पीरपंचाल के दाएं तरफ बनिहाल में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य डाप्लर रडार सोनमर्ग के ऊपरी हिस्से में स्थापित कर रहे हैं। बनिहाल में स्थापित किए जाने वाले रडार 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर हाईवे और उसके साथ सटे इलाकों में मौसम का अनुमान लगाने में सहायक होगा। पीरपंचाल पर्वत श्रृंखला और जवाहर सुरंग के दोनों तरफ होने वाली मौसमी गतिविधियों का यह स्टीक अनुमान व उसके प्रभाव का पता लगाने में मदद करेगा।

मंडलायुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान की अध्यक्षता में गत दिनों श्रीनगर में तीर्थयात्रा के प्रबंधों को लेकर हुई बैठक में मौसम का मुद्दा उठा। इस बैठक में मौसम विभाग को बालटाल से पवित्र गुफा और पहलगाम से पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों पर चार से पांच ऑटोमेटिक वेदर फोरकास्टिग स्टेशन स्थापित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग के दो अधिकारी बालटाल और पहलगाम में यात्रावधि के दौरान लगातार मौजूद रहकर मौसम की निगरानी करेंगे और नियमित तौर पर मौसम की गतिविधियों का अनुमान लगाते हुए यात्रा प्रबंधकों व श्रद्धालुओं को सूचित करेंगे।

बाढ़, बादल फटने, हिमस्खलन और बारिश की तीव्रता की देंगे जानकारी : श्रीनगर स्थित मौसम विभाग केंद्र के निदेशक सोनम लोटस ने बताया हमारा प्रयास है कि इस बार मौसम के चलते श्रद्धालुओं को होने वाली दुश्वारियों को यथासंभव न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। मौसम पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन मौसम के मूड का पता लगाकर हम कई दिक्कतों से बच सकते हैं। इसलिए हम न सिर्फ मौसम का पूर्वानुमान बल्कि बाढ़, बादल फटने, हिमस्खलन की आशंका, ठंड कितनी होगी या मौसम जल्द साफ होगा आदि की जानकारी देंगे। यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि बारिश होगी तो उसकी तीव्रता कितनी होगी।

प्रशासन व श्रद्धालुओं के लिए जारी किए जाएंगे अलर्ट : यात्रा प्रबंधों की तैयारियों में शामिल राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर मौसम का पूर्वानुमान लगाने में समर्थ अत्याधुनिक मोबाइल मौसम पूर्वानुमान उपकरण भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इन उपकरणों की सहायता से संबंधित क्षेत्र में मौसम की गतिविधियों के अनुमान पर प्रशासन व श्रद्धालुओं के लिए लगातार अलर्ट जारी किए जाएंगे।

उल्लास

किशोरीजू ने लड्डुअन की बरसात कराई, आज लठामार होली

जागरण संवाददाता, मथुरा

श्रीजी के आंगन में हुई लड्डू होली, झूमे श्रद्धालु, बुधवार को नंदगांव के हुरियारों पर लाठियां बरसाएंगी बरसाना की हुरियारिनें

वसंत पंचमी से ही होली की मस्ती में डूबे ब्रज में मंगलवार को उल्लास चरम पर पहुंच गया। राधारानी मंदिर में लड्डू होली खेली गई। देश-दुनिया से आए श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप लुटाए गए इन लड्डुओं को लपकने की होड़ मची रही। राधाकृष्ण के प्रेम भरे गीतों और होली के रसिया गीतों पर श्रद्धालु झूमते रहे। अबीर-गुलाल से पूरा मंदिर बहुरंगी हो गया। बुधवार को विश्व प्रसिद्ध लठामार होली खेली जाएगी।

ब्रज की होली पूरी दुनिया में निराली है। होली की खुशी में मंगलवार को सूरज की किरणों ने भी मानो ब्रज की धरा को रंग-बिरंगा कर दिया था। पूरा बरसाना उल्लास में था। परंपरा के तहत, शाम को जब राधा की सखी स्वरूप राधादासी ने लौटकर होली खेलने का आमंत्रण स्वीकार होने की जानकारी दी, नंदभवन में हुए स्वागत सत्कार से गदगद राधादासी भी खुशियों से सराबोर थी। लाडली मंदिर में खुशियां छा गईं। राधादासी को लड्डू खिलाया गया मगर खुशी में राधादासी ने लड्डू लुटाने शुरू कर दिए और इसके साथ ही लड्डू होली शुरू हो गई। राधा ने भी लड्डुअन की बरसात की। श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप लुटाए जा रहे इन लड्डुओं को लपकने की होड़ मच गई। इसके साथ ही द्वापरकालीन लीला भी जीवंत हो उठी। मंदिर में गोस्वामी समाज ने पद गायन किया। 'आज बिरज में होरी रे रसिया' के गीत पर सखियां ढोल-नगाड़े की थाप पर नृत्य कर रही थीं।

मथुरा स्थित बरसाना के लाड़िली जी मंदिर में लड्डू होली के दौरान लड्डू लूटने की कोशिश में श्रद्धालु। जागरण

बंगाल में परीक्षार्थियों को कम अंक देने का कारण बताना होगा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षकों के लिए नया नियम जारी किया। माध्यमिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों को किसी सवाल पर पूरा नंबर नहीं देने का कारण स्पष्ट करना होगा। उत्तर पुस्तिका में लिखे उत्तर के आगे परीक्षकों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि क्यों उन्होंने नंबर कम दिए हैं। यदि किसी प्रश्न का पूर्णांक 3 है और निरीक्षक ने परीक्षार्थी को 2 नंबर दिए हैं तो इसका कारण क्या है यह बात उक्त अंक के सामने लिखना होगा। बोर्ड की ओर से यह निर्देश माध्यमिक परीक्षा की कॉपी जांचने वाले परीक्षकों को भेज दिया गया है।

इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय का कहना है कि कॉपी की जांच में किसी तरह का कोई गड़बड़ी न हो इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। क्योंकि उत्तरपुस्तिका की जांच में परीक्षकों द्वारा गलती किए जाने का हर वर्ष सैकड़ों शिकायतें आती है। विशेष रूप से किसी सवाल का सही जवाब देने पर भी नंबर क्यों कम दिए गए यह शिकायत सबसे अधिक होती है। कई बार जब कॉपी की दोबारा जांच की जाती है तो मूल्यांकन में परीक्षकों की लापरवाही सामने आती है और हर साल ऐसे शिकायतकर्ता परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही नहीं, गड़बड़ी दुरुस्त होने पर मेरिट लिस्ट में भी बदलाव करना पड़ता है। कई बार उत्तर पुस्तिका में नंबर जोड़ भी गलत हो जाता है। जिसे लेकर परीक्षार्थी के परिजन अदालत तक चले जाते हैं। इस बार बोर्ड उस गलती को दोहराना नहीं चाहता है। इसलिए मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों के लिए यह नया नियम बनाया गया है।

नया नियम

- माध्यमिक बोर्ड ने उत्तरपुस्तिका जांचने वाले परीक्षकों को भेजा निर्देश
- बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा-कॉपी की जांच में न हो गड़बड़ी, इसलिए लिया गया फैसला

8.9 करोड़ भारतीय महिलाएं बेरोजगार हैं, जबकि कार्यशील महिलाओं की तादाद 43.2 करोड़ है। गूगल की मदद से तैयार और 18 फरवरी को जारी कंसल्टिंग फर्म बैन एंड कंपनी का यह अनुमान है।

देश में इस बार होली पर जमकर उड़ेगा स्प्रे वाला प्राकृतिक गुलाल

फाल्गुन हलचल ▶ हाथरस में पहली बार तैयार किया गया स्प्रे गुलाल, फिल्म से आया आइडिया, स्प्रेयर कैन में भरा गया है प्राकृतिक रंगों से तैयार सूखा गुलाल

जागरण विशेष

हिमांशु गुप्ता, हाथरस

हाथरस के रंगों की मांग देश ही नहीं विदेश में भी खूब है। होली हो या जश्न, गली-मुहल्ले से लेकर बॉलीवुड और सत्ता के गलियारों तक, गालों पर हाथरस का रंग और गुलाल ही खिलता है। अमेरिका, यूरोप और चीन सहित अन्य एशियाई देशों में तक हाथरस से रंगों की सप्लाई होती है। इस बार यहां नया प्रयोग हुआ है, जो होली में धूम मचाएगा।

रंग उद्योग से जुड़े हाथरस के कारोबारियों की मानें तो यह जीनियस आइडिया था, जो देश में होली के अंदाज को बदल देगा। देश में अबकी होली पर हाथरस का स्प्रे वाला नेचुरल गुलाल जमकर उड़ेगा, जिसकी सप्लाई देश के कोने-कोने तक और विदेश तक जमकर हुई है। डिमांड इतनी रही कि जनवरी के अंत हाथरस में इसका स्टॉक खत्म हो गया था। स्प्रे गुलाल पहली बार तैयार किया गया है। प्राकृतिक रंगों से तैयार सुगंधित महीन गुलाल को स्प्रेयर कैन में भरा गया है, जो बटन दबते ही दूर तक उड़ता है और माहौल को सुवासित सुर्ख रंगों से सराबोर कर देता है।

स्प्रे की बात करें तो बाजार में अब तक रंगों वाला स्नो स्प्रे ही खूब दिखता था। लेकिन इसमें रसायन युक्त रंगों को पानी में मिलाकर भरा जाता है। इसमें गुलाल नहीं बल्कि रंग होता है। वहीं, गालों पर लगाने और एक-दूसरे पर उड़ाने के लिए सूखा गुलाल ही इस्तेमाल होता है। अब यही सूखा गुलाल स्प्रेयर कैन में उपलब्ध होगा।

कारोबारियों से बात करने पर पता चला कि अलग-अलग प्रदेशों की अनेक रंग कंपनियां गुलाल स्प्रेयर बनाने की कोशिश में थीं, लेकिन कामयाबी की चाबी नहीं मिली थी। हाथरस की जानी-मानी तोता

प्राकृतिक गुलाल स्प्रे की छोटी कैन दिखाते हुए व्यवसायी। जागरण

हाथरस का प्राकृतिक गुलाल इस तरह होता है स्प्रे। जागरण

रंग कंपनी ने यह कर दिखाया। कंपनी के संचालक राम बिहारी अग्रवाल ने स्प्रे गुलाल बनाने पर काम शुरू किया, जो सफल हुआ। बीते साल इसके तैयार होने और मार्केटिंग होते ही डिमांड देश ही नहीं विदेश में भी जमकर रही। थंडर नाम के गुलाल स्प्रे की रिटेल कीमत 200 रुपये है। राम बिहारी अग्रवाल कहते हैं कि वह पहले गुलाल स्प्रे को लेकर काम कर चुके थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अगस्त 2018 में फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा जीनियस फिल्म की शूटिंग के लिए वृंदावन पहुंचे। होली के गाने को फिल्माया जाना था। इसके बोल थे- सा रा रा... होली बिरज मा..., तुझसे है रंगोली बिरज मा....। इसके लिए डायरेक्टर की डिमांड के अनुसार सिलेंडर में गुलाल भरकर उड़ाना था। अनिल शर्मा ने इसके लिए राम बिहारी से संपर्क किया। यहीं से राम बिहार अग्रवाल को स्प्रे गुलाल का व्यावसायिक आइडिया मिला। अंततः उन्होंने कई कोशिशों के बाद गुलाल स्प्रे तैयार कर लिया।

स्प्रे में बेहद बारीक और खुशबूदार गुलाल भरा गया है। यह पूरी तरह प्राकृतिक उत्पादों से ही बनाया गया है। जैसे हरा रंग पालक से, हल्का हरा रंग मेहंदी से, लाल रंग शलजम से, ऑरेंज रंग संतरे से बनाया गया है। इन रंगों को सफेद रंग के स्टार्च में मिलाया गया है। स्टार्च और रंगों की मात्रा किस तरह रहे, इसके लिए भी प्रयोगशाला में कई माह प्रयोग किए गए। रंगों को अलग-अलग अनुपात में मिलाकर ही गुलाबी, केसरिया और दूसरे रंग तैयार हो सके।

दुनिया भर में मांग... : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में रंग का उत्पादन करने वाली करीब 10 बड़ी और 15 छोटी यूनिट संचालित हैं। 15 से अधिक फर्में केवल ट्रेडिंग करती हैं। इसका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये के आसपास है। 20-25 हजार टन की सप्लाई की जाती है। करीब छह हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है।

> हाथरस के रंगों की मांग दुनियाभर में रहती है। अक्टूबर से रंगों का उत्पादन शुरू होता है और जनवरी अंत तक मांग के अनुसार आपूर्ति कर दी जाती है। गुलाल वाला स्प्रे कई प्रयोगों के बाद पहली बार हाथरस में बनाया गया है। इसकी सप्लाई देश-विदेश में की गई है। होली में जमकर इस्तेमाल होता दिखेगा।
> **- राम बिहारी अग्रवाल, रंग कारोबारी, हाथरस।**
>
> इस बार रंग का कारोबार अच्छा रहा है। मौसम ने भी साथ दिया है। केमिकल रंग की जगह प्राकृतिक रंगों से तैयार गुलाल की मांग काफी बढ़ी है।
> **- देवेंद्र गोयल, रंग कारोबारी हाथरस**

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

दिव्यांगों के लिए वरदान साबित होगा 'सस्ता' एक्सोस्केलेटन सूट

विकास शर्मा, चंडीगढ़

एक्सोस्केलेटन सूट यानी शरीर के ढांचे को सपोर्ट करने वाला कंकालनुमा बाह्य मशीनी आवरण। चलने-फिरने उठने-बैठने में लाचार किसी दिव्यांग को यह मशीनी सूट पहना दिया जाए तो निर्देशों के अनुरूप यह उसे चलने-फिरने उठने-बैठने में पूरा सपोर्ट करता है। चंडीगढ़ के नवउद्यमी ने सरकारी सहयोग से स्वदेशी एक्सोस्केलेटन सूट विकसित किया है, जो बाजार में उपलब्ध 60 लाख से तीन करोड़ तक की कीमत वाले विकल्पों के मुकाबले 26 लाख रुपये में मिलेगा। इससे आस जगी है कि भविष्य में ऐसे उपकरण दिव्यांगों को सुलभ हो सकेंगे।

नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान एक दिव्यांग दोस्त की प्लेसमेंट न होने से पूरा बैच परेशान था। दोस्त की परेशानी देखकर जोन आइ कुजुर ने एक्सोस्केलेटन सूट बनाने की ठानी। भारत सरकार ने स्टार्टअप स्कीम के तहत सहयोग दिया तो जोन को मंजिल और करीब दिखने लगी। जोन ने बताया, मार्केट में पहले से उपलब्ध एक्सोस्केलेटन सूट का पता किया तो इनकी न्यूनतम कीमत 60 लाख रुपये और अधिकतम कीमत तीन करोड़ रुपये है। हमने स्टार्टअप के माध्यम से इस दिशा में काम शुरू कर दिया ताकि दिव्यांगों को इस तरह के उच्च तकनीकी उपकरण आसानी से मुहैया हो सकें। अब हमने 26 लाख की लागत से इस सूट को बनाया है। हम इसकी लागत और कम करने पर काम कर रहे हैं। इस सूट को बनाने में जोन कुजुर के साथी रहे विवेक पांडे ने बताया कि रोबोटिक्स पर आधारित यह सूट मोबाइल एप के माध्यम से काम करता है। इसकी मदद से इसको पहनने वाला व्यक्ति बिना व्हीलचेयर के चल-फिर उठ-बैठ सकता है। सीढ़ियां चढ़ सकता है। हम इस सूट को अपडेट कर रहे हैं ताकि यही नहीं, आप जैसा बोलेंगे यह यह सूट वैसे ही काम करेगा।

इस सूट को पहनकर पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर (पीआरसी) के दिव्यांग पूर्व सैनिक अजीत कुमार शुक्ला और अरुण पाल स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित होने वाली सायबथलोन में हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता दो से तीन मई को आयोजित होगी। अजीत और अरुण पूर्व सैनिक हैं और दोनों आतंकी हमले के बाद व्हीलचेयर पर हैं। व्हीलचेयर रहते हुए इन दोनों पैरा एथलीट ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई टूर्नामेंट जीते हैं। दोनों पैरा एथलीट ने कहा कि वह चाहते हैं कि इस सूट की कीमत और कम की जाए ताकि दिव्यांगजन इसे आसानी से खरीद सकें।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

एक्सोस्केलेटन सूट का प्रारूप। सौ. कंस्ट्रक्टिबल

स्वस्थ समाज

जगी आस...

- चंडीगढ़ के नवउद्यमी ने सरकारी सहयोग से विकसित किया अपेक्षाकृत सस्ता एक्सोस्केलेटन सूट
- बाजार में उपलब्ध 60 लाख से तीन करोड़ तक की कीमत वाले विकल्पों के मुकाबले कीमत 26 लाख
- प्रयोग ने जगाई उम्मीद, उच्च तकनीकीयुक्त ऐसे सहायक उपकरण आने वाले दिनों में दिव्यांगों को हो सकेंगे सुलभ

दुनिया देखेगी भारतीय टेक्नोलॉजी का कमाल...

जोन आइ कुजुर ने बताया कि हम इस सूट का ट्रायल सायबथलोन जैसे बड़े इवेंट में कर रहे हैं, जिसमें 98 देशों के लोग हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट में जब भारतीय टेक्नोलॉजी का कमाल दुनिया देख लेगी, तो उसके बाद हम इसे बाजार में उतार देंगे।

आरएसएस के स्कूलों में बढ़े सात फीसद मुस्लिम विद्यार्थी

मध्य प्रदेश को लेकर विद्या भारती की रिपोर्ट में किया गया दावा

सौरभ खंडेलवाल, भोपाल

2900 सरस्वती शिशु मंदिर हैं मध्य प्रदेश में

100 मुस्लिम शिक्षक भी पढ़ाते हैं इन स्कूलों में

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश में दो समुदायों को बांटने की राजनीति के बीच यह खबर सुखद अहसास कराने वाली है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को कई नेता कट्टरवादी संगठन करार देते हैं, उसके द्वारा संचालित स्कूलों में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती ने आंकड़े जारी कर दावा किया है कि पिछले दो सालों में मध्य प्रदेश में संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या करीब सात फीसद बढ़ी है।

रोज गाते हैं वंदे मातरम् : इन स्कूलों के ये मुस्लिम विद्यार्थी न सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि रोज वंदे मातरम् भी गाते हैं। सभी समुदाय के बच्चों के साथ भोजन से पहले प्रार्थना भी करते हैं। विद्या भारती के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में मप्र के सरस्वती शिशु मंदिर में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या 9168 थी, जो 2019-20 में बढ़कर 9804 हो गई है। हालांकि, 2018-19 में संख्या में मामूली गिरावट के साथ 9152 हो गई थी। इन स्कूलों में पढ़ रहे कई मुस्लिम विद्यार्थियों ने खेलकूद प्रतियोगिता व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में पुरस्कार भी जीते हैं।

ग्वालियर जिले के भितरवार में रिहान खान ने पिछले दिनों वंदे मातरम् गायन प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया था। विद्या भारती के पदाधिकारियों के मुताबिक सरस्वती शिशु मंदिर में

> सरस्वती शिशु मंदिरों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती। यहां विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए काम किया जाता है, इसलिए अन्य धर्मों के लोग भी अपने बच्चों को यहां पढ़ाते हैं।
> **- हितानंद शर्मा, मध्यभारत प्रांत संगठन मंत्री, विद्या भारती**

ईसाई समुदाय के विद्यार्थी और शिक्षक भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है।

मालवा-मध्यभारत प्रांत में घटी संख्या : आरएसएस ने कार्य विभाजन के लिए मध्य प्रदेश को तीन प्रांत में बांटा है। इसमें मालवा, मध्य भारत प्रांत और महाकौशल शामिल हैं। दो सालों में मालवा और मध्यभारत प्रांत में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या घटी है, लेकिन महाकौशल प्रांत में इनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।

अभिभावकों का सीएए पर रुख साफ : राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आठवीं कक्षा में पढ़ रही अशफिया मिर्जा के पिता रियाज बेग मिर्जा का सीएए पर रुख साफ है। कानून को लेकर मिर्जा का कहना है कि सरकारें सोच-समझकर कानून बनाती हैं। एक प्रतिशत लोग यदि इसे खराब कह रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि कानून खराब हो गया। दतिया जिले के भांडेर में रहने वाले जमा मंसूरी कहते हैं कि सीएए हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए लाया गया है, इसलिए इसका समर्थन करना चाहिए। जहां तक मुस्लिम होने के बावजूद सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चा के दाखिला कराने का सवाल है तो हमने यहां अच्छी पढ़ाई की वजह से यह निर्णय लिया है।

अब म्यांमार तक होगी प्राच्य विद्या की शाखाएं

जागरण संवाददाता, वाराणसी

संस्कृत विश्वविद्यालय

- **मिला आवेदन, विश्वविद्यालय नियमानुसार संबद्धता देने को तैयार, म्यांमार से एनओसी मिलते ही जांच के लिए गठित होगा पैनल**

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्राच्य विद्या की शाखाएं देश के कोने-कोने में है। अब इसकी नींव विदेशी भूमि पर भी रखने तैयारी है। मौका भी मिल गया है। म्यांमार के आशुतोष संस्कृत पालि महाविद्यालय की ओर से संबद्धता के लिए आवेदन किया गया है। विश्वविद्यालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। म्यांमार की संस्था ने अपनी सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) को अर्जी भी दे दी है। एनओसी मिलते ही संस्कृत विश्वविद्यालय पैनल गठित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराएगी। ताकि संबद्धता/ मान्यता प्रदान की जा सके।

जम्मू-कश्मीर समेत 12 राज्यों में संस्थाएं : विश्वविद्यालय की शाखाएं सूबे के अलावा बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर तक हैं। विश्वविद्यालय मध्यमा (जूनियर हाईस्कूल) लगायत आचार्य (स्नातकोत्तर) तक की, वर्ष 2002 में माध्यमिक संस्कृत बोर्ड के गठन के बाद शास्त्री-आचार्य की ही परीक्षा संचालित कर रहा है।

विदेश के 55 छात्र पंजीकृत : संस्कृत विश्वविद्यालय में वर्तमान में म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, स्पेन सहित विभिन्न देशों के करीब 55 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

229 साल पुराना वट वृक्ष : संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1791 में बनारस संस्कृत पाठशाला के रूप में हुई। बाद में नाम बदलकर राजकीय संस्कृत पाठशाला व क्वींस कालेज कर दिया गया। 1956 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। नाम रखा गया वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय। वर्ष 1974 में एक बार पुनः नाम संशोधित कर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय से करीब 600 विद्यालय व महाविद्यालय संबद्ध है।

प्राच्य विद्या में कई विषय : प्राच्य विद्या से आशय परंपरागत ज्ञान से है। इसमें वेद, वेदांत, मीमांसा, ज्योतिष, कर्मकांड, पुराणेतिहास समेत अन्य संस्कृत के विषय शामिल हैं।

> म्यांमार के छात्रों में संस्कृत के प्रति गहरी रुचि है। वर्तमान में म्यांमार के करीब 40 विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। इसमें सर्वाधिक बौद्ध दर्शन व पालि में छात्र शामिल है। म्यांमार के तीन छात्र पालि से शोध भी कर रहे हैं।
> **- प्रो. हरप्रसाद दीक्षित, विभागाध्यक्ष पालि विभाग**
>
> विश्वविद्यालय एक्ट के तहत संस्था को दुनिया के किसी भी देश में संबद्धता/ मान्यता देने का अधिकार है। काफी पहले विश्वविद्यालय की शाखाएं नेपाल तक थीं। नेपाल में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद वहां संस्कृत विद्यालय नेपाल से ही संबद्ध हो गए।
> **- प्रो. राजाराम शुक्ल, कुलपति**

कमरा न मिलने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए पंजाब के 25 विधायक

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

- पंजाब भवन में विधायक को नहीं मिला कमरा, तो सत्ता-विपक्ष आए एक मंच पर
- बोले- विधायक का ओहदा मुख्य सचिव के बराबर, पर अफसर मानते हैं सबसे नीचे

जनहित के मुद्दों पर भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव हो, लेकिन अपनी सुविधाओं के लिए दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। पंजाब विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक ऐसे ही एक मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी भरपूर साथ मिला। स्थिति ऐसी बन गई कि सत्ता पक्ष के विधायक खड़े होकर स्पीकर की कुर्सी की तरफ चलने लगे। मामला कांग्रेस के विधायक निर्मल सिंह शुतराना को दिल्ली के पंजाब भवन में कमरा नहीं मिलने का था।

इस मुद्दे पर कांग्रेस और आप एक ही मंच पर आ गई। कांग्रेस के विधायक फतेह जंग बाजवा ने यह मुद्दा उठाया था। कांग्रेस के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। इसी मुद्दे को आप की सरबजीत कौर माणुके ने भी उठाया, जबकि निर्मल सिंह शुतराना में इसे विशेषाधिकार हनन का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वह दिल्ली गए थे। वहां जाकर उन्हें कमरा नहीं मिला। जब उन्होंने अधिकारियों को फोन किया, तो किसी ने फोन नहीं उठाया। चंडीगढ़ में एक अधिकारी ने 17 बार फोन करने के बाद फोन उठाया और कहा कि मीटिंग रद हो गई है। आप वहां क्या कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मुझे कमरा नहीं मिला, इसलिए मुझे रात को ही वापस आना पड़ा। निर्मल सिंह के साथ कांग्रेस और आप के विधायक खड़े हो गए। हाउस का पारा चढ़ते देख स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा को सदन को आश्वासन देने के लिए कहा, लेकिन विधायक मोहिंदरा की बात सुनने तो तैयार नहीं थे।

बता दें कि 2007 में पंजाब सरकार ने एक पत्र जारी किया था, जिसके तहत पंजाब भवन में अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि विधायक को इस लिस्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद व सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया था। परमिंदर पिंकी ने यह पत्र पहले ही स्पीकर को भेज दिया था।

स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी को किया तलब, होगी कार्रवाई : हाउस में गर्मागर्मी को देखते हुए स्पीकर राणा केपी सिंह ने कहा कि उनके पास सरकार का एक पत्र आया है, जो 2007 का है। इसमें विधायक से ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी है। इस पत्र में विधायक को सबसे नीचे रखा गया है। एक विधायक का रुतबा चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। पत्र बिल्कुल ठीक है। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधायकों को मान-सम्मान दिया जाएगा। स्पीकर ने कहा कि वह चीफ सेक्रेटरी को बुलाएंगे। उस चिट्ठी को रद करवा कर विधायको को उनका सम्मान दिलवाएंगे। स्पीकर के आश्वासन के बाद विधायक शांत हुए। इसके बाद ब्रह्म मोहिंदरा ने कहा कि वह छह बार विधायक रह चुके हैं। पिछले पांच बार के विधायक काल में वह यह परेशानी झेलते रहे हैं, जबकि इससे पहले विधायकों ने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठा। स्पीकर ने भरोसा दिया कि दोषियों के विरुद्ध अवश्य कार्रवाई होगी।

प्रधानमंत्री से प्रेरित किसान बदल रहा कइयों की जिंदगी

भारत भूषण को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित करते केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी। जागरण

- डोडा के दूरदराज गांव में लैवेंडर की खेती के लिए भारत भूषण को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड
- दो कनाल से शुरू कर अब 62 एकड़ भूमि पर करते हैं खेती
- 60 अन्य लोगों को भी रोजगार दिया, 100 किसान साथ जुड़े

राज्य ब्यूरो, जम्मू

'मैं गरीबी रेखा से नीचे रहता था और सिर्फ दो कनाल भूमि पर सब्जियां और मक्की की खेती करता था। इससे पूरे साल में महज 15 हजार रुपये ही कमा पाता था, लेकिन चार साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंस में बात करने के बाद मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। उनके प्रेरित शब्दों की बदौलत आज मैं 62 एकड़ भूमि में एरोमैटिक (लैवेंडर) प्लांट की खेती करता हूं। इसके बाद मेरी आय साल में तीन लाख तक पहुंच गई। ऐसा कर मैंने केवल खुद के लिए ही रोजगार के साधन नहीं जुटाए बल्कि आज 60 अन्य लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। मेरे साथ करीब 100 किसान जुड़े हुए हैं और हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।'

यह कहानी है जम्मू संभाग के डोडा जिले के दूरदराज के गांव लहरोट-खेल्लानी के 42 वर्षीय किसान भारत भूषण की। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भूषण को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड के लिए चुना है। यह पहली बार है कि जब डोडा जिले के किसी किसान को अवार्ड मिल रहा है।

भूषण ने कहा पहली बार साल 2010 में उसने लैवेंडर की खेती करने की सोची, लेकिन सभी ने उसका मजाक उड़ाया। विरोध घर से ही शुरू हो गया, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की और खेती करने का जोखिम उठाया। किस्मत ने मेरा साथ दिया और फसल अच्छी हुई। इससे उसकी आय बढ़ी, लेकिन शुरू में यह खेती करना आसान नहीं था। लैवेंडर का बीज बहुत महंगा था। इसी बीच, वर्ष 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंस में बात की तो सब कुछ बदलने लगा। असल में वह मेरी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट था। उसी दिन केंद्र सरकार ने एरोमा मिशन भी शुरू कर दिया। आज हमें सैंपलिंग बिल्कुल मुफ्त मिलती है। उसने इन पौधों की खेती के लिए लीज पर अतिरिक्त भूमि ली। अब लाभ हर खेती में तीन लाख रुपयों तक पहुंच गया है। मैंने इससे कई लोगों को सीधा रोजगार भी दिया है।

किसानों को भूषण के खेतों में दी जा रही है फील्ड ट्रेनिंग : भूषण के खेत कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक नई जगह बन गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र डोडा और कृषि विभाग ने इन खेतों को फील्ड ट्रेनिंग के लिए चुना है। यहां किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र डोडा के प्रभारी नरेंद्र पाल ने भूषण को इस सम्मान के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह पहली बार है कि डोडा जिले से किसी किसान को यह विख्यात सम्मान मिल रहा है। यह सम्मान किसान को पहचान ही नहीं दे रहा है बल्कि कृषि विज्ञान केंद्र के किसानों को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी बल देता है।

क्या होती है लैवेंडर की खेती : लैवेंडर हल्के बैंगनी रंग के फूल होते हैं। इनकी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और फूल फरवरी महीने में खिलना शुरू हो जाते हैं। इनके फूलों से सुगंधित तेल बनाया जाता है, जो दवाइयां बनाने सहित कई चीजों में काम आता है। यह खाद्य पदार्थों में सुगंध के लिए भी इस्तेमाल होता है।

जायदाद का मामला

भोपाल के पूर्व नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान के पुत्र हैं शहरयार, मप्र हाई कोर्ट में याचिका दायर, शर्मिला टैगोर के वकील ने जताई आपत्ति

पाक के पूर्व विदेश सचिव ने मांगा नाना की संपत्ति में हक

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत के नवाब रहे हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान के पुत्र शहरयार खान ने नाना की संपत्ति पर अपना हक जताया है। शहरयार पाकिस्तान के विदेश सचिव भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में संपत्ति पर हक के लिए गत दिनों एक याचिका दायर की गई है। इसमें नवाब परिवार से जुड़े 14 वारिसों ने अपना हक मांगा है।

आबिदा सुल्तान नवाब की बड़ी बेटी थीं, लेकिन वे 1950 से 52 के बीच पाकिस्तान चली गईं। 68 साल बाद अब आबिदा के पुत्र शहरयार ने भी नवाब की संपत्ति पर अपना हक जताने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, नवाब परिवार की सदस्य और फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की तरफ से पैरवी कर रहे वकील राजेश पंचोली ने उनके इस दावे पर आपत्ति जताई है। दरअसल, 31 जुलाई 2019 को नवाब की संपत्तियों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था कि नवाब की संपत्तियों का बंटवारा मुस्लिम विधि (शरीयत) के हिसाब से होगा। इसे आधार बनाकर

शहरयार खान (फाइल फोटो)

शहरयार ने जबलपुर हाई कोर्ट में संपत्तियों पर अधिकार जताया है।

1960 में हुई थी नवाब की मौत : नवाब हमीदुल्ला खान की मौत 1960 में हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गईं थीं। कायदे से नवाब की मौत के बाद सबसे बड़ी संतान के नाते आबिदा को उत्तराधिकारी बनाना था और सारी संपत्ति उन्हें सौंपना थी, लेकिन वह भारत छोड़ चुकी थीं, इसलिए 1962 में मंझली बेटी साजिदा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।

अंतिम बहस के बाद फैसला : मामले में 10 फरवरी को सुनवाई के बाद यह मामला अंतिम सुनवाई के लिए लग गया है। सभी तरह की आपत्ति और आवेदनों को सुनने के लिए एक अंतिम बहस होगी। इसके बाद इस मामले में फैसला हो जाएगा।

शत्रु संपत्ति की जद में आ जाएगी शहरयार की संपत्ति : गौरतलब है कि 1968 में केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम लाई थी। इस कानून के 47 साल बाद कस्टोडियन ऑफ एनीमी प्रॉपर्टी ऑफिस ने भोपाल नवाब की कुछ संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया था। शत्रु संपत्ति कार्यालय मुंबई ने युद्ध के समय पाकिस्तान जाने वाली नवाब की बेटी आबिदा सुल्तान को वारिस मानते हुए उनकी चार दर्जन से अधिक प्रॉपर्टी की लिस्ट भेजी थी। इसमें पाक जाकर बसीं आबिदा सुल्तान को बेगम ऑफ भोपाल मानते हुए इस प्रॉपर्टी की जांच के निर्देश दिए थे। इसमें 70 साल के खसरों की जांच कर जो रिपोर्ट तैयार गई है, उसमें मात्र 24 संपत्तियां सामने आई हैं। भोपाल शहर और इसके आसपास करीब 15,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन नवाब के निधन के बाद साजिदा सुल्तान के नाम कर दी गई थीं।

> भोपाल नवाब की मौत 1960 में हुई थी, इसके पहले ही आबिदा सुल्तान पाकिस्तान जा चुकी थीं। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ने साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ऐसे में शहरयार खान का कोई हक नहीं बनता है।
> **- फैजबिन जंग, साजिदा सुल्तान का बेटा**
>
> पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने नवाब संपत्ति पर अपना हक जताया है। इसके लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है, लेकिन इस पर मैंने आपत्ति जताई है।
> **- आरके पंचोली, वरिष्ठ अधिवक्ता (शर्मिला टैगोर के वकील)**

राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 4 मार्च 2020
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

अजय भूषण पांडेय होंगे नए वित्त सचिव

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय अगले वित्त सचिव होंगे। वे राजीव कुमार की जगह लेंगे। राजीव कुमार पिछले महीने रिटायर हो चुके हैं। कुमार पिछले साल जुलाई में वित्त सचिव बनाए गए थे। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी पांडेय आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआइडीएआइ के सीईओ भी रह चुके हैं। राजस्व सचिव के तौर पर उनके कार्यकाल में जीएसटी कलेक्शन पिछले चार माह से एक लाख करोड़ के स्तर को पार कर रहा है।

हमारी इकोनॉमी पर कोरोना कई तरह से वार कर सकता है। हम सभी तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार हैं।

— शक्तिकांत दास
गवर्नर, आरबीआइ

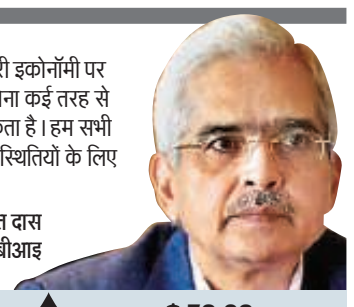

सेंसेक्स	38,623.70 ▲ 479.68	निफ्टी	11,303.30 ▲ 170.55	सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 42,958 ▲ ₹6	चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 46,213 ▼ ₹58	डॉलर	₹ 73.23 ▲ ₹0.47	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 52.93

अप्रैल-दिसंबर में हुए 1.43 लाख करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने मंगलवार को बताया है कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर, 2019) के दौरान बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों से 1.43 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। इसके तहत इस वर्ष जनवरी के अंत तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने 626 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 2,111 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। बैंकिंग धोखाधड़ी पर पूछे एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों (पीएसबी) के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में फ्रेमवर्क जारी किए थे। इसके तहत बैंकों को बड़ी रकम की धोखाधड़ी वाले मामलों की समय पर पहचान, रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित दिशानिर्देश दिए गए थे।

फ्रेमवर्क के तहत बैंकों को उन धोखाधड़ी पर नजर रखनी थी, जिनका मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक हो और जिन्हें फंसा कर्ज (एनपीए) घोषित किया जा चुका हो। इसके अलावा भी सरकार ने कई संरचनात्मक सुधारों की भी घोषणा की थी।

सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने पिछले वर्ष दिसंबर में जारी वित्तीय साक्षरता रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा था कि फ्रेमवर्क के माध्यम से बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम कसने में बड़ी मदद मिली है।

वजह ▶ अगले महीने से सिर्फ बीएस-6 आधारित कारों का उत्पादन

अप्रैल से कारों के दाम छह फीसद तक बढ़ने के आसार

पेट्रोल कारों के दाम छह फीसद, डीजल के चार फीसद तक महंगे होने के संकेत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इस साल अप्रैल से कारें महंगी हो सकती हैं। कीमतों में तीन से छह फीसद तक इजाफा होने के आसार हैं। पहली अप्रैल से कंपनियां बीएस-6 मानक वाली कारों की ही बिक्री कर पाएंगी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) के पदाधिकारियों के मुताबकि बीएस-6 मानक के तहत कार के निर्माण में लागत बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि बीएस-6 मानक वाली पेट्रोल कार की लागत बीएस-4 के मुकाबले चार फीसद तक अधिक होगी। वहीं, डीजल वर्जन में यह अंतर छह फीसद तक होगा। सियाम के मुताबिक यह कार कंपनियों पर निर्भर करेगा कि वह कार की कीमत किस स्तर तक बढ़ाती है, लेकिन पहले से ही लागत का दबाव झेल रही कंपनियां बीएस-6 मानक वाली कार की कीमत बढ़ा सकती हैं। कार

प्रतीकात्मक

कंपनियों के मुताबिक बीएस-4 मानक वाली कारों का स्टॉक काफी कम रह गया है और 15 मार्च तक स्टॉक समाप्त होने की उम्मीद है। लेकिन ग्राहक भी बीएस-6 के इंतजार में हैं। ऐसे में 31 मार्च के बाद बीएस-4 कारों का क्या होगा, इस पर कंपनियां कुछ नहीं कह रही हैं।

अप्रैल में कार डिलीवरी में हो सकती दिक्कत : कार कंपनियों के मुताबिक चीन से ऑटो पार्ट्स की सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से अप्रैल माह में कारों की डिलीवरी में देरी हो सकती है। कंपनियां बीएस-6 मानक के मुताबिक कार बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन उनके पास बीएस-6 गाड़ियों का स्टॉक नहीं है। बीएस-4 का कुछ स्टॉक है जिसे एक अप्रैल से नहीं बेचा जा सकता है। चीन से सप्लाई चेन बाधित होने से कार निर्माण प्रभावित हो रहा है। औद्योगिक संगठन सीआइआइ के अनुमान के मुताबिक चीन से ऑटो पार्ट्स की सप्लाई लंबे समय के लिए प्रभावित रहने पर वर्ष 2020 के दौरान ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग में 8-10 फीसद की गिरावट हो सकती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में भी गिरावट : औद्योगिक संगठन सीआइआइ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए इस्तेमाल होने वाली बैट्री के मामले में काफी हद तक चीन पर निर्भर है। विश्व की तीन-चौथाई बैट्री का उत्पादन चीन में किया जाता है। लिथियम केमिकल्स के लिए भारत पूरी तरह से चीन पर आश्रित है। सोसाइटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई पार्ट चीन से आते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में देरी होगी। मुख्य रूप से ई-रिक्शा के निर्माण में देरी के आसार हैं। टू-व्हीलर की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी एक फीसद से भी कम है।

टेलीकॉम कंपनियां किस्तों में चुका रहीं एजीआर बकाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद टेलीकॉम कंपनियां लगातार किस्तों में भुगतान कर रही हैं। इस बीच एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और टाटा टेलीसर्विसेज ने एजीआर का कुछ और हिस्सा चुकाने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को भारती एयरटेल ने 1,950 करोड़, जियो ने 1,053 करोड़ और टाटा टेलीसर्विसेज ने 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस दौरान एजीआर से सबसे ज्यादा प्रभावित वोडाफोन आइडिया ने और 3,043 करोड़ रुपये दूरसंचार विभाग (डीओटी) को दिए हैं। इस तरह से एजीआर के तहत सरकार को अब तक 25,701 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज ने स्वमूल्यांकन के तहत पूरी राशि अदायगी का दावा किया है। जबकि डीओटी गणना के हिसाब से अभी तक किसी कंपनी ने पूरा भुगतान नहीं किया है। आधिकारिक गणना के हिसाब से वोडाफोन आइडिया को एजीआर के 57,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं। मंगलवार को किए गए ताजा भुगतान के साथ ही एयरटेल ने एजीआर के कुल 18,000 करोड़ रुपये चुकाए हैं। लेकिन डीओटी की गणना के हिसाब से उसे कुल 35,586 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इसी तरह टाटा टेलीसर्विसेज ने एजीआर के लिए अतिरिक्त 2,000 करोड़

प्रतीकात्मक

रुपये देने की बात कही है। इससे पहले कंपनी ने 2,197 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद देनदारी से मुक्त हो जाने की बात कही थी। डीओटी की गणना के हिसाब से टाटा टेलीसर्विसेज को 14,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं।

इस बीच डीओटी ने कहा है कि वह एजीआर गणना में अंतर को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को पत्र लिखेगा। पत्र के जरिये कंपनियों को गणना के संबंध में सफाई देने का निर्देश दिया जाएगा। इससे पहले विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नाम और पते की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। डीओटी ने कोर्ट द्वारा यह जानकारियां मांगे जाने की बात कही गई थी। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष एजीआर को सही ठहराते हुए टेलीकॉम कंपनियों को इसका भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन कंपनियों द्वारा समय पर बकाया नहीं देने के चलते कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई थी।

आरकॉम की समाधान योजना को मंजूरी के संकेत

नई दिल्ली, प्रेट्र : रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) के इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल जाने के संकेत हैं। सूत्रों का कहना है कि कंपनी के प्रमुख कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के बोर्ड ने आरकॉम की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। इस कंपनी से कर्जदाताओं को करीब 23,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

कहा जा रहा है कि यूवी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने 14,700 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। वहीं, मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जियो ने आरकॉम की सहयोगी रिलायंस इन्फ्राटेल के टावर और फाइबर बिजनेस के लिए 4,700 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। इसके साथ ही कंपनी को आरकॉम के कुछ चीन और भारतीय कर्जदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर 4,300 करोड़ रुपये भी चुकाने होंगे।

घटनाक्रम से जुड़े नजदीकी सूत्रों ने बताया कि एसबीआइ के बोर्ड ने आरकॉम के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) में समाधान प्रक्रिया के लिए वोटिंग जारी है। यह वोटिंग बुधवार को खत्म होगी। उम्मीद की जा रही है कि एसबीआइ का बोर्ड इस समाधान योजना के पक्ष में ही वोटिंग करेगा।

गौरतलब है कि आरकॉम ने अपना कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बिक्री की पहले भी कई कोशिशें कीं। लेकिन उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया।

महिलाओं को सशक्त बना रहीं आर्थिक योजनाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार की आर्थिक योजनाओं ने महिला सशक्तीकरण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत कुल खाताधारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 81 परसेंट रही है। पांच अप्रैल, 2016 को लांच हुई इस योजना के तहत अब तक महिलाओं को 16,712 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। मंत्रालय ने बताया कि महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले छह वर्षों के दौरान कई योजनाएं पेश की हैं।

महिला दिवस से पहले वित्त मंत्रालय ने सरकारी प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि अपना रोजगार खड़ा करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। पांच अप्रैल, 2016 को पेश की गई स्टैंड-अप

बढ़ते कदम

- स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं में महिलाओं का बोलबाला
- आसान और सस्ते कर्ज से महिलाओं को मिल रही आर्थिक आजादी

इंडिया स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिला उद्यमी को प्राथमिकता के आधार पर 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का लोन आवंटित किया जाता है।

मंत्रालय ने बताया कि फरवरी, 2020 तक इस योजना के तहत महिलाओं के लिए 73,155 खाते खोले गए हैं। इसके लिए 16,712.72 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है और 9,106.13 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70 परसेंट लाभार्थी महिलाएं हैं। आठ अप्रैल, 2015 को लांच हुई इस योजना के तहत छोटे स्तर के कारोबार के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। अगर मुद्रा योजना के आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष की शुरूआत तक कुल 22.53 करोड़ रुपये का लोन आवंटित किया गया था। इसमें से 15.75 करोड़ रुपये का कर्ज सिर्फ महिलाओं को प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। 28 जनवरी, 2014 को प्रकाश में आई इस योजना का मकसद देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कम से कम एक बैंक खाते की व्यवस्था करना था। इस वर्ष फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल 38.13 करोड़ लाभार्थियों में से 20.33 करोड़ महिलाएं हैं। इस तरह से जन-धन योजना में महिलाओं की 53 परसेंट हिस्सेदारी है।

टाटा स्टील का भविष्य बेहतर : चंद्रशेखरन

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा है कि टाटा स्टील की बुनियाद मजबूत और भविष्य बेहतर है। कंपनी मौजूदा चुनौतियों से पार पाते हुए फिर मजबूती के साथ खड़ी होगी। टाटा समूह के संस्थापक जेएन टाटा की 181वीं जयंती पर बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क से जमशेदपुरवासियों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखरन ने कहा कि एशिया महाद्वीप सहित यूरोप में कोरोना वायरस का असर है। लेकिन टाटा स्टील में इन चुनौतियों से निपटने की क्षमता है।

चंद्रशेखरन के मुताबिक कोरोना से कच्चे व तैयार माल के ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा है। लेकिन 150 वर्ष पुराने टाटा समूह ने दो-दो विश्व युद्ध देखे हैं और बाजार के कई उतार-चढ़ावों का सामना किया है। कंपनी इस चुनौती का भी डटकर मुकाबला करेगी।

सात सत्रों की गिरावट से उबरे शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : मंगलवार का दिन घरेलू शेयर बाजारों के लिए मंगलकारी साबित हुआ। इस दौरान लगातार सात सत्रों की गिरावट पर ब्रेक लगाते हुए देश के प्रमुख शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कोरोना संकट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कहा कि वह वित्त मंत्रालय के साथ इकोनॉमी पर इसके संभावित असर को लेकर बातचीत कर रहा है। इसके चलते शेयर बाजारों को थोड़ी राहत मिली और दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 479.68 अंकों की बढ़त के साथ 38,623.70 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाला निफ्टी में 170.55 अंकों की तेजी देखने को मिली। सत्र समाप्ति की घंटी बजने के समय यह 11,303.30 पर था।

सेंसेक्स पैक में सन फार्मा के शेयरों में सबसे ज्यादा 6.64 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। इसके साथ ही टाटा स्टील, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, पावरग्रिड, आरआइएल, कोटक बैंक और एचसीएल के शेयर भी हरे निशान पर रहे। वहीं आइटीसी और एचडीएफसी के स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में सभी स्टॉक्स हरे निशान पर बंद हुए। इस दौरान मेटल कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.67 परसेंट की तेजी देखने को मिली।

सोना-चांदी के भाव में नहीं हुआ ज्यादा बदलाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : मंगलवार को सोना-चांदी के भाव लगभग सपाट रहे। इस दौरान पीली धातु छह रुपये सुधार के साथ 42,958 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुई। वहीं चांदी की कीमत में 58 रुपये कि गिरावट देखने को मिली। यह 46,213 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी।

जानकारों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव में गिरावट के चलते सोने की कीमत ऊपर बनी रही। इस दौरान ग्लोबल मार्केट में सोना 1,595 डॉलर और चांदी 16.76 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिके। पिछले कई सत्रों से निवेशकों ने सोने में खरीद बढ़ाई थी।

जानकारों के मुताबिक वित्तीय बाजार के सुचारू संचालन के लिए आरबीआइ द्वारा सभी जरूरी कदम उठाने के आश्वासन के बाद निवेशकों के मनोबल में इजाफा हुआ। मंगलवार को एशिया के अन्य शेयर बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। इस दौरान शंघाई और सियोल के शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। वहीं हांगकांग और टोक्यो के बाजारों में गिरावट दर्ज की गई।

झारखंड में किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड की नई सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। चुनाव पूर्व अपने किये गए वादों के मुताबिक सरकार ने बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। किसानों का 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ कर दिया गया है। इसके लिए 2000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं कुछ शर्तों के साथ आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाकर एपीएल वर्ग के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिलाने की घोषणा कर सरकार ने एक बड़े वर्ग को साधा है। महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की भी सरकार ने घोषणा की है। हालांकि बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं राज्य की 100 मलिन बस्तियों में मोहल्ला क्लीनिक खोलने का भी प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों और युवाओं की चिंता तो की ही गई है साथ ही पहली बार परंपरा से हटकर गरीबी रेखा के ऊपर जीवन बसर

- हेमंत सरकार ने पेश किया 86 हजार 370 करोड़ का बजट
- एपीएल को भी मिलेगा आयुष्मान का लाभ

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद

पूर्व की रघुवर सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने इसे स्वीकार किया। कहा कि इस योजना का जिक्र बजट में नहीं है, जाहिर है यह बंद हो रही है।

करने वाले (एपीएल परिवारों) लोगों को भी राहत दी गई है। साथ ही कोई नया कर नहीं लगाकर सरकार ने व्यवसायी वर्ग को भी राहत दी है। सबसे अधिक बजट शिक्षा को देकर सरकार ने अपनी प्राथमिकता भी बता दी है।

फर्जी राशन कार्ड प्रिंटिंग घोटाले का भंडाफोड़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- खाद्य मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दो को दबोचा
- रांची के दो ठगी करने वाले गिरफ्तार, देशव्यापी नेटवर्किंग की जांच
- कार्ड प्रिंट कराने के नाम पर लाखों रुपये वसूलने की थीं शिकायतें
- सरकार ने किया है स्पष्ट- नहीं बन रहे नए राशन कार्ड

'वन नेशन वन राशन कार्ड' की देशव्यापी स्कीम में फर्जी राशन कार्ड प्रिंट करने के नाम पर घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें लोगों को राशन कार्ड प्रिंट करने का ठेका देने के नाम पर वसूली हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में रांची के दो लोगों को राजधानी में ही गिरफ्तार किया है।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने जांच करते हुए 24 घंटे के भीतर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो प्रमुख आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

केंद्रीय खाद्य राज्यमंत्री राव साहेब दानवे ने संवाददाताओं को इस बारे में विस्तार से बताया। उनके साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी थे, जिन्होंने पुलिस कार्रवाई और अभियुक्तों की धर पकड़ के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसी भी तरह का कोई राशन कार्ड नहीं प्रिंट कराया जा रहा है। इसके बावजूद फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने देशव्यापी ठगी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कार्ड प्रिंट कराने का ठेका देने के नाम पर लोगों से

नई दिल्ली में मंगलवार को राशन कार्ड घोटाले की शिकायत मामले को लेकर उपभोक्ता व सार्वजनिक वितरण प्रणली मामलों के राज्यमंत्री राव साहेब डी. पाटिल दानवे ने प्रेस कांफ्रेंस की। साथ में दिल्ली पुलिस में डीसीपी ईश सिंघल। जागरण

लाखों रुपये वसूलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने संसद में इस बारे में स्पष्ट किया है कि सरकार किसी तरह का कोई नया राशन कार्ड प्रिंट नहीं करा रही है। इसके बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों से राशन कार्ड प्रिंटिंग का ठेका देने की शिकायतें मिल रही हैं। दानवे ने बताया कि अब तक कम से कम सौ लोगों ने इस तरह की शिकायत की है। ऐसे ठग फर्जी दस्तावेज, विजिटिंग कार्ड और कथित राशन कार्ड के नमूने देकर लोगों को फंसाते हैं।

दिल्ली पुलिस के डीसीपी ईश सिंघल ने गिरफ्तार आरोपितों के बारे में बताया कि प्रत्यूष राणा पूरे मामले का मास्टर माइंड है। पांच सदस्यों में से दो पकड़ लिए गए हैं। ये सब झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। जिलावार टेंडर देने के नाम पर वसूली कर रहे थे। महाराष्ट्र के रहने वाले भगवत साहेब राव वेयाल ने खाद्य मंत्रालय को इसकी सूचना दी थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। महाराष्ट्र के राव को उनके एक मित्र संजय शालिग्राम कोचे ने बताया था कि मंत्रालय ने महाराष्ट्र में कार्ड प्रिंट करने का ठेका तीन कंपनियों को दिया है, जिसका खुदरा ठेका अन्य लोगों को दिया जाने वाला है। टेंडर दिलाने के लिए 10 लाख रुपये लिए गए थे, लेकिन बात बिगड़ते देख इसमें से 3.5 लाख रुपये वापस भी कर दिए गए हैं। अभियुक्तों को कॉफी होम से गिरफ्तार किया गया।

महिलाओं में अद्भुत नेतृत्व क्षमता : निशंक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर चल रहे कार्यक्रमों के बीच मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंत्रालय की सभी महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के काम-काज और नेतृत्व क्षमता की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी क्षमता और योग्यता से कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

निशंक ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका अहम है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। निशंक के साथ इस दौरान मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी थे।

सरकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए एक पखवाड़ा मना रही है जिसमें सभी मंत्रालयों को महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम संचालित करना है। इस कड़ी में मंगलवार को निशंक ने मंत्रालय पहुंचकर महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को फूल देकर सम्मानित किया।

बड़ा कदम

वरिष्ठजन के लिए सरकार शुरू करेगी नेशनल हेल्प लाइन नंबर, सभी सरकारी एजेंसियों और एनजीओ को जोड़ा जाएगा

बुजुर्गों को अब एक कॉल पर मिलेगी मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उम्र के आखिरी पड़ाव में अपनों की उपेक्षा और एकाकीपन के शिकार बुजुर्गों को अब सुरक्षा सहित अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उनकी एक कॉल पर ही सारी मदद मिलेगी। बुजुर्गों का ख्याल रखने में जुटी सरकार ने उन्हें लेकर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके तहत अप्रैल तक बुजुर्गों के लिए एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया जाएगा। शुरू में इसे कुछ महीने तक ट्रायल के तौर पर रखा जाएगा।

बुजुर्गों तक सीधी मदद पहुंचाने की इस सरकारी योजना के तहत बुजुर्गों के लिए काम कर रही सभी सरकारी एजेंसियों और एनजीओ को कॉल सेंटर से जोड़ा जाएगा। ऐसे में कोई भी कॉल मिलने पर उसे तुरंत उस क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी एजेंसी या एनजीओ को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही उसे पूरा करने की एक समय सीमा भी तय की जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

- देश में 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों की संख्या तकरीबन 15 करोड़

प्रतीकात्मक

से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस क्षेत्र में काम करने वाली आइटी क्षेत्र की कंपनियों से इसे लेकर संपर्क साधा गया है। कई कंपनियों ने रूचि दिखाई है। फिलहाल मंत्रालय ने इसे अप्रैल 2020 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक बुजुर्गों के लिए कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है। ऐसे में इसके शुरू होने से बुजुर्गों को काफी लाभ मिलेगा।

बुजुर्गों की देखरेख को लेकर सरकार ने यह रुझान तब दिखाया है, जब देश में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय में देश में करीब 15 करोड़ बुजुर्ग हैं जो साठ साल की आयु पूरी कर चुके हैं। मंत्रालय की ओर से बुजुर्गों के लिए इसके साथ ही और भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना भी शामिल है, जिसमें बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे से जुड़ी जरूरत के उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इनमें छड़ी, सुनने की मशीन, नकली दांत, चश्मे आदि शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार बुजुर्गों की देखरेख के लिए एक नया विधेयक भी लाई है, जो फिलहाल संसद में लंबित है। माना जा रहा है कि वह संसद के मौजूदा सत्र में पारित भी हो जाएगा।

नकली दवा फैक्ट्री मामले में छापा, भाजपा नेता के भाई समेत तीन पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, भगवानपुर

- रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी एक कंपनी पर मारा छापा
- नामी कंपनियों के नाम पर बनाई जा रही थी दवाएं
- तैयार दवाओं की 26 पेटियां जब्त, 28 कट्टे केमिकल एवं अन्य सामान बरामद

उत्तराखंड में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने नकली दवा बना रही एक फैक्ट्री में छापा मारा। पुलिस ने मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष के भाई समेत तीन को नामजद किया है। फैक्ट्री से नामी दवा कंपनियों के नाम पर बनी 26 पेटी दवाएं एवं केमिकल के कट्टे आदि जब्त किए हैं। वहीं, भगवानपुर क्षेत्र के रायपुर स्थित एक निर्माणाधीन फैक्ट्री पर भी टीम ने छापा मारा। यहां दवाओं की पैकिंग करने वाली तीन मशीनें लगी हुई थीं। तीनों मशीनों को सील कर दिया है। यह निर्माणाधीन फैक्ट्री भी चुड़ियाला में पकड़ी फैक्ट्री की ही शाखा है।

औषधि नियंत्रण विभाग को कुछ नामी दवा कंपनियों की ओर से शिकायत की गई थी कि उनके नाम से बाजार में नकली दवाएं बेची जा रही हैं। इस शिकायत के बाद औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में भगवानपुर क्षेत्र के चुड़ियाला में नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। नकली दवा बनाने की फैक्ट्री भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमन त्यागी के भाई पराग त्यागी की है।

पराग त्यागी के साथ दिनेश चंद्रा निवासी उसायनी, फिरोजाबाद एवं बहादुर हयात निवासी लिंक रोड, खान आलमपुरा सहारनपुर भी उसके साझीदार हैं। छानबीन के दौरान टीम को पता चला कि भगवानपुर क्षेत्र के रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी इस फैक्ट्री की एक शाखा संचालित है। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि रायपुर स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा गया। यह फैक्ट्री निर्माणाधीन है। इस फैक्ट्री में उन्हें तीन मशीनें मिली हैं। इसमें पैकिंग एवं बिलिस्टर मशीन लगी थी। इन मशीनों से दवाओं की पैकिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री पर कोई नाम नहीं लिखा था। केवल मशीनें लगी हैं। इन मशीनों को सील कर दिया है।

वहीं, नकली दवा बनाने के मामले में पराग त्यागी, दिनेश चंद्रा एवं बहादर हयात के खिलाफ भगवानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की पड़ताल अभी जारी है। कई और नाम सामने आ सकते हैं।

अफगानिस्तान युद्ध से जबरदस्त नुकसान

अफगानिस्तान में पिछले 18 वर्षों से लड़ रहे अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध समाप्त हो सकता है। अमेरिका और तालिबान ने दोहा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान में जारी संघर्ष समाप्त हो सकता है। यह समझौता हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अफगानिस्तान की सरकार को किनारे रखकर यह कितना आगे बढ़ पाएगा? दूसरी ओर देखें तो इस युद्ध ने अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों को ही जान-माल का काफी नुकसान पहुंचाया है।

तालिबान पर जिम्मेदारी

यदि तालिबान इस समझौते को निभाता है तो अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी 14 महीने में अफगानिस्तान छोड़ देंगे। इस समझौते को बनाए रखने के लिए तालिबान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अल कायदा और ऐसे ही दूसरे आतंकी संगठनों को इस क्षेत्र में काम करने से रोकना होगा।

बहुत महंगा युद्ध

एक अनुमान के मुताबिक, इस युद्ध ने अमेरिकी करदाताओं पर 2 ट्रिलियन डॉलर (146 लाख करोड़ रुपये) का बोझ डाला है। यह राशि सैन्य अभियानों, अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, पुनर्निर्माण और मादक पदार्थों की रोक पर खर्च की गई। विशेषज्ञों के अनुसार, पूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा और विकलांगता की देखभाल के कारण भविष्य में यह राशि और भी बढ़ सकती है।

चुकानी पड़ी बड़ी कीमत

इस युद्ध की अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ब्राउन विश्वविद्यालय ने नवंबर 2019 में दावा किया था कि सेना और राष्ट्रीय पुलिस के 64 हजार जवानों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 42 हजार आम लोग भी मारे गए। इसके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद गठबंधन की ओर से बमबारी काफी बढ़ गई। 2001 से अफगानिस्तान पर 58,602 बम गिराए गए।

अमेरिकी सैनिकों का हाल

2010 से 2012 के मध्य करीब एक लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद थे और फिलहाल यह संख्या 12 हजार है। युद्ध के दौरान 2,309 अमेरिकियों ने अपनी जान गंवा दी और 20,662 घायल हुए।

33 फीसद पर सरकारी नियंत्रण

इस संघर्ष के बारे में लांग वार जर्नल ने आंकड़े जारी किए हैं। यह सरकार और तालिबान के नियंत्रण वाले जिलों से जुड़ी जानकारी रखता है। अफगानिस्तान सरकार के नियंत्रण में देश के करीब 400 जिलों में से 133 या 33 फीसद का नियंत्रण है। वहीं तालिबान का पूर्ण नियंत्रण 74 जिलों या 19 फीसद है। इसके अतिरिक्त शेष 190 जिलों या 48 फीसद विवादास्पद हैं।

आत्मविश्वास और सुरक्षा की कमजोर भावना

(सर्वे के आंकडें फीसद में)

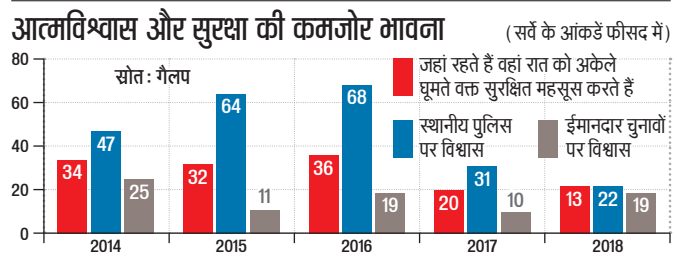

हवाई हमले में मारे गए नागरिक

(सितंबर 2018 तक)

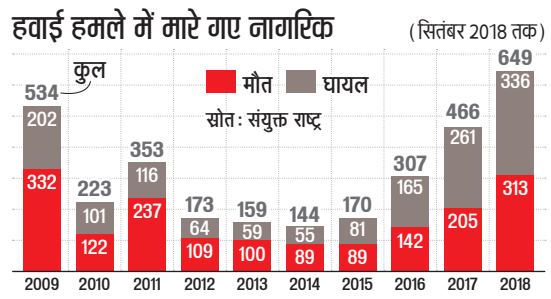

अफगानिस्तान में मरने वालों की संख्या

(2009-19 के मध्य)

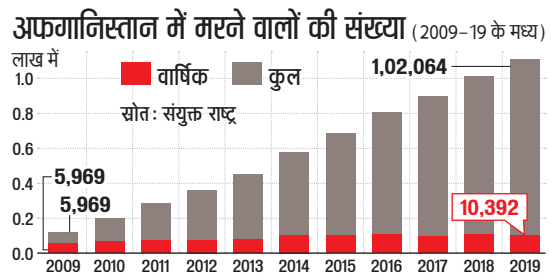

जानें, भारत पर अमेरिका-तालिबान डील का असर और पाकिस्तान की चाल

अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच हुई डील एक ऐतिहासिक पहल है। इसके तहत दोनों तरफ से बड़ी संख्या में कैदियों की रिहाई होनी है। इस संधि के भारत पर होने वाले असर, पाकिस्तान की रणनीति और किस तरह सदियों से रणक्षेत्र रहे इस मुल्क में शांति की बहाली होगी, इन्हें जानना बेहद दिलचस्प है।

कब तक टिकेगा अमेरिका-तालिबान का दोस्ताना?

देखें, ऐतिहासिक यूएस-तालिबान संधि के असर ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens से स्कैन करके

वीडियो देखने के लिए

1. अपने मोबाइल पर Google Lens App डाउनलोड करके OPEN करें. Go to goo.gle/lens, or use the Google Lens App on Android/Google App on iOS
2. ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens के साथ स्कैन करें
3. छपी तस्वीर पर आधारित विश्लेषणात्मक वीडियो देखें

अमेरिका में कोरोना वायरस से छह की मौत

एहतियात ▶ ट्रंप प्रशासन इस हफ्ते के आखिर तक दस लाख लोगों की जांच कराने की तैयारी में

देश में करीब 100 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित

वाशिंगटन : अमेरिका में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। देश में छह मरीजों की मौत के बाद संक्रमण की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की जांच की तैयारी की गई है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को कहा कि वायरस को लेकर इस हफ्ते के आखिर तक करीब दस लाख लोगों की जांच की जा सकती है। अमेरिका में करीब 100 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।

ह्वाइट हाउस में खाद्य और औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉ स्टीफन हान ने कहा, 'निजी कंपनियां और प्रयोगशालाएं भी कोरोना वायरस की जांच में आगे आई हैं। इस विस्तार से बड़े पैमाने पर अमेरिकियों की जांच करने में मदद मिलेगी।' जबकि उप राष्ट्रपति माइक पेंस ने शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा, 'अमेरिकी नागरिकों के कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा निम्न है।' अधिकारियों ने बताया कि मौत के सभी छह मामले वाशिंगटन प्रांत में सामने आए हैं। संक्रमित लोगों में 48 मरीज ऐसे हैं, जो दूसरे देशों से अमेरिका आए हैं।

एक टेस्ट किट से 350 लोगों की होगी जांच : अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अभी उन्हें महज 337 टेस्ट किट मिली हैं। निजी निर्माता जल्द ही ढाई हजार अतिरिक्त किट्स मुहैया करा सकते हैं। एक किट से करीब 350 लोगों की जांच हो सकती है।

टास्क फोर्स में भारतवंशी सीमा को अहम जिम्मेदारी : समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के कोरोना वायरस टास्क फोर्स में भारतीय मूल की हेल्थ पॉलिसी कंसल्टेंट सीमा वर्मा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप राष्ट्रपति पेंस ने यह जानकारी दी। 49 वर्षीय सीमा अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाली संघीय एजेंसी सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकल सर्विसेज (सीएमएस) की प्रशासक हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सीमा को इस पद पर नामित किया था।

पोप का कोरोना वायरस टेस्ट निगेटिव

वेटिकन सिटी, रायटर : पोप फ्रांसिस का कोरोना वायरस टेस्ट निगेटिव आया है। इटली के एक अखबार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वेटिकन के प्रवक्ता मेटियो ब्रूनी ने हालांकि अखबार में छपी खबर पर तत्काल कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। खराब स्वास्थ्य के कारण 83 वर्षीय रोमन कैथोलिक धर्मगुरु ने पिछले सप्ताह कई सार्वजनिक कार्यक्रम रद कर दिए थे। वह ऐसे समय पर बीमार हुए हैं जब इटली कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से जूझ रहा है। इटली में कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या सोमवार को 52 तक पहुंच गई। जबकि संक्रमित लोगों की संख्या दो हजार से ज्यादा हो गई है।

बीमारी की वजह से ऐसा पहली बार हुआ जब पोप ने आध्यात्मिक कार्यक्रम लेंट रिट्रीट में भी हिस्सा नहीं लिया। पोप को वेटिकन के वरिष्ठ धर्मगुरुओं के साथ सप्ताहभर चलने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। लेकिन रविवार को रिट्रीट शुरू होने से कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि वह वेटिकन अतिथि गृह स्थित अपने निवास से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीमारी के चलते एक दशक पहले पोप फ्रांसिस का एक फेफड़ा निकाल दिया गया था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में फार्मास्यूटिकल अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति माइक पेंस (बाएं) से गुफ्तगू करते हुए। बैठक में कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने पर चर्चा हुई। रायटर

दक्षिण कोरिया में प्रभावितों की संख्या पांच हजार के करीब पहुंची

सियोल, एएफपी : कोरोना वायरस के प्रकोप से चीन के बाद विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण कोरिया में संक्रमित लोगों की संख्या करीब पांच हजार पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को 477 नए मामलों की जानकारी दी। कोरिया रोग नियंत्रण एवं बचाव केंद्र (केसीडीसी) ने बताया कि दो और लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 28 तक पहुंच गई है।

दक्षिण कोरिया में हाल में संक्रमण के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। वहीं, अधिकारियों ने शिंचेओंजी चर्च ऑफ जीसस के साथ जुड़े 2,60,000 से अधिक लोगों की जांच तेज कर दी है। संक्रमण के आधे से ज्यादा मामले इस धार्मिक समूह से जुड़े लोगों में पाए गए हैं। प्रकोप को देखते हुए कोरिया पॉप संगीत कार्यक्रम से लेकर खेल कार्यक्रमों तक सैकड़ों आयोजनों को या तो रज करना पड़ा या स्थगित कर दिया गया है। वहीं, देशभर में स्कूलों की छुट्टियां तीन हफ्ते तक बढ़ा दी गई हैं। केसीडीसी ने बताया कि देशभर में सामने आए 4,812 मामलों में से करीब 90 फीसद दाएगू और पड़ोसी प्रांत उत्तर ग्योंगसांग से सामने आए।

तुर्की ने मार गिराया एक और सीरियाई लड़ाकू विमान

बेरुत, एएफपी : सीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इदलिब में असद सरकार और तुर्की के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। तुर्की के एफ-16 विमान ने मंगलवार को सीरिया का एल-39 लड़ाकू विमान मार गिराया। इसकी पुष्टि तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अलावा मुल्क में मानवाधिकार के लिए काम करने वाली निगरानी संस्था ने भी की है। तुर्की ने रविवार को भी सीरिया के दो लड़ाकू विमान मार गिराए थे।

विद्रोहियों के गढ़ इदलिब में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए रूस समर्थित सीरियाई सेना ने बीते गुरुवार को एक हवाई हमले में तुर्की के 34 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद से जवाबी कार्रवाई में तुर्की अभी तक सीरिया के 93 सैनिकों को मौत की नींद सुला चुका है। इदलिब में जमे विद्रोहियों को तुर्की का सहयोग मिलता रहा है। इससे पहले सीरिया ने दावा किया था कि उसने तुर्की के तीन ड्रोन मार गिराए।

ब्राजील में नौका डूबने से 18 लोगों की मौत

साओ पाउलो, एएफपी : ब्राजील के अमेजन जंगलों में बहने वाली एक नदी में सोमवार को नौका डूबने से 18 लोगों की मौत हो गई। अमेजन की सहायक नदी जारी में यह घटना तब हुई जब यात्रियों से भरी नौका दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली थी। नौका पर बैठे 46 लोगों को बचा लिया गया। 30 यात्री लापता बताए जा रहे हैं। इन लोगों की तलाश में हेलीकॉप्टर, गोताखोरों और हवाईजहाज की मदद ली जा रही है। ब्राजील की नौसेना ने हादसों के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

शांति प्रक्रिया के लिए ट्रंप ने दी अशरफ गनी को बधाई

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए उठाए गए कदमों पर अपने अफगानी समकक्ष अशरफ गनी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को जानकारी दी कि ट्रंप और गनी ने रविवार को फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस पर रजामंदी जताई कि यह समझौता अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए मील का पत्थर है।

न्यूज गैलरी

पाक में महिलाओं के मार्च के खिलाफ याचिका खारिज

लाहौर : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लाहौर में महिलाओं के मार्च पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि महिलाओं को मार्च करने से नहीं रोका जा सकता। इस दौरान पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। महिलाओं के सड़क पर उतरने को इस्लाम के विरुद्ध मानते हुए याचिकाकर्ता ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी। (प्रेट्र)

इंडोनेशिया में ज्वालामुखी से निकली राख, सोलो एयरपोर्ट बंद

जकार्ता : इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी मंगलवार सुबह अचानक राख उगलने लगा। इसकी वजह से एहतियात के तौर पर नजदीकी शहर सोलो का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। लोगों को माउंट मेरापी से तीन किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी गई है। 2010 में ज्वालामुखी के विनाशकारी विस्फोटों से 350 लोगों की जान चली गई थी। 9,612 फीट ऊंचा यह देशी-विदेशी ज्वालामुखी पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। (रायटर)

तालिबान ने अफगानिस्तान के 16 प्रांतों पर 33 हमले किए, छह की गई जान

- अफगानी सैन्य अड्डों पर तालिबानी हमले से शांति समझौता खतरे में
- महज 24 घंटों में हुए हमलों में 14 नागरिकहुए घायल

काबुल, एएफपी : अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगानी सेना के अड्डों पर दर्जनों हमले करके तीन दिन पुरानी युद्ध विराम संधि को ही खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी मध्यस्थता से अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच यह संधि कराई गई थी।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत राहिमी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 16 पर 33 हमले किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इन हमलों में छह नागरिक मारे गए हैं और 14 घायल हुए हैं। जबकि दुश्मन सेना के आठ लोग मारे गए हैं और 15 लोग घायल हुए हैं। सरकार ने एक बयान जारी करके बताया कि दक्षिणी कांधार में हुए हमलों में दो सैनिक मारे गए हैं। लोगार प्रांत के गर्वनर के प्रवक्ता दीदार लवांग ने बताया कि काबुल के पास हुए हमले में सुरक्षा बलों के पांच जवान मारे गए हैं।

विगत शनिवार को दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते की शुरुआत आगामी दस मार्च से होनी है। लेकिन कैदियों की अदला-बदली को लेकर हुए विवाद से अब यह सवाल उठने लगा है कि यह समझौता आगे जारी रह पाएगा या नहीं। वहीं, अफगानिस्तान सरकार के एक कर्मचारी नकीबुल्लाह का कहना है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान को बंधक नहीं बना सकता है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन ने कहा कि देश में हिंसा कम करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। साथ ही ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे समझौता मूर्त रूप ले सके।

दूसरी ओर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरैशी ने एक बयान जारी करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी से अपील की है कि वह कैदियों की अदला-बदली की शर्त को छोड़ दें और अमेरिका और तालिबान के शांति समझौते को कायम रहने दें।

एस्पर ने दोहराया, तालिबान से समझौता सशर्त

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि तालिबान के साथ अमेरिका का समझौता 18 साल से अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध की समाप्ति के लिए राजनीतिक समाधान का पहला कदम है। लेकिन यह सशर्त भी है। पेंटागन के रिपोर्टरों से रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि हम कदम-दर-कदम इस समझौते की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। हम अपनी सद्भावना का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर परिस्थितियों में बदलाव होता है तो हम इसे किसी भी समय रोके देंगे। गौरतलब है कि तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका ने अगले 135 दिनों में अपने सैनिकों की संख्या घटाकर 8600 करने और 14 माह में अफगानिस्तान से सभी सैनिक वापस बुला लेने की घोषणा की है।

दो डेमोक्रेट दावेदारों ने किया पूर्व उपराष्ट्रपति बिडेन का समर्थन

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवारी की होड़ में शामिल रहे इंडियाना के साउथ बेंड शहर के पूर्व मेयर पीट बटीगीग और सीनेटर एमी क्लोबुशर ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन की दावेदारी का समर्थन किया है। माना जा रहा है कि 14 राज्यों में होने वाले अहम प्राइमरी चुनाव में दोनों के समर्थन से बिडेन को फायदा हो सकता है।

युवा नेता बटीगीग और मिनिसोटा से सीनेटर क्लोबुशर ने सोमवार को राष्ट्रपति उम्मीदवारी की होड़ से हटने का एलान कर दिया। इन दोनों के हटने से डेमोक्रेटिक पार्टी में अब पांच दावेदार रह गए हैं। राष्ट्रपति पद उम्मीदवारी पाने की होड़ में बिडेन को सीनेटर बर्नी सैंडर्स से तगड़ी चुनौती मिल रही है। बिडेन और सैंडर्स के अलावा अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड, सीनेटर एलिजाबेथ वारेन और न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ही अब इस मुकाबले में रह गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जो व्यक्ति विजेता बनेगा, उसे राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाएगा।

चीनी मीडिया कर्मियों की संख्या में कटौती करेगा अमेरिका

वाशिंगटन, रायटर : चीन में अमेरिकी पत्रकारों के उत्पीड़न के कारण ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका स्थित चीनी मीडिया संस्थानों में काम करने वाले चीनी नागरिकों की संख्या में कटौती का निर्णय लिया है। चीन ने इस पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, अमेरिका के एलान का चीन जोरदार विरोध और निंदा करता है। उसकी यह घोषणा एक तरह से चीनी पत्रकारों का निष्कासन है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने भी अमेरिका के इस कदम को गैर जरूरी बताया।

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान चीन में स्वतंत्र रिपोर्टिंग के हालात सबसे ज्यादा खराब हुए हैं और इसकी तुलना सोवियत संघ के साथ शीतयुद्ध से की जा सकती है। 13 मार्च से प्रभावी होने वाले नियम के तहत वाशिंगटन स्थित शिन्हुआ न्यूज एजेंसी, चीन ग्लोबल टीवी नेटवर्क, चाइना रेडियो इंटरनेशनल और चाइना डेली डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की संख्या 160 से घटाकर 100 की जाएगी। विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा, वर्षों से चीन की सरकार वहां सक्रिय अमेरिकी और विदेशी पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है। चीन ने पिछले माह बीजिंग स्थित वॉल स्ट्रीट जर्नल के तीन पत्रकारों का वीजा रद कर दिया था।

ऑस्ट्रेलिया की 85 साल पुरानी न्यूज एजेंसी जून में होगी बंद

मेलबर्न, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलिया की 85 साल पुरानी न्यूज एजेंसी ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट प्रेस (एएपी) आगामी 26 जून से बंद होने जा रही है। न्यूज एजेंसी बंद होने से करीब 180 लोगों की नौकरी चली जाएगी। न्यूज एजेंसी के मुख्य कार्यकारी बूस डेविडसन ने कहा कि एएपी को बंद करने का फैसला बेहद कठिन रहा। एएपी की न्यूजवायर सर्विस वर्ष 1935 से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अखबारों, प्रसारकों और डिजिटल संपादकों को लेख व समाचार सामग्री मुहैया करा रही है। यह सर्विस 26 जून को अपनी अंतिम सेवा मुहैया कराएगी। 1935 में एएपी की स्थापना कीथ मर्डोक ने की थी।

जनादेश

सत्तारूढ़ गठबंधन 60 और विपक्षी ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी 31 सीटों पर आगे, नई सरकार बनाने में जुटे नेतन्याहू ने कहा, मतभेदों के खिलाफ जीते

इजरायल के संसदीय चुनाव में नेतन्याहू बहुमत के करीब

यरुशलम, प्रेट्र : इजरायल में एक साल के भीतर तीसरी बार हुए संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत के करीब है। इस गठबंधन को हालांकि बहुमत से एक-दो सीटें कम मिलने का अनुमान है। इसके बावजूद नेतन्याहू नई सरकार के गठन में जुट गए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इजरायल में पिछले एक साल से जारी सियासी गतिरोध जल्द दूर हो सकता है।

नेतन्याहू ने मंगलवार को अपनी लिकुड पार्टी के मुख्यालय में समर्थकों से कहा, 'यह बड़ी जीत है। हम सभी मतभेदों के खिलाफ जीते हैं।' पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल करने के लिए दूसरे धड़े के सांसदों से बातचीत शुरू कर दी गई है। इजरायली मीडिया में आई खबरों के अनुसार, 81 फीसद मतपत्रों की गिनती में लिकुड पार्टी 36 सीटों के साथ सबसे आगे है। जबकि पूर्व सेना प्रमुख बेनी गेंट्ज के नेतृत्व वाली ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी को 31 सीटों पर बढ़त मिली है। दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के गठबंधन में शामिल अन्य दल भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गठबंधन में शामिल शास पार्टी और यूनाइटेड तोराह जूडिज्म को क्रमशः दस और आठ सीटें मिलती दिख रही हैं। यामिना पार्टी छह सीटों पर आगे चल रही है। इस तरह नेतन्याहू के गठबंधन को 120 सदस्यीय संसद में कुल 60 सीटों पर बढ़त मिली है। यह आंकड़ा सामान्य बहुमत से एक सीट कम है। अरब इजरायल दलों के गठबंधन को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। पूर्व रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन की धर्मनिरपेक्ष यिजरायल बेइतेनु पार्टी के खाते में सात सीटें आती दिख रही हैं।

एक साल में तीसरे चुनाव : इजरायल में पिछले साल अप्रैल और सितंबर में भी 120 सदस्यीय संसद के चुनाव कराए गए थे। इन दोनों ही चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। लिकुड और ब्लू एंड ह्वाइट दलों में से कोई भी गठबंधन सरकार नहीं बना सका था। इसी के चलते तीसरी बार संसदीय चुनाव की नौबत आई।

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ तेल अवीव में अपने पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए। तीसरी बार हुए चुनाव में नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत के करीब है। रायटर

कश्मीर पर दुष्प्रचार के खिलाफ पाकिस्तान पर बरसे ईयू सांसद

जेनेवा, एएनआइ : कश्मीर पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ यूरोपीय यूनियन (ईयू) के सांसदों ने पाकिस्तान को जमकर खरीखोटी सुनाई है। सांसदों ने कहा कि आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। आतंकी संगठनों में कई असामाजिक तत्व भी हैं जो स्थानीय कश्मीरियों के रोजमर्रा के जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र के मौके पर जेनेवा प्रेस क्लब में 'जम्मू एंड कश्मीरः शिफ्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन' विषय पर हुई परिचर्चा में ईयू सांसदों के अलावा विशेषज्ञों और मीडिया से जुड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया। सांसद गियाना गैंसिया और फुल्वियो मार्टुसिएल्लो ने कहा कि अपने देश में विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पाक आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। गिलगिट पाकिस्तान स्टडीज के प्रेसिडेंट सेंग सेरिंग ने कहा, अनुच्छेद-370 खत्म करने से इस क्षेत्र के लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। एक अन्य सांसद पाउलो कसाका ने कहा, कश्मीर को लेकर पाक दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन हकीकत अलग है।

ईयू के पूर्व सांसद नाथन गिल ने कहा, जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। टू वॉइस ऑफ कश्मीर की सैयद तहमीना ने दुख और गुस्से के साथ कहा कि धरती पर स्वर्ग सरीखा उनका राज्य कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ कहीं खो गया है। परिचर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सज्जाद रजा ने कहा कि पाकिस्तान के शोषण से कश्मीर को निकालने का एकमात्र तरीका विकास है।

दैनिक जागरण
राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 4 मार्च 2020
स्पोर्ट्स
14
www.jagran.com

भारतीय महिला टीम टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की हकदार है। टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है।
— ब्रेट ली, पूर्व तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया

एलिस पैरी महिला टी-20 विश्व कप से बाहर

सिडनी : गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसकी ऑलराउंडर एलिस पैरी महिला टी-20 विश्व कप से बाहर हो गई। उनके पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया जिसके कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की करीबी जीत के दौरान रन आउट करने का प्रयास करने के बाद पैरी को मैदान से लड़खड़ाते हुए बाहर जाते हुए देखा गया था।

एक नजर में

विराट को अधिक अभ्यास करने की जरूरत : कपिल

नई दिल्ली : पूर्व कप्तान कपिल देव का मानना है कि न्यूजीलैंड में विराट कोहली के जूझने का कारण 'रिफ्लैक्स (प्रतिक्रिया देने की क्षमता)' में कमी हो सकती है। पूर्व भारतीय कप्तान ने कोहली को सलाह दी है कि उम्र से जुड़े मुद्दों से उबरने के लिए उन्हें अधिक अभ्यास करने की जरूरत है। न्यूजीलैंड दौरा 31 साल के कोहली के लिए भुलाने वाला अनुभव रहा। कपिल ने कहा, 'प्रत्येक बड़े बल्लेबाज के साथ ऐसा चरण आता है। यह उम्र है, कहते हैं कि 30 साल के होने के बाद नजर कमजोर होती है और इसका आदी होने में छह महीने से एक साल का समय लगता है। मुझे लगता है कि उन्हें (कोहली को) अपनी नजर के अनुसार सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। बड़े खिलाड़ी जब अंदर आती गेंद पर बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होते हैं तो आपको उन्हें अधिक अभ्यास करने के लिए कहना होता है।' 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे कपिल ने कहा, 'यह दर्शाता है कि आपकी आंखें और प्रतिक्रिया देने की क्षमता में कुछ कमजोर हुई है। (प्रेट्र)

फिडे महिला ग्रां प्रि में हरिका की ड्रॉ से शुरुआत

लुसाने : भारत की दूसरे नंबर की खिलाड़ी डी हरिका ने यहां फिडे महिला ग्रां प्रि के पहले दौर में सोमवार को स्वीडन की अनुभवी पिया क्रेमलिंग के खिलाफ ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। हरिका और पिया 37 चाल के बाद अंक बांटने पर सहमत हो गईं। 12 खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन चीन की जू वेनजुन भी हिस्सा ले रही हैं। यह चार ग्रां प्रि की सीरीज का तीसरा टूर्नामेंट है। इस सीरीज से सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली दो शीर्ष खिलाड़ी अगले कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगी। भारत की दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी कोनेरू हंपी दो प्रतियोगिताओं के बाद 293 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। ग्रैंडमास्टर हरिका वेनजुन (120 अंक, एक प्रतियोगिता) के साथ संयुक्त पांचवें स्थान पर है। (प्रेट्र)

जयपुर में होगा एनबीए का ड्रिबल-ए-थॉन

जयपुर : जयपुर में आठ मार्च को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) द्वारा भारत में पहली बार लांच किए गए ड्रिबल-ए-थॉन की धूम होगी। आयोजकों ने मंगलवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह एक ऐसा बास्केटबॉल चैलेंज इवेंट है, जिसमें छह साल से अधिक आयु के प्रतिभागी एक किलो मीटर के कोर्स पर बास्केटबॉल को ड्रिबल करने की चुनौती का सामना करेंगे। भारत में पहली बार हो रही इस इवेंट की शुरुआत 29 फरवरी को चंडीगढ़ में हुई थी। चंडीगढ़ में इस इवेंट के लिए 4000 से अधिक प्रतिभागी पहुंचे थे। इसके बाद यह इवेंट जयपुर पहुंचा है, जहां आगामी रविवार को बापूनगर में स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी के मैदान पर इसका आयोजन होगा। (आइएएनएस)

पूर्व फुटबॉलर पीके बनर्जी की स्थिति संतोषजनक : अस्पताल

कोलकाता : पूर्व भारतीय फुटबॉलर पीके बनर्जी की स्थिति जीवनरक्षक प्रणाली से हटाए जाने के बाद संतोषजनक है। अस्पताल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बनर्जी को निमोनिया के कारण सांस लेने में दिक्कत के कारण 24 घंटे पहले जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। पूर्व में पर्किंसन बीमारी और दिल की समस्या से भी परेशान रहे हैं। इस 83 वर्षीय पूर्व कप्तान का मेडिका सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के बयान के अनुसार, चिकित्सा बोर्ड की मंगलवार को बैठक हुई जिसमें उनकी स्थिति और प्रगति की समीक्षा की गई। बोर्ड ने अभी चलाए जा रहे इलाज की समीक्षा की और वेंटीलेशन से हटाए जाने के बाद रोगी की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। (प्रेट्र)

कोरोना वायरस ने किया खेलों को भी बीमार

अगर 2020 में ओलंपिक नहीं हुए तो टोक्यो गंवा सकता है मेजबानी बाक ने कहा, हम सफलतापूर्वक ओलंपिक के लिए कर रहे हैं तैयारी

टोक्यो, एपी : चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के खेल जगत को बीमार कर दिया है जिसके कारण कई टूर्नामेंट रद कर दिए गए हैं और कई रद होने की कगार पर है। इस साल 24 जुलाई से होने वाले खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक के आयोजन पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के कारण जापान में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और ओलंपिक क्वालीफायर जैसे टूर्नामेंटों को भी स्थगित करना पड़ा है। कोरोना के कारण ग्रीस में अगले सप्ताह होने वाली ओलंपिक मशाल सेरेमनी भी सादे अंदाज में मनाई जाएगी।

जापान की ओलंपिक मंत्री सीको हाशिमोतो ने मंगलवार को अपनी संसद के उच्च सदन में कहा कि अगर टोक्यो ओलंपिक को इस साल के बाद के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो टोक्यो ओलंपिक की मेजबानी गंवा सकता है। उन्होंने कहा, 'अनुबंध के अनुसार अगर यह खेल 2020 में आयोजित नहीं किए जाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) मेजबानी के अधिकार वापस ले सकती है। हालांकि मई के अंत तक ओलंपिक पर फाइनल फैसला हो सकता है इसलिए मई का महीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।' जापान की सरकार, टोक्यो ओलंपिक के आयोजक और आइओसी इन खेलों का आयोजन 24 जुलाई से ही कराने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते कोराना वायरस ने उन सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इससे पहले ओलंपिक मंत्री ने कहा था कि ओलंपिक अगर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो पाता है तो इन्हें इस साल के अंत में भी आयोजित किया जा सकता है। वहीं, आइओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि हम सफलतापूर्वक इन खेलों की तैयारी कर रहे हैं। हमें आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे और यह जून में होगा। लुसाने में 15-17 जून तक गेम्स को लेकर पहली कार्यकारी बोर्ड की बैठक होगी। टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने कहा कि इस वायरस के कारण इस महीने होने वाले व्हीलचेयर रग्बी टूर्नामेंट को रद कर दिया गया। यह टूर्नामेंट 12 से 15 मार्च तक होना था। **कुमिंग ओपन टेनिस टूर्नामेंट स्थगित :** महिलाओं के कुमिंग ओपन टेनिस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण रद कर दिया गया है।

टोक्यो में मंगलवार को कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहने हुए ओलंपिक रिंग को देखती एक महिला ● रायटर

भारतीय टीम का दौरा रद

नई दिल्ली : भारतीय अंडर-16 फुटबॉल टीम के मैत्री मैचों के लिए प्रस्तावित दौरे को तजाकिस्तान ने कोरोना के कारण रद कर दिया। भारतीय टीम को तजाकिस्तान के खिलाफ दो दोस्ताना मुकाबले खेलने के लिए पांच मार्च को यहां से रवाना होना था।

प्रशंसकों को ऑटोग्राफ ना दें खिलाड़ी

लास एंजिलिस : नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) ने खिलाड़ियों को सुझाव दिए हैं कि वे प्रशंसकों से बातचीत करने से बचें। टीमों को संदेश भेजा गया है जिसमें खिलाड़ियों को वायरस के संपर्क से बचाने के उद्देश्य से अल्पकालिक उपायों की रूपरेखा तैयार की है। खिलाड़ी प्रशंसकों से हाथ मिलाने से भी बचें। खिलाड़ियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऑटोग्राफ देने के लिए पेन, बॉल और जर्सी जैसी चीजें लेने से बचें।

आइपीएल पर खतरा नहीं : बृजेश पटेल

मुंबई : आइपीएल संचालन समिति के अध्यक्ष बृजेश पटेल ने कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट पर किसी खतरे की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए है। आइपीएल का आगाज 29 मार्च को मुंबई में चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से होगा। इसका फाइनल 24 मई को खेला जाएगा। पटेल से जब पूछा गया कि क्या आइपीएल को कोरोना वायरस से कोई खतरा है तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई खतरा नहीं है।

श्रीलंका दौरे पर हाथ नहीं मिलाएंगे इंग्लैंड के क्रिकेटर

लंदन : इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा कि उनके खिलाड़ी कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के कारण श्रीलंका दौरे पर हाथ नहीं मिलाएंगे। इंग्लैंड की टीम दो टेस्ट की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर जा रही है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर पहले टेस्ट से पूर्व और बाकी मैचों के दौरान भी इंग्लैंड टीम के कई सदस्यों को पेट में तकलीफ और फ्लू की समस्या से जूझना पड़ा था। कप्तान रूट ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका में बीमारी से टीम के सदस्यों के परेशान होने के बाद हम न्यूनतम संपर्क की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं और हमारी मेडिकल टीम ने रोगाणुओं और जीवाणुओं को फैलने से रोकने के लिए हमें व्यावहारिक सलाह दी है। हम एक-दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हम नियमित तौर पर हाथ धोएंगे।'

कोरोना वायरस से भारतीय महिला पहलवानों का यूक्रेन शिविर रद

नंदकिशोर भारद्वाज ● सोनीपत

कोरोना वायरस का असर भविष्य में होने वाली खेल की बड़ी प्रतियोगिताओं पर भी पड़ रहा है। कोरोना वायरस के डर के कारण किर्गिस्तान में एशियन देशों के पहलवानों के लिए इसी माह के अंत में होने वाले ओलंपिक क्वालीफाइंग आयोजन को पहले ही रद कर दिया गया है। ओलंपिक क्वालीफायर की तैयारी के लिए भारतीय महिला टीम को पांच मार्च से 13 दिन के अभ्यास शिविर के लिए यूक्रेन जाना था। अब इस शिविर को भी रद कर दिया गया। शिविर की नई तारीख का एलान बाद में किया जाएगा।

किर्गिस्तान में एशियन देशों के पहलवानों के लिए 27 मार्च से 29 मार्च तक होने वाले ओलंपिक क्वालीफाइंग आयोजन को कोरोना वायरस के कारण रद कर दिया गया। इसी की तैयारी के लिए भारतीय महिला पहलवानों के दल को पांच मार्च से 18 मार्च तक यूक्रेन में अभ्यास शिविर के लिए जाना था, लेकिन इसे भी रद कर दिया गया। अभी भारतीय महिला पहलवान लखनऊ में अभ्यास कर रही हैं। अभ्यास शिविर के लिए नई तारीख का एलान बाद में किया जाएगा। ओलंपिक के लिए 53 किलो भार वर्ग में विनेश को ट्रायल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें कोटा मिल चुका है। इसके अलावा ओलंपिक क्वालीफायर में 50 किग्रा में निर्मला, 57 किग्रा में अंशु मलिक, 62 किग्रा में सोनम मलिक, 68 किग्रा में दिव्या काकरान और 87 किग्रा में किरण भाग लेंगी। वहीं, ग्रीको रोमन श्रेणी के छह पहलवान 20 दिवसीय अभ्यास शिविर के लिए अजरबैजान के लिए मंगलवार शाम को बहालगढ़ स्थित साई केंद्र से रवाना हुए। ये पहलवान ओलंपिक क्वालीफायर के लिए तैयारी करेंगे। उधर, ओलंपिक क्वालीफायर की तैयारियों के लिए फ्री स्टाइल के पहलवानों का दल भी पांच मार्च को 18 दिवसीय अभ्यास शिविर के लिए रूस के लिए रवाना होंगे।

पांच मार्च से 18 मार्च तक होना था यह अभ्यास शिविर

13 दिन का यूक्रेन अभ्यास शिविर कोरोना वायरस के कारण हो गया। फिलहाल महिला पहलवान देश में ही अभ्यास करेंगी। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है।
कुलदीप सिंह मलिक, मुख्य कोच

तेज गेंदबाजी विभाग में बदलाव करना चाहते हैं कोहली

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज हारने के तुरंत बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस हार का ठीकरा अपने बल्लेबाजों के सिर पर फोड़ा था और अपने गेंदबाजों की तारीफ की थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि उनके गेंदबाज लंबे समय तक सही लाइन व लेंथ के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाए। फिर भी इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह से नाकाम रहा था। यहां तक कि खुद कोहली भी चार पारियों में सिर्फ 38 रन ही बना पाए थे। इसके एक दिन बाद ही मंगलवार को कोहली ने निकट भविष्य में टीम में बदलाव करने के संकेत दिए हैं, लेकिन ये बदलाव बल्लेबाजी क्रम में नहीं, बल्कि तेज गेंदबाजी विभाग में हो सकते हैं। कप्तान ने कहा है कि भारतीय तेज गेंदबाजों की बढ़ती उम्र के कारण टीम के थिंक टैंक ने निकट भविष्य में तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी तैयार करने की जरूरत महसूस की है।

भारतीय टीम सोमवार को जब क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट सात विकेट से हारी थी तो उसके बाद कोहली ने कहा था कि इस प्रदर्शन के लिए कोई बहाना नहीं है। टेस्ट मैचों में हम वैसा क्रिकेट नहीं खेल पाए जैसा खेलना चाहते थे। बल्लेबाजों ने इतने रन नहीं बनाए कि गेंदबाज प्रयास और आक्रमण करते। गेंदबाजी अच्छी थी, मुझे लगता है कि वेलिंगटन में भी हमने अच्छी गेंदबाजी की। पहले मैच में हम पर्याप्त जज्बा नहीं दिखा पाए, जबकि यहां हम मैच को खत्म नहीं कर पाए। कोहली के इस बयान के बाद अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। लेकिन, 24 घंटे बीतने के साथ ही कोहली का नजरिया बदला है और वह इस हार के सबसे प्रमुख कारण को अपने तेज गेंदबाजों की बढ़ती उम्र के साथ जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के कई और वर्षों तक टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करने की उम्मीद है, लेकिन इस साल 32 वर्ष के होने वाले इशांत शर्मा और 29 साल के मुहम्मद शमी पहले ही अपने खेल के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उमेश यादव भी इस साल 33 साल के हो जाएंगे।

बदलाव के लिए रहना होगा तैयार : अगले कुछ वर्षों की योजना को छिपाए बिना कोहली ने कहा, 'ये खिलाड़ी अब युवा नहीं होने वाले, इसलिए हमें बेहद सतर्क और जागरूक रहना होगा और स्वीकार करना होगा कि यह स्थिति है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है और हमारे पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो उनकी जगह ले सकें।' इशांत का रिहैबिलिटेशन अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण उनके टखने की चोट दोबारा उभर गई और पिछले दो साल में शमी पर पड़ा बोझ संकेत है कि शायद अगले दो साल में टीम को तेज गेंदबाजी विभाग में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए।

योजना का हिस्सा : नई प्रतिभाओं पर ध्यान देने का संकेत देते हुए कोहली ने कहा, 'बड़ी तस्वीर देखें तो हमें यह पहचान करने की जरूरत है कि अगले तीन-चार खिलाड़ी कौन होंगे जो स्तर को बरकरार रख सकें क्योंकि आप नहीं चाहते कि अगर अचानक कोई बाहर हो जाए तो उसकी कमी महसूस हो। क्रिकेट में ऐसा ही होता है। समय-समय पर छोटे स्तर पर बदलाव के दौर का सामना करना पड़ता है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी खिलाड़ी का इस्तेमाल करें और जब वह जाए तो आपके पास कोई विकल्प ही न हो। मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में हमें पता है कि इस तरह की चीजें संभव हैं।' कप्तान ने कहा कि नवदीप सैनी पहले ही टीम का हिस्सा हैं, जबकि दो या तीन और नाम हैं जो योजना का हिस्सा हैं। कोहली ने कहा, 'सैनी प्रणाली का हिस्सा बन चुका है। दो या तीन और खिलाड़ियों पर हमारी नजर है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है और समझना होगा कि इनसे (तेज गेंदबाजों से) हमें काफी सफलता मिली है।

इशांत शर्मा / उम्र : 31 साल				
28 साल की उम्र तक प्रदर्शन				
टेस्ट	विकेट	औसत	सर्वश्रेष्ठ	5विकेट
72	209	36.71	7/74	7
28 साल की उम्र के बाद प्रदर्शन				
25	88	22.11	5/22	4

इशांत व उमेश पार कर चुके हैं 30 की उम्र

तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन की तुलना				
जसप्रीत बुमराह / उम्र : 26 साल				
टेस्ट	विकेट	औसत	सर्वश्रेष्ठ	5विकेट
14	68	20.33	6/27	5

उमेश यादव / उम्र : 32 साल				
28 साल की उम्र तक प्रदर्शन				
टेस्ट	विकेट	औसत	सर्वश्रेष्ठ	5विकेट
15	48	38.56	5/93	1
28 साल की उम्र के बाद प्रदर्शन				
31	96	26.42	6/88	2

मुहम्मद शमी / उम्र : 29 साल				
28 साल की उम्र तक प्रदर्शन				
टेस्ट	विकेट	औसत	सर्वश्रेष्ठ	5विकेट
34	128	29.19	5/28	3
28 साल की उम्र के बाद प्रदर्शन				
15	56	23.30	6/56	2

कोहली काफी ऊर्जावान खिलाड़ी : साउथी

क्राइस्टचर्च : न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी ने विराट कोहली के आक्रामक रवैये का बचाव करते हुए कहा कि भारतीय कप्तान 'काफी जुनूनी खिलाड़ी' हैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं।

दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के आउट होने के बाद कोहली ने जबरदस्त जश्न मनाया था और कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। आइपीएल में कोहली के साथ खेल चुके साउथी ने कहा, 'वह काफी जुनूनी व्यक्ति हैं और मैदान पर काफी ऊर्जावान। वह अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं।' सोमवार को यहां हार के बाद एक स्थानीय पत्रकार ने इस घटना पर कोहली की प्रतिक्रिया पूछी तो भारतीय कप्तान को यह पसंद नहीं आया था। पत्रकार ने कोहली से पूछा, आपको क्या लगता है? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं।

हार्दिक पांड्या ने 39 गेंदों पर ठोक डाले 105 रन

नवी मुंबई, आइएएनएस : फिट होकर वापस लौटे भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले 39 गेंदों पर 105 रन जड़ते हुए मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने यह पारी यहां मंगलवार को डीवाई पाटिल टी-20 कप के ग्रुप-सी के मैच में रिलायंस 1 की ओर से सीएजी के खिलाफ खेली। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान हार्दिक ने आठ चौके व 10 छक्के जड़े। इस पारी की मदद से रिलायंस-1 ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 252 रन बनाए।

पीठ के निचले हिस्से की सर्जरी कराने के बाद हार्दिक पिछले करीब छह महीने से टीम से बाहर चल रहे हैं। अपनी इस तूफानी पारी के बाद हार्दिक ने कहा, 'यह मेरे जैसे लोगों के लिए शानदार प्लैटफॉर्म है। मैं लगभग छह महीने तक खेल से दूर रहा। मेरे लिए यह एक अच्छा प्लैटफॉर्म है जहां मैं वर्तमान में हूं और अपना परीक्षण कर रहा हूं।'

हार्दिक ने तीन महीने में बढ़ाया सात किग्रा वजन : हार्दिक पांड्या ने तीन महीने में सात किलोग्राम वजन बढ़ाया है। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर अपनी दो तस्वीरें साझा कीं। वह पिछले साल सितंबर में टीम इंडिया की जर्सी पहने खेलते नजर आए थे जिसके बाद से वह भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं।

हार्दिक पांड्या ● ट्विटर

सीरीज हारने के बावजूद भारत शीर्ष पर कायम

दुबई, प्रेट्र : न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 0-2 से गंवाने के बाद भी भारतीय टीम मंगलवार को जारी ताजा आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर बरकरार है। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं।

टेस्ट रैंकिंग

भारतीय टीम के नाम 116 अंक हैं, जो दूसरे स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड से छह अंक ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया 108 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। आइसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को पहली बार किसी सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। आइसीसी के मुताबिक, सीरीज की चार पारियों में महज 38 रन बनाने वाले कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। वह सीरीज से पहले रैंकिंग में शीर्ष पर थे, लेकिन पहले टेस्ट के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ पहले स्थान पर आ गए थे। वह कोहली से 25 अंक आगे हैं। रैंकिंग में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल, भारतीय सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और कीवी तेज गेंदबाज काइली जेमिसन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ब्लंडेल ने सीरीज की चार पारियों में एक अर्धशतक के साथ 117 रन बनाए। वह रैंकिंग में 27 स्थान का सुधार करते हुए 46वें पायदान पर पहुंच गए हैं। क्राइस्टचर्च टेस्ट में 54 रन की पारी खेलने वाले शॉ 17 स्थान के सुधार के साथ 76वें स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा और वह चौथे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशाने तीसरे स्थान पर आ गए हैं।

इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स शीर्ष-10 में जगह बनाने में सफल रहे, जबकि मयंक अग्रवाल 10वें से 11वें स्थान पर फिसल गए। चेतेश्वर पुजारा सातवें और अजिंक्य राहणे नौवें स्थान पर हैं। गेंदबाजों में मैन ऑफ द सीरीज टिम साउथी शीर्ष पांच में पहुंच गए हैं। उन्होंने रैंकिंग में दो स्थान का सुधार किया और चौथे स्थान पर काबिज हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट चार-चार स्थानों के सुधार के साथ क्रमशः सातवें और नौवें स्थान पर आ गए हैं। गेंदबाजों की सूची में सबसे ज्यादा फायदा जेमिसन को हुआ, जो 43 स्थान के सुधार के साथ 80वें पायदान पर पहुंच गए। वह ऑलराउंडर खिलाड़ियों की सूची में 26 पायदान ऊपर 22वें स्थान पर आ गए हैं। इस सूची में रवींद्र जडेजा तीसरे और अश्विन पांचवें स्थान पर बने हुए हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद लौटती भारतीय टीम ● फाइल फोटो, एएनआइ

टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पांच बल्लेबाज		
बल्लेबाज	देश	रेटिंग
स्टीव स्मिथ	ऑस्ट्रेलिया	911
विराट कोहली	भारत	886
लाबुशाने	ऑस्ट्रेलिया	827
विलियमसन	न्यूजीलैंड	813
बाबर आजम	पाकिस्तान	800

टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पांच गेंदबाज		
गेंदबाज	देश	रेटिंग
पैट कमिंस	ऑस्ट्रेलिया	904
नील वैगनर	न्यूजीलैंड	843
जेसन होल्डर	वेस्टइंडीज	830
टिम साउथी	न्यूजीलैंड	812
कैगिसो रबादा	द. अफ्रीका	802

टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पांच टीम: भारत 116, न्यूजीलैंड 110, ऑस्ट्रेलिया 108, इंग्लैंड 105, द. अफ्रीका 98

मुकाबला सेमीफाइनल में कर्नाटक को 174 रनों से दी शिकस्त, मुकेश ने झटके छह विकेट, अनुस्तूप ने खेली शतकीय पारी

13 साल बाद रणजी के फाइनल में पहुंचा बंगाल

विशाल श्रेष्ठ ● कोलकाता

क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन जब कोई टीम एकजुट होकर शानदार प्रदर्शन कर रही होती है तो सारी चीजें निश्चित नजर आने लगती हैं। ईडन गार्डेंस स्टेडियम में बंगाल-कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में कुछ ऐसा ही दिखा।

मैच के पहले दिन अनुस्तूप मजुमदार (नाबाद 149) की घोर संकट के समय खेली गई साहसिक पारी, दूसरे दिन तेज गेंदबाज इशान पोरेल (5/39) का बंगाल को ड्राइविंग सीट पर बैठाने वाला शानदार स्पैल, तीसरे दिन एक बार फिर मजुमदार (41) और उनके साथ सुदीप चटर्जी (45) की उपयोगी पारियां और चौथे व अंतिम दिन मुकेश कुमार (6/61) का निर्णायक स्पैल। इन शानदार प्रदर्शनों ने बंगाल को 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद फिर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा दिया। बंगाल अब नौ मार्च से शुरू होने वाली खिताबी जंग में जोरआजमाइश करेगी। बंगाल ने दक्षिण भारतीय टीम का विजय रथ रोकते हुए उसे क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में 174 रन से हरा दिया। 352 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्नाटक ने तीसरे दिन ही अपनी दूसरी पारी में 98 रन पर तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। मंगलवार को आखिरी दिन उसके बाकी सात विकेट महज 16.3 ओवर में 79 रन पर ढह गए। बंगाल की टीम इससे पहले 2007 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। वहीं, भारतीय टेस्ट विकेटकीपर और अनुभवी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को नौ मार्च से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच के लिए बंगाल टीम में शामिल किया गया है।

सौराष्ट्र ने गुजरात को दिया बड़ा लक्ष्य

राजकोट : अर्पित बासवदा की विषम परिस्थितियों में खेली गई शतकीय पारी से सौराष्ट्र ने सेमीफाइनल के चौथे दिन मंगलवार को यहां गुजरात के सामने 327 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा। बासवदा ने 139 रन बनाए जिसमें उन्होंने 16 चौके और एक छक्का जड़ा। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के सामने स्टंप उखड़ने के समय गुजरात ने एक विकेट पर सात रन बनाए थे।

सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत

सिडनी, प्रेट्र : भारत महिला टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा जो ग्रुप-बी में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरे स्थान पर रहा। इस मैच के रद होने से दक्षिण अफ्रीका को एक अंक मिला और टीम ग्रुप-बी में सात अंक के साथ शीर्ष पर रही।

पहली बार फाइनल में जगह बनाने की कोशिशों में जुटा भारत ग्रुप-ए में अपने चारों मैच जीतकर आठ अंक के साथ शीर्ष पर रहा था। तीन जीत और एक हार से छह अंक जुटाने वाले इंग्लैंड और भारत के बीच सेमीफाइनल गुरुवार को खेला जाएगा। 2018 में हुए पिछले टूर्नामेंट में भी यही दोनों टीमें सेमीफाइनल में आमने-सामने थीं। इंग्लैंड ने 2018 टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत को हराया था, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। दूसरा सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। वहीं, नथाकन चंतम (56) के पचासे से थाइलैंड ने पाक के खिलाफ 150 रन का स्कोर खड़ा किया और टीम का टी-20 में यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। जवाब में पाक की टीम बारिश के कारण अपनी पारी नहीं खेल सकी।

महिला टी-20 विश्व कप			
सेमीफाइनल	मैच	दिन	समय
पहला	भारत बनाम इंग्लैंड	गुरुवार	सुबह 9.30 सुबह से
दूसरा	द. अफ्रीका vsऑस्ट्रेलिया	गुरुवार	दोपहर 1.30 बजे से

> पाकिस्तान को अगर नंबर एक टेस्ट टीम बनना है तो उसे नियमित तौर पर शानदार प्रदर्शन करना होगा।
> – यूनिस खान, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर

हॉकी इंडिया के पुरस्कार की दौड़ में कप्तान मनप्रीत सिंह

नई दिल्ली, प्रेट्र : हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय टीमों के कप्तानों मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल को आठ मार्च को दिए जाने वाले अपने तीसरे वार्षिक पुरस्कारों के लिए मंगलवार को घोषित नामांकन में ध्रुव बत्रा साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए पुरुष और महिला वर्ग में नामांकित किया। इस पुरस्कार समारोह में कुल 1.30 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि के साथ विजेताओं को ट्रॉफियां दी जाएंगी।

न्यूज गैलरी

धौनी से मिले रैना तो किया गर्दन पर किस

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और बल्लेबाज सुरेश रैना का सारा ध्यान आइपीएल के अगले सत्र पर है। धौनी और रैना दोनों ही चेन्नई में आइपीएल की तैयारी के लिए पहुंच चुके हैं। इन दोनों के बीच हुई पहली मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंगलवार को अपने कप्तान धौनी और रैना की मुलाकात का एक वीडियो चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया। धौनी और रैना लंबे समय बाद मिले। जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें धौनी को आते देख रैना आगे जाकर उनसे गले मिलते हैं और साथ ही उनकी गर्दन पर किस भी करते हैं। धौनी को किस करने वाला यह वीडियो काफी चर्चा में है। सभी जानते हैं कि रैना और धौनी के बीच कितनी गहरी दोस्ती है। (जेएनएन)

पोंटिंग के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हूं : कैरी

केपटाउन : दिल्ली कैपिटल्स के नए विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने मंगलवार को कहा कि वह 29 मार्च से शुरू हो रहे आइपीएल के अगले सत्र में कोच और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग के क्रिकेट कौशल से सीखने के लिए उत्सुक हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप टीम के सदस्य रहे कैरी इस साल आइपीएल में पदार्पण करेंगे। उन्हें दिल्ली की टीम ने खिलाड़ियों की नीलामी में दो करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के ब्लोमफोंटेन रवाना होने से पहले कैरी ने कहा, 'मैं इंतजार नहीं कर सकता, अगर मैं खेल नहीं भी रहा हूं तो भी, उनके (पोंटिंग) साथ बैठने और क्रिकेट पर बात करने के लिए।' (प्रेट्र)

मैक्सवेल ने लंकाशायर के साथ अनुबंध बढ़ाया

लंदन : ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को इंग्लैंड की काउंटी टीम लंकाशायर ने 28 मई से यहां शुरू हो रहे टी-20 ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र के लिए एक बार फिर अनुबंधित किया है। क्लब ने घोषणा की कि 31 साल का यह क्रिकेटर नॉर्थ ग्रुप के कम से कम पहले आठ मैचों में खेलेगा और फिर राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौट जाएगा। (प्रेट्र)

तमीम के शतक से बांग्लादेश ने जिंबाब्वे को दी शिकस्त

दूसरा वनडे ▶ इकबाल ने 132 गेंदों पर खेली 158 रनों की पारी

सिलहट, एएफपी : तमीम इकबाल की अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी की मदद से विशाल स्कोर बनाने वाले बांग्लादेश ने डोनाल्ड टिरिपानो के अंतिम क्षणों की धुआंधार बल्लेबाजी के बावजूद दूसरे वनडे मैच में मंगलवार को यहां जिंबाब्वे पर चार रन से रोमांचक जीत दर्ज की। तमीम ने 132 गेंदों पर 158 रन बनाए जिसमें 20 चौके और तीन छक्के शामिल हैं। उन्होंने खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले उन्होंने जिंबाब्वे के खिलाफ ही 2009 में 154 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। तमीम जब 84 रन पर पहुंचे तो वह वनडे में 7000 रन पूरे करने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने। उन्होंने 106 गेंदों पर अपना 12 वनडे शतक पूरा किया, जो उनका जुलाई 2018 के बाद पहला सैकड़ा है।

तमीम की इस पारी से बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 322 रन बनाए और जिंबाब्वे के खिलाफ अपने रिकॉर्ड में एक रन से सुधार किया। जवाब में सलामी बल्लेबाज टिनसे कामुनकामवे (51), युवा वेस्ले माधवेरे (52) और अनुभवी सिकंदर रजा (66) की बदौलत जिंबाब्वे की टीम आठ विकेट पर 318 रन तक ही पहुंच पाई। टिरिपानो (28 गेंदों पर नाबाद 55) ने टिनोटेंडा मुतोम्बोदजी (21 गेंदों पर नाबाद 34) ने आठवें विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की। जिंबाब्वे को आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे। टिरिपानो ने अल अमीन हुसैन पर दो छक्के जड़कर मैच रोमांचक स्थिति में पहुंचा दिया। जिंबाब्वे को अंतिम दो गेंदों पर छह रन चाहिए थे लेकिन टिरिपानो एक रन ही बना पाए। बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। बांग्लादेश की तरफ से ताइजुल इस्लाम ने 52 रन देकर तीन विकेट लिए।

बांग्लादेश के बल्लेबाज तमीम इकबाल। फाइल फोटो, ट्विटर

ओलंपिक ट्रायल में शामिल होना चाहते हैं मुक्केबाज सुमित

यशपाल वर्मा, करनाल : हरियाणा के मुक्केबाजों के लिए आइकन बने सुमित सांगवान पर लगा एक साल का प्रतिबंध राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने हटा लिया है। इसके चलते उम्मीद जगी है कि वह पदक जीतने का सिलसिला फिर से जारी करेंगे। प्रतिबंध हटने के बाद सुमित ने टोक्यो ओलंपिक में खेलने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए भारतीय मुक्केबाजी संघ को अर्जी देकर खुद को ट्रायल में शामिल करने गुहार लगाई है।

गांव शेखपुरा सोहाना निवासी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज सुमित ने 11 वर्ष की उम्र से अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अप्रैल-2012 में अस्ताना में एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुमित सुर्खियों में आए। लंदन ओलंपिक-2012 में भाग ले चुके सुमित 91 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले खेलते रहे हैं। सुमित के अनुसार टोक्यो ओलंपिक-2020 क्वालीफायर ट्रायल के लिए उनके पास मौका है और उसके लिए महासंघ को अर्जी दी है। सुमित के अनुसार, खिलाड़ी पर डोपिंग का आरोप किसी दाग से कम नहीं होता है। 26 दिसंबर को लगे प्रतिबंध के बाद से मैं काफी परेशान था।

गौरव और आशीष प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

एशियन ओलंपिक क्वालीफायर

- सेमीफाइनल में पहुंचने वाले मुक्केबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए करेंगे क्वालीफाई

अम्मान (जॉर्डन), प्रेट्र : कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता गौरव सोलंकी (57 किग्रा) और आशीष कुमार (75 किग्रा) एशियन ओलंपिक क्वालीफायर के शुरुआती दौर में मंगलवार को यहां अपने-अपने मुकाबले जीतकर अंतिम-16 में पहुंचे।

कॉमनवेल्थ गेम्स में 52 किग्रा में पीला तमगा हासिल करने वाले सोलंकी ने किर्गिस्तान के अकीलबेक एसेनबेक उलु को एकतरफा मुकाबले में हराकर 5-0 से हराया जबकि एशियन चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता आशीष ताईवान के कान चीया-वेई पर भारी पड़े। भारतीय मुक्केबाज ने 5-0 की दमदार जीत दर्ज की। सोलंकी ने किर्गिस्तान के दो बार के राष्ट्रीय चैंपियन के खिलाफ शुरू से ही दबदबा बना लिया और उन्हें विरोधी मुक्केबाज की कमजोर रक्षा तकनीक का भी फायदा मिला। उन्होंने सटीक पंच लगाकर अंक हासिल किए।

प्री-क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान के शीर्ष वरीय मिराजिजबेक मिर्जाखालिलोव से होगा जिन्हें पहले दौर में बाई मिली। मिर्जाखालिलोव मौजूदा विश्व चैंपियन हैं और उन्होंने 2018 एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप के के स्वर्ण पदक हासिल किया था। आशीष प्री-क्वार्टर फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त किर्गिस्तान के ओमुरबेक बेखजित उलु से भिड़ेंगे। उन्होंने पिछले साल एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में इस मुक्केबाज को हराया था।

टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले मुक्केबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे। विश्व रजत पदक विजेता अमित पंघाल (52 किग्रा) को पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गइ है जबकि एमसी मेरी कॉम (51 किग्रा) को महिला वर्ग में दूसरी वरीयता मिली है। अन्य भारतीयों में दो बार की विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहिन (69 किग्रा), एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता पूजा रानी (75 किग्रा) और कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता सतीश कुमार (91 किग्रा से अधिक) ड्रॉ के छोटे आकार के कारण ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने से एक जीत दूर हैं।

विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान से हटे दिग्गज खिलाड़ी फेडरर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

टेनिस डायरी

स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर विश्व रैंकिंग में अपने तीसरे पायदान से हट गए हैं। फेडरर की जगह पर डोमिनिक थिएम हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविक और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ताजा टेनिस रैंकिंग में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। एटीपी रैंकिंग में ऑस्ट्रिया के थिएम करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तीसरे नंबर पर पहुंच गए। 26 वर्षीय थिएम ने 7045 अंक के साथ स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। एटीपी रैंकिंग में छह मई 2019 के बाद से जोकोविक, राफेल नडाल और फेडरर का ही कब्जा था।

पिछले सप्ताह ही दुबई मास्टर्स का खिताब जीतने वाले जोकोविक 10220 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं जबकि नडाल 9850 अंक के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। डब्ल्यूटीए की महिला वर्ग की रैंकिंग में बार्टी 8717 अंक के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि रोमानिया की सिमोना हालेप 6076 अंक लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान हैं। स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनकिक को ही केवल फायदा हुआ है और वह शीर्ष-10 में एक पायदान आगे बढ़कर नौवें से आठवें नंबर पर पहुंच गई। बेनकिक ने 23 बार की ग्रैंडस्लैम विजेता अमेरिका की दिग्गज सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया। रूस की स्वेटलाना कुच्नेसोवा 14 स्थानों की छलांग लगाकर 32वें, जबकि हीटर वॉटसन 49वें नंबर पर पहुंच गई।

प्रसाद, जोशी और शिवा चयनकर्ता की दौड़ में, अगरकर को किया नजरअंदाज

क्रिकेट

- शिवरामाकृष्णन, राजेश, हरविंदर को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया
- दो पदों को भरने के लिए पूर्व पांच क्रिकेटरों का आज होगा साक्षात्कार

मुंबई, प्रेट्र : कर्नाटक के वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी उन पांच उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्हें बीसीसीआइ की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) राष्ट्रीय चयन समिति के दो पदों को भरने के लिए बुधवार को होने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया है।

पूर्व भारतीय स्पिनरों लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन और राजेश चौहान तथा मध्यम गति के गेंदबाज हरविंदर सिंह को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है जो स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होंगे। समिति में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल, आर पी सिंह और सुलक्षणा नाइक शामिल हैं। निर्वतमान चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद और उनके साथी गगन खोड़ा के स्थान पर नए चयनकर्ताओं को चुना जाएगा। इन दो पदों के लिए कुल 44 आवेदन मिले थे। आवेदकों में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजित अगरकर भी शामिल थे जिन्हें इस पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। पूर्व विकेटकीपर नयन मोंगिया ने भी आवेदन किया था। अगरकर का नहीं चुना जाना इस बात का संकेत है कि बोर्ड राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए मौजूदा क्षेत्रीय नीति पर कायम रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो पंजाब और रेलवे की तरफ से खेलने वाले हरविंदर को खोड़ा की जगह मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जा सकता है जबकि शिवरामाकृष्णन, प्रसाद और जोशी में से किसी एक को एमएसके प्रसाद की जगह दक्षिण क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चयन समिति में रखा जा सकता है। वेंकटेश प्रसाद को इस पद पर कुछ अनुभव है। वह जूनियर चयन पैनल का हिस्सा रह चुके हैं।

नई चयन समिति दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 मार्च से शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों के लिए टीम का चयन करेगी। सीएसी की नियुक्ति 31 जनवरी को की गई थी, लेकिन उसकी पहली बैठक मंगलवार को हुई।

रुतुजा की हार से चीन ने ली 1-0 की बढ़त

दुबई : भारतीय टेनिस खिलाड़ी रुतुजा भोसले को चीन की विश्व रैंकिंग में 35वें स्थान पर काबिज शुआई झांग के खिलाफ फेड कप के पहले मुकाबले में मंगलवार को हार का सामना करना पड़ा। चीन ने इस जीत के साथ 1-0 की बढ़त बना ली।

पुणे की 23 साल की खिलाड़ी ने पहले सेट में 3-1 की बढ़त कायम की लेकिन शुआई ने शीर्ष 50 में शामिल खिलाड़ी का दमखम दिखाते हुए एक घंटे 16 मिनट तक चले मुकाबले को 6-4, 6-2 जीत लिया। चीनी खिलाड़ी को दूसरे सेट में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा और आसानी से यह सेट और मैच अपने नाम किया। भारतीय कप्तान विशाल उप्पल ने विश्व रैंकिंग में 433वें स्थान पर काबिज रुतुजा को रिया भाटिया (विश्व रैंकिंग 388) पर तरजीह दी। छह टीमों की एशिया ओशियाना ग्रुप एक में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करेंगी।

विविध

रामकचहरी मंदिर में होगा ट्रस्ट का पहला कार्यालय

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या : राम मंदिर निर्माण के पहले श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थायी ठौर की तलाश अब पूरी हो गई। ट्रस्ट का पहला कार्यालय रामजन्मभूमि दर्शन मार्ग पर स्थित रामकचहरी मंदिर में बनने वाला है। यहां कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मंदिर के महंत शशिकांत ने ट्रस्ट को दिया था। इसी के बाद मंगलवार को ट्रस्ट के सदस्यों ने राम कचहरी मंदिर का निरीक्षण किया और वहां कार्यालय खोले जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

इसके पहले राम कोट में स्थित सुंदर सदन में कार्यालय बनाने की चर्चा रही। बताया गया कि सुंदर सदन जीर्णशीर्ण है। इसे भी दुरुस्त कराकर यहां भी ट्रस्ट कार्यालय का कंप्यूटर सेक्शन खोला जाएगा। सुंदर सदन को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से राम कचहरी में ट्रस्ट का कार्यालय खोलने की सहमति बनी। राम कचहरी के महंत शशिकांत 2013 से सरयू जी की नित्य भव्य महाआरती के आयोजक हैं। योगी सरकार ने भी शासकीय सहायता देकर शशिकांत दास के सरयू आरती आयोजन को संबल प्रदान किया।

जमीन कब्जाने के दोषी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री को पांच साल कैद

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी

- फर्जी वसीयत से स्वतंत्रता सेनानी की 32.5 एकड़ जमीन कब्जाने का आरोप सिद्ध
- पूर्व मंत्री की पत्नी, बेटे और बहू को भी हुई सजा

फर्जी वसीयत बनाकर जमीन कब्जाने के लिए अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह, उनकी पत्नी मंजूलता, बहू निधि, पूर्व शासकीय अधिवक्ता स्वतंत्र बहादुर सिंह, पत्नी गीता सिंह और उनकी बहू को सजा सुनाई है। इन सभी पर फर्जी वसीयत बनाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामअवध सिंह की रुद्रपुर स्थित जमीन कब्जाने का आरोप सही साबित हुआ है। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन छवि बंसल की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश मूल रूप से यूपी के देवरिया जिले के पैना गांव के रहने वाले हैं।

किसको मिली कितनी सजा : प्रभावती के वकील सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह को पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उनके बेटे शिव वर्धन, फर्जी वसीयत के दो गवाहों नवनाथ तिवारी व प्रेम नारायण सिंह को तीन साल, पूर्व मंत्री की पत्नी मंजूलता, बहू निधि, शासकीय अधिवक्ता की पत्नी गीता सिंह व बहू शिखा को एक-एक साल और शासकीय अधिवक्ता स्वतंत्र बहादुर सिंह को दो साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के आदेश पर प्रेम प्रकाश को जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपितों को अंतरिम जमानत मिल गई।

आजाद हिंद फौज के सिपाही रामअवध सिंह मूल रूप से आजमगढ़ के पूनापार के रहने वाले थे। आजादी के बाद पुलिस में भर्ती हुए और डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को देखते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें कृषि कार्य के लिए मौजूदा ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर के बागवाला गांव में 32.5 एकड़ जमीन आवंटित की थी।

निधन के बाद जमीन पर पड़ी पूर्व मंत्री की नजर : 10 जून 1999 को रामअवध की मृत्यु के बाद जमीन उनकी इकलौती पुत्री प्रभावती देवी के नाम दर्ज हो गई। उनकी शादी आजमगढ़ की में हुई। ऐसे में वह यहां नहीं रहतीं। इस पर फर्जी वसीयत तैयार कर पूर्व मंत्री ने जमीन अपने नाम करा ली।

2014 में दर्ज हुआ मुकदमा : घटना की जानकारी होने पर प्रभावती ने इसकी शिकायत डीआइजी से की। इस पर तीन मई, 2014 को प्रेम प्रकाश के साथ ही वसीयत के गवाह ग्राम तिलियापुर, सितारगंज निवासी नवनाथ तिवारी और प्रेमनारायण को नामजद किया गया।

पूरे परिवार पर कसा शिकंजा : जांच में पूर्व मंत्री की पत्नी सितारगंज की तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख मंजूलता सिंह, पुत्र शिव वर्धन, बहू निधि सिंह, एसबी सिंह, उनकी पत्नी गीता सिंह और बहू शिखा सिंह के नाम भी सामने आए। इसपर पुलिस ने 17 जून 2018 को आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज से दो बार विधायक रहे हैं। जबकि उनकी पत्न ी मंजूलता पूर्व में सितारगंज की ब्लाक प्रमुख रही हैं।

सीमांचल में घुसपैठ पर केंद्र की कड़ी नजर

जागरण संवाददाता, किशनगंज : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से बिहार के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ में बढ़ोत्तरी को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके पर कड़ी नजर रखे हुए है। इसकी गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि दो महीनों में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यहां का दो बार दौरा कर चुके हैं। दरअसल, बिहार में सीमांचल का क्षेत्र नेपाल और बांग्लादेश से सीधे जुड़ता है, जहां से घुसपैठ होती रही है। लेकिन हाल के दिनों में घुसपैठ में और तेजी आई है। इस दौरान एक दर्जन से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार भी किए गए हैं।

सीमांचल में सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। 31 दिसंबर को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने बांग्लादेश सीमा पर फुलबरिया कैंप में बीएसएफ के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया था। उन्होंने 29 फरवरी को भी नेपाल सीमा पर अवस्थित किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में एसएसबी के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय सीमांचल को लेकर काफी गंभीर है और सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

जम्मू एयरपोर्ट और विवि होगा डोगरा शासकों के नाम पर!

जागरण संवाददाता, जम्मू

- जम्मू हवाई अड्डे का नाम महाराजा हरि सिंह व जम्मू विवि का महाराजा गुलाब सिंह विश्वविद्यालय होगा
- निगम की जनरल हाउस मीटिंग में पारित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा

पुराने शहर के सिटी चौक को भारत माता चौक और सर्कुलर रोड चौक को अटल जी मार्ग का नाम देने के साथ जम्मू नगर निगम ने जम्मू हवाई अड्डे व जम्मू विश्व विद्यालय को डोगरा शासकों का नाम देने का प्रस्ताव भी पारित किया है। जम्मू नगर निगम की हल ही में हुई जनरल हाउस की मीटिंग में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। अब नगर निगम ने इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। अगर उनकी ओर से इसे मंजूरी मिल जाती है तो राजस्व रिकार्ड के साथ जमीनी स्तर पर नामों में बदलाव होगा।

नगर निगम ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उसमें सतवारी स्थित जम्मू एयरपोर्ट का नाम 'महाराजा हरि सिंह जम्मू हवाई अड्डा' और जम्मू विवि का नाम 'महाराजा गुलाब सिंह विश्वविद्यालय' रखा गया है। इन दोनों शासकों का जम्मू के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। महाराजा गुलाब सिंह ने जहां जम्मू-कश्मीर में डोगरा शासन की नींव रखी थी, वहीं महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय किया था। दैनिक जागरण से बातचीत में जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि जम्मू हवाई अड्डे व जम्मू विश्वविद्यालय का नामकरण करने के लिए हाउस ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उसे मंजूरी के लिए उप राज्यपाल प्रशासन के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद राजस्व रिकार्ड में एंट्री करते हुए जमीनी स्तर पर इसे प्रभावी बनाया जाएगा।

पुराना शहर नगर निगम के अधीन

पुराने शहर के सीटी चौक और सर्कुलर रोड का नाम बदलने पर जारी विवाद पर जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि पुराना शहर जम्मू नगर निगम के अधीन आता है, लिहाजा हाउस में पारित प्रस्ताव को लागू करने के लिए निगम को प्रशासन की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। सिटी चौक एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक चौराहा है जो कई महत्वपूर्ण फैसलों व प्रदर्शनों का गवाह रहा है। इस चौक में हर स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लहराया जाता है। लोगों की मांग को देखते हुए सिटी चौक का नाम भारत माता चौक रखा गया और इसी तरह सर्कुलर रोड को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया गया है।

लद्दाख की सड़कों पर बर्फ से जंग लड़ रहे जवान

राज्य ब्यूरो, जम्मू

बर्फ की जमी सड़कों पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। लद्दाख की सड़कों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है कि यहां सफर करना आसान नहीं है। बर्फ के कारण सितंबर से लद्दाख की सड़कें बंद हैं। मगर बर्फ के योद्धा जवानों के जोश से यहां बर्फ पिघल रही है। यहां सीमा पर मोर्चा संभाले सैनिकों और यहां के लोगों के सफर को सुगम बनाने के लिए बीआरओ और सेना के जवानों मशीनों से बर्फ हटाने में जुटे हैं। मकसद है कि मार्च के अंत तक लद्दाख को सड़क मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से जोड़ना।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और सेना की फायर एंड फ्यूरी (14वीं) कोर के जवान शून्य से नीचे के तापमान में बर्फ से पटे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला पास को रिकॉर्ड समय में बहाल करने में जुटे हैं। इसका कार्य 14 फरवरी से शुरू किया गया है। अब तक कारगिल के द्रास से मिनामर्ग तक सड़क से बर्फ हटाई जा चुकी है। इसके लिए लद्दाख प्रशासन ने भी आग्रह किया है। मंगलवार को मार्ग पर बर्फ हटाने में जुटी टीम विजयक और 14 कोर के जवानों का वीडियो वायरल हुए। इससे देशवासियों को अंदाजा हुआ कि सेना, सीमा सड़क संगठन दुर्गम हालात में भी काम कर लद्दाख में कैसे सड़क संपर्क को बहाल करते हैं। जंस्कार के पदम से किलमा, पदम से शिनकुनला व वानला से नेरक तक सड़कों को खोलने के लिए भी प्रोजेक्ट विजयक की टीमें काम कर रही हैं।

हरियाणा में अब हिंदी के बाद दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी को दिया जाएगा बढ़ावा

सुधीर तंवर, चंडीगढ़

- हिंदी के साथ-साथ पंजाबी में भी होंगे साइन बोर्ड
- मंत्रियों व अधिकारियों की नेम प्लेट भी पंजाबी में

हरियाणा सरकार ने पंजाबी भाषा को हिंदी के बाद दूसरी भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एलान किया है कि भविष्य में राज्य में सभी साइन बोर्ड हिंदी के साथ-साथ पंजाबी में भी लिखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हवाले से संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उक्त एलान किया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक शीशपाल ने सरकार से पूछा था कि क्या हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है? कितने कार्यालय ऐसे हैं, जो पंजाबी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? विधानसभा में इस मुद्दे पर खासी बहस भी हुई। बता दें कि हरियाणा में चार लोकसभा और दो दर्जन विधानसभा सीटों पर पंजाबी भाषी लोगों की बहुलता है।

शीशपाल ने सदन में दावा किया कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के साथ पंजाबी में पत्राचार करता है तो उसका जवाब पंजाबी में नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार के पास पंजाबी भाषा में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी या लिपिक नहीं हैं। जवाब में संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा सभी विभागों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पंजाबी भाषा में पत्र लिखता है तो उसका जवाब पंजाबी में दिया जाए। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पूरक सवाल दागते हुए कहा कि यह आदेश उनकी सरकार के कार्यकाल में जारी हो चुके थे, लेकिन इन्हें सख्ती से लागू करवाने के लिए कदम उठाने होंगे। गीता भुक्कल ने पंजाबी को संस्कृत व उर्दू की तरह प्रमोट करने के लिए कई सुझाव दिए, जिस पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं। अब हरियाणा में सभी साइन बोर्ड हिंदी व अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी भाषा में भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा मंत्रियों व अधिकारियों की नेम प्लेट भी पंजाबी भाषा में होगी।

मौसम विशेष

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में सुबह के समय हल्का कोहरा व कुहासा छाया रहेगा। दिन का मौसम तेज धूप के साथ हल्का गर्म रहेगा। रात सुहावनी रहेगी। कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा संभव है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी।

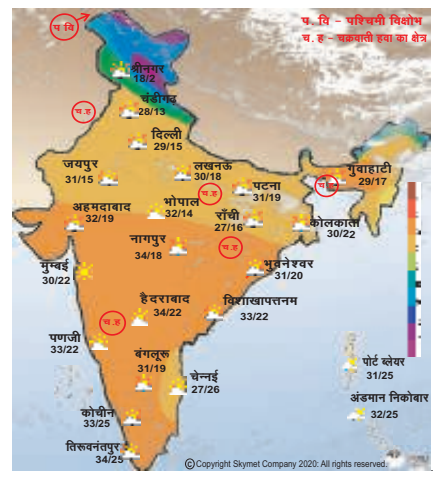

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/22/व	अहमदाबाद	34/16/व
कोलकाता	29/21/व	बड़ौदा	34/15/सा
चेन्नई	35/25/आंबा	नागपुर	34/18/व
हैदराबाद	33/22/आंबा	इन्दौर	33/16/व
बंगलूरू	30/20/व	राँची	28/17/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/24/आंबा	पटना	30/19/व
गुवाहाटी	32/19/आंबा	जमशेदपुर	29/16/व
गंगटोक	12/06/व	पुणे	34/14/व

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

बुधवार 4 मार्च 2020

आजकल

16

www.jagran.com

आज ही के दिन शिकागो शहर के रूप में अस्तित्व में आया

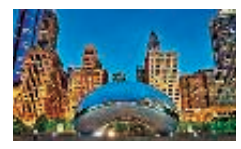

आज ही 1837 में शिकागो अमेरिका के शहर के रूप में शामिल हुआ। उस वक्त शिकागो की आबादी करीब 4 हजार थी। हालांकि आज यह अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। साथ ही यह यह अमेरिका की व्यावसायिक और सांस्कृतिक राजधानी है।

पहले एशियाई खेलों का दिल्ली में हुआ था आयोजन

एशियाई खेलों का सबसे पहले आयोजन 1951 में दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया। 11 मार्च तक एशिया के 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 1982 में दूसरी बार भारत ने इन खेलों की मेजबानी की।

मैला आंचल से अमर हो गए साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु

साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म आज ही के दिन 1921 में बिहार के औराही हिंगना गांव में हुआ। पढ़ाई नेपाल के विराटनगर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और फिर 1950 में नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लिया। 1952-53 में गंभीर रूप से बीमार होने के बाद लेखन की ओर झुकाव हुआ। कहानी 'तबे एकला चलो रे' के जरिये हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। 1970 में पद्मश्री मिला। 'मारे गए गुलफाम' कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी। मैला आंचल सर्वाधिक लोकप्रिय कृति रही। 11 अप्रैल 1977 को निधन हो गया।

इधर-उधर की

रिकॉर्ड के लिए सड़क पर अग्निशमन वाहन

मनीला, एजेंसी : रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि जब ऐसे प्रयास सरकारी समर्थन से होते हैं तो आश्चर्य होता है। ऐसा ही हुआ फिलीपींस में, जहां पर 242 अग्निशमन वाहन सड़क पर उतरे। इन वाहनों को सड़क पर परेड कराने का मकसद था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शुमार कराना। अग्निशमन विभाग की ओर से इस महीने को अग्निशमन महीने के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के दौरान यह परेड भी रखी गई। विभाग के अधिकारी रिको नील क्वान टियू ने दावा किया कि अग्निशमन वाहनों ने पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। पिछली बार यह रिकॉर्ड जनवरी 2012 में ओकलाहोम में बनाया गया था। उन्होंने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड के लिए प्रक्रिया अपनाई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि उस वक्त कहीं आग लग जाती तो रिकॉर्ड बनाने की चिंता में जुटे अग्निशमन कर्मचारी उससे कैसे निपटते?

वायु प्रदूषण से तीन साल घटा जीवन

दावा ▶ जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन

इस कारण सालाना 88 लाख लोग असामयिक मौत का शिकार हो रहे हैं

प्रतीकात्मक।

बर्लिन, प्रेट्र : वायु प्रदूषण एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि यह दुनिया भर में लोगों की आयु औसतन तीन साल कम कर रहा है। इस कारण सालाना 88 लाख लोग असामयिक मौत का शिकार हो रहे हैं।

अध्ययन में शामिल जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रसायन विज्ञान के शोधकर्ताओं ने पाया कि युद्ध और अन्य प्रकार की हिंसा, वेक्टर जनित बीमारियों जैसे कि मलेरिया, एड्स और धूमपान से जितना नुकसान लोगों को नहीं होता, उससे कहीं अधिक नुकसान वायु प्रदूषण से हो रहा है। कार्डियोवस्कुलर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया वायु प्रदूषण नामक 'महामारी' का सामना कर रही है।

मृत्यु दर पर वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के प्रभाव को जानने की एक नई पद्धति का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण वर्ष 2015 में 88 लाख लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बना। यह दुनिया भर में सभी व्यक्तियों का जीवन लगभग तीन साल कम होने का प्रमाण है। शोधकर्ताओं ने बताया कि तुलनात्मक रूप से तंबाकू धूमपान से जीवन में जीवन में औसतन 2.2 वर्ष, एचआइवी / एड्स से 0.7 वर्ष तक की कमी आती है। वहीं, मलेरिया जैसे रोग जो परजीवियों या कीड़ों जैसे मच्छरों आदि के काटने से होता है, से औसत आयु में करीब 0.6 साल और हिंसा के सभी प्रकार (युद्ध में मृत्यु सहित), 0.3 साल तक की कमी पाई गई।

वायु प्रदूषण से कई बीमारियां हुईं : शोधकर्ताओं ने पाया कि वायु प्रदूषण की वजह से श्वसन तंत्र संक्रमण, लंग कैंसर, हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी रोग के लोग शिकार हुए। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे कम आय वाले देशों में पांच साल से कम उम्र के बच्चे भी इससे प्रभावित हुए। वहीं, दुनिया भर में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वृद्ध लोग होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण की वजह से मरने वालों में 75 फीसद लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह पहला अध्ययन है जिसमें आयु, बीमारी के प्रकार और देशों और क्षेत्रों के स्तर पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को आंकने की कोशिश की गई है।

मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री के प्रोफेसर जोस लेलिवल्ड ने कहा, 'यह उल्लेखनीय है कि वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या और औसत जीवन में आ रही कमी, तंबाकू धूमपान औरप अन्य वजहों से होने वाली मौतों से काफी अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो इससे सबसे अधिक मृत्यु होती है। इसलिए दुनिया भर के देशों को इस बारे में सोचने की जरूरत है। शोधकर्ताओं ने कहा कि नीति-निर्माताओं और चिकित्सा समुदाय को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण और धूमपान दोनों ही रोके जा सकते हैं, लेकिन पिछले दशकों में वायु प्रदूषण की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसलिए जरूरी है कि लोगों के बीच इसके लिए जागरूकता फैलाई जाए।

लिवर खराब होने पर भी ले सकते हैं जीवनरक्षक दवाएं

प्रतीकात्मक।

- कम मात्रा में खुराक लेने से नहीं पहुंचता यकृत को नुकसान
- अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : आम तौर पर लिवर खराब होने पर डॉक्टर दवाओं को खाने से यह सोचकर मना कर देते हैं कि कहीं कोई रिएक्शन न हो जाए। लेकिन एक नए अध्ययन में इस प्रकार की आशंकाओं को नकारा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि आप मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं और आप अपने खराब लिवर को दुरुस्त करने के लिए दवाएं ले रहे हैं तो भी आप जीवनरक्षक दवाओं की डोज कम मात्रा में ले सकते हैं।

ड्रग मेटाबोलिज्म एंड डिपोजिशन नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि डॉक्टरों को चाहिए कि लिवर का इलाज करा रहे मरीजों को ऐसा सुझाव न दें कि जब तक लिवर पूरी तरह ठीक न हो जाए अन्य जरूरी दवाओं का सेवन न करें क्योंकि ऐसा करने से मरीज की अन्य बीमारियां काफी बढ़ सकती हैं। बता दें कि पूरे विश्व में खराब लिवर की समस्या से लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हैं।

अमेरिका में कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के शियाओबो झोंग ने कहा, 'डॉक्टर मरीजों को बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाएं देते हैं। कोई नहीं चाहता है कि उनका लिवर खराब हो, लेकिन कई बार दवाओं से भी लिवर में खराबी आ जाती है। इससे बचने के लिए दवा की खुराक को कम या सीमित किया जा सकता है। इससे बीमारियां तो ठीक होंगी ही साथ ही लिवर को भी नुकसान नहीं होगा।'

दवा को विभाजित करते हैं एंजाइम : शोधकर्ताओं ने कहा कि जब कोई व्यक्ति मुंह से दवा की खुराक लेता है तो वह सीधे उसके पेट से होते हुए आतों में जाती है, जहां रासायनिक क्रियाओं के जरिये इसमें मौजूद घटक रक्त में घुल जाते हैं। इसके बाद यह रक्त शरीर के किसी भी हिस्से में जाने से पहले लिवर में जाता है। लिवर में एंजाइम होते हैं जो दवाओं को विभाजित कर शेष हिस्सों तक पहुंचाते हैं। लेकिन विभिन्न लोगों में स्वाभाविक रूप से इन एंजाइमों की संख्या कम या ज्यादा होती है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक व्यक्ति के लिए दवा की एक सीमित खुराक उपयुक्त हो लेकिन वही खुराक किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। इसीलिए आपने गौर किया होगा दवा देते समय डॉक्टर आपकी उम्र जरूर पूछते हैं और उसी आधार पर खुराक तय करते हैं।

चूहों पर किया अध्ययन : यही कारण है कि कई लोगों का लिवर दवाओं को खाने से भी कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टरों के पास कोई मानक दिशा-निर्देश भी नहीं होते। इसीलिए लिवर खराब होने पर वह मरीजों से कहते हैं कि आप दवाएं खाना बंद कर दीजिए। शोधकर्ताओं ने कहा, यदि ज्यादा गंभीर बीमारी न हो तो आप कम से कम हफ्ते भर तक दवाएं लेना बंद कर सकते हैं लेकिन इसके बाद दवा न खाने पर आपकी समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में कई बार जान पर भी बन आती है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने ऐसे चूहों पर अध्ययन किया जिनका लिवर खराब था। इस दौरान उन्होंने पाया कि छोटी-छोटी मात्रा में दवाएं देने लिवर को नुकसान नहीं पहुंचता। इसी वजह से शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लिवर खराब होने पर दवाओं से परहेज नहीं करना चाहिए।

शोधकर्ताओं की सलाह है कि जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं खुद से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी भी छिपाएं। इससे डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आप जल्द स्वस्थ होंगे। इसके अलावा खान-पान पर ध्यान रखना चाहिए जिससे लिवर संबंधी बीमारियां आपसे दूर रहें।

नई दवा ने जगाई पार्किंसंस के इलाज की उम्मीद

- मस्तिष्क के भीतर सेरोटोनिन कोशिकाओं को लक्षित करती है 'एनएलएक्स -112'
- उपयुक्त मात्रा में डोपामाइन जारी कर डिस्किनेशिया की समस्या को करती है कम

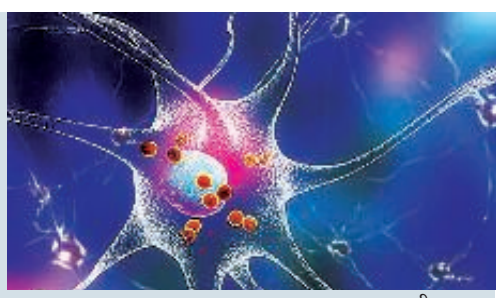

प्रतीकात्मक।

वाशिंगटन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने एक ऐसी दवा का पता लगाया है जिससे पार्किंसंस के इलाज की उम्मीद जगी है। अमेरिका की बायोटेक कंपनी न्यूरोलिक्स के शोधकर्ताओं ने पशुओं पर अध्ययन कर यह दावा किया है।

इसके लिए शोधकर्ताओं ने डिस्किनेशिया पर एनएलएक्स -112 नामक दवा के प्रभाव का विश्लेषण किया। डिस्किनेशिया पार्किंसंस रोग की ही एक रूप है, जो कई वर्षों से लेवोडोपा आधारित दवाओं को लेने से दुष्परिणाम के रूप में सामने आता है। ये दवाएं पार्किंसंस से बचने के लिए खाई जाती हैं।

शोधकर्ताओं ने कहा कि पार्किंसंस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक रोग है जिसमें रोगी के शरीर के अंग खुद-ब-खुद कंपन करते रहते हैं। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर रोजमर्रा के कार्यों को असंभव बना सकता है। उन्होंने कहा कि डिस्किनेशिया को ठीक करने के लिए लोग मुख्य एमेंटैडाइन नामक दवा का प्रयोग करते हैं। हर किसी व्यक्ति को यह दवा सूट भी नहीं करती है, जिसके दुष्प्रभाव भी कई बार सामने आते हैं। इस कारण नई दवा को खोजने का काम किया जा रहा है और अब इसमें सफलता भी हासिल हुई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका फिलहाल इंसानों पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। जल्द ही इसके लिए अनुमति ली जाएगी और उसके सही परिणाम आने के बाद ही बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा।

मस्तिष्क की कोशिकाओं को लक्षित करती है 'एनएलएक्स -112' : शोधकर्ताओं की टीम के मुताबिक, लगातार पांच वर्षों तक लेवोडोपा लेने से लगभग 50 फीसद पार्किंसंस के मरीजों को डिस्किनेशिया की समस्या का सामना करना पड़ता है और 80 फीसद लोगों में 10 वर्षों बाद इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि 'एनएलएक्स -112' सीधे मस्तिष्क के भीतर सेरोटोनिन कोशिकाओं को लक्षित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य डोपामाइन (रसायन)को कोशिकाओं में जारी कर डिस्किनेशिया को कम करना होता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अन्य दवाएं डोपामाइन को अनिश्चित तरीके से जारी कर डिस्किनेशिया के विकास में अहम योगदान देती हैं।

बंदरों पर किया अध्ययन

यह अध्ययन न्यूरोफॉर्माकोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें 'एनएलएक्स -112' का परीक्षण पार्किंसंस जैसे लक्षणों वाले बंदरों पर किया गया था। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि लेवोडोपा के जरिये पार्किंसंस का इलाज करने पर बंदरों में भी मनुष्यों की तरह दुष्प्रभाव देखने को मिले। इस दौरान शोधकर्ताओं ने यह भी जांच की कि केवल 'एनएलएक्स -112' और इसके साथ लेवोडोपा के संयोजन वाली दवाएं लेने से डिस्केनेशिया और पार्किंसंस के लक्षणों कैसे प्रभावित होते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि हमारे अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि 'एनएलएक्स -112' ने सफलतापूर्वक डिस्केनेशिया को कम कर दिया और लेवोडोपा की प्रभावशीलता को बनाए रखा।

मंगोलिया में 300 ईसा पूर्व में भी होता था डेयरी खाद्य उत्पादों का इस्तेमाल

बर्लिन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने पूर्वी एशिया में डेयरी खाद्य उत्पादों की खपत के सबसे पहले साक्ष्य पाए हैं। उनके मुताबिक ये लगभग 3,000 ईसा पूर्व के हैं। इससे प्रागैतिहासिक मंगोलिया में डेयरी आधारित पशुपालन की शुरुआत और विकास के बारे में जानकारी मिलती है। जर्मनी स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने कहा कि डेयरी आधारित पशुपालन कई हजार सालों के लिए पूर्वी यूरेशियन स्टेपे संस्कृति का हिस्सा रहा है। दक्षिण-पश्चिम एशिया से पूर्व की ओर इसके बढ़ने के बारे में फिलहाल काफी कम जानकारी है। नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन नामक जर्नल में प्रकाशित अपने वर्तमान अध्ययन में वैज्ञानिकों ने शुरुआती कांस्य युग से लेकर मंगोल साम्राज्य तक के उपलब्ध मानव दांतों का अध्ययन किया गया। इसमें तीन चौथाई दांतों में डेयरी खाद्य पदार्थों के सेवन का सुबूत मिला। इससे प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक मंगोलिया, दोनों में इस खाद्य स्रोत के व्यापक महत्व का पता चलता है।

तीन अरब साल पहले पानी की दुनिया रही होगी पृथ्वी : अध्ययन

वाशिंगटन, प्रेट्र : तीन अरब साल पहले पृथ्वी चारों ओर से एक वैश्विक महासागर से घिरी रही होगी। इसी कारण यह 'पानी की दुनिया' के तौर पर जानी जाती थी। यह जानकारी नेचर जियोसाइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में दी गई है।

शोधकर्ताओं का सुझाव है कि सर्वनाश के बाद पृथ्वी भूमि मुक्त हो गई थी और अमेरिकी फिल्म निर्माता केविन कोस्टनर की काल्पनिक फिल्म वॉटरवर्ल्ड की तरह दिखती थी। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह अध्ययन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर सकता है कि पहली बार पृथ्वी पर एकल-कोशिका वाले जीव कैसे और कहां पाए गए। अमेरिका में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर के एक एसोसिएट प्रोफेसर बोसवेल विंग ने कहा, 'पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के कई सुबूत उपलब्ध हैं।' अध्ययन में इस सवाल का जवाब देने की भी कोशिश की गई है कि पहले पृथ्वी कैसी दिखती थी। अध्ययन के प्रमुख लेखक बेंजामिन जॉनसन ने कहा कि शोध के दौरान उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाहरी इलाके में स्थित पैनोरमा जिले के भूगर्भिक स्थल के चारों ओर कुछ अलग दिखा। आज, यह वास्तव में एक रगड़ के कारण बना पहाड़ है जो सूखी नदी के सिरों पर स्थित है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह समुद्र की परत के 3.2 अरब साल पुराने समुद्री तट का विश्राम स्थल भी है।

वसायुक्त दुग्ध उत्पादों से मोटापे का खतरा नहीं

शोध अनुसंधान

एक नए अध्ययन में वसायुक्त दुग्ध उत्पादों का सेवन करने वाले बच्चों में मोटापे या हृदय रोग का कोई खतरा नहीं पाया गया। यह निष्कर्ष 29 अध्ययनों की समीक्षा के आधार पर निकाला गया है। इन अध्ययनों में बच्चों में फुल फैट डेयरी प्रोडक्टस के सेवन पर गौर किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की एदिथ कोवान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, बच्चों में वसायुक्त दुग्ध उत्पादों का वजन वृद्धि, उच्च कोलेस्ट्राल या हाई ब्लड प्रेशर से कोई स्पष्ट संबंध नहीं पाया गया। आमतौर पर दो साल से ज्यादा उम्र के बच्चों और वयस्कों को कम वसा वाले दुग्ध उत्पाद के सेवन की सलाह दी जाती है। अध्ययन की शोधकर्ता थेरेसी ओसुल्विन ने कहा, 'इससे यह जाहिर होता है कि निम्न वसा वाले दुग्ध से संपूर्ण दुग्ध की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए बच्चे दूसरे खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन कर सकते हैं।' -प्रेट्र

अल्जाइमर रोग का पता लगाने में मदद कर सकती है नई रक्त जांच

वैज्ञानिकों ने एक आसान रक्त जांच विकसित की है। इस नई जांच से उन लोगों में अल्जाइमर रोग को भांपा जा सकता है, जो याददाश्त संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यह जांच इस बीमारी का पता लगाने की दूसरी जांच मसलन ब्रेन इमेजिंग और स्पाइनल फ्लूड टेस्ट का किफायती और कम कष्टकारी विकल्प बन सकती है।

नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, नई रक्त जांच में असामान्य तौर पर जमा होने वाले फॉस्फोरिलेटेड-ताउ-181 नामक प्रोटीन की पहचान की जाती है। यह प्रोटीन भूलने की बीमारी अल्जाइमर का बायोमार्कर माना जाता है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एडम बॉक्सर ने कहा कि ताउ प्रोटीन और दूसरे बायोमार्कर्स की पहचान पेट ब्रेन इमेजिंग और स्पाइनल फ्लूड टेस्ट से भी हो सकती है। -प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

'मिर्जापुर' के मुन्ना भैया ने छुड़ाई दिव्येंदु की कार!

फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले अभिनेता दिव्येंदु शर्मा इन दिनों उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि के किरदारों में काफी नजर आ रहे हैं। वेब शो 'मिर्जापुर', डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म 'बदनाम गली' और 'कानपुरिए' तीनों में दिव्येंदु उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि के किरदारों में नजर आए। खास बात यह है कि इन किरदारों में उन्हें काफी पसंद भी किया गया है। हाल ही में रिलीज हुई वेब फिल्म 'शुक्राणु' में भी वह उत्तर प्रदेश के इंदर के किरदार में नजर आए। इस पर वह कहते हैं, 'मैंने कभी यह नहीं कहा कि मुझे सिर्फ उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि वाले किरदार निभाने हैं। वहां से बहुत दिलचस्प कहानियां आ रही हैं। यहां की बातचीत के लहजे से लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। इन दिनों एकाएक वहां की कहानियों पर आधारित फिल्में ज्यादा बनने लगी हैं। वहां पर फिल्मों की शूटिंग को मिलने वाली सब्सिडी भी इसका बड़ा कारण है। इंडस्ट्री में सभी चीजों का एक दौर होता है। पहले मुंबई की पृष्ठभूमि पर फिल्में ज्यादा बनती थीं, फिर दिल्ली का नंबर आया और अब यूपी का दौर चल रहा है।' वेब सीरीज मिर्जापुर के मुन्ना भैया के किरदार की लोकप्रियता के बारे में वह बताते हैं कि 'शुक्राणु' की शूटिंग के दौरान जब वह लखनऊ से जा रहे थे तो वहां हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर उनकी गाड़ी रोक ली गई। लेकिन पुलिस अधिकारी ने गाड़ी में उन्हें देखकर कहा, 'अरे यह तो मुन्ना भैया हैं, इन्हें जाने दो।' दिव्येंदु बताते हैं कि उन्हें आज भी रोज मुन्ना पर बने कई मीम्स मिलते रहते हैं। 'मिर्जापुर 2' इस साल की पहली छमाही में रिलीज होने की संभावना है।

दोस्ती की खातिर गुलशन कर रहे हैं राधिका आप्टे की फिल्म!

हालांकि अपने बेहद बिजी शेड्यूल के बावजूद, गुलशन राधिका के लिए समय निकालना चाहते थे, जिनसे उनकी दोस्ती काफी पुरानी है। उन्होंने बताया, 'आमतौर पर मैं फीचर फिल्म या सीरीज जैसे लंबे फॉर्मेट के लिए काम करना पसंद करता हूं, लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा दोस्त राधिका के डायरेक्शन में बन रही पहली फिल्म होने के नाते इसे छोड़ पाना असंभव था। साथ ही शहाना गोस्वामी के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। इसकी शूटिंग का शेड्यूल काफी चैलेंजिंग होने के बावजूद मेरे लिए बेहद खास था, क्योंकि राधिका और शहाना के साथ काम करने का अनुभव मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी। शहाना के साथ मेरी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई है कि अब मैं उनके साथ और ज्यादा काम करना चाहता हूं। बताना चाहूंगा कि 'स्लीपवॉकर्स' हमारी सोसाइटी, क्लास, नेचर, बैलेंस की कमी और लालच पर एक कमेंट्री की तरह है।'

फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती के चलते अक्सर लोग काम कर लेते हैं। गुलशन देवैया भी अपने दोस्तों के लिए जान देने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल वह रीमा कागती के डायरेक्शन में आने वाली सीरीज 'फॉलन' की शूटिंग कर रहे हैं। वही 'स्लीपवॉकर्स' नामक शॉर्ट फिल्म में भी काम करेंगे, जिसे राधिका आप्टे ने लिखा है और वही इसे निर्देशित भी करेंगी। इस फिल्म को अभिषेक चौबे, हनी त्रेहन और ललित शर्मा ने प्रोड्यूस किया है।

'गंगूबाई...' में आइटम सांग करेंगी कट्रीना कैफ

कहते हैं जहां चिंगारी होगी, वहीं से धुआं निकलेगा। पिछले दिनों कट्रीना कैफ को संजय लीला भंसाली के ऑफिस से निकलते देखा गया था। अब उनके वहां जाने की वजहें साफ होती दिख रही हैं। बॉलीवुड गलियारों की खबरों में कहा जा रहा है कि कट्रीना संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में आइटम सांग करेंगी। गाने को मुंबई में ही भव्य स्तर पर फिल्माया जाएगा। 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में आलिया भट्ट प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। कहानी पिछली सदी के पांचवें दशक की है। आलिया उसमें कोठे चलाने वाली महिला का किरदार निभा रही हैं। फिल्म से उनका पहला लुक भी सामने आ चुका है। कट्रीना इससे पहले 'चिकनी चमेली', 'शीला की जवानी', 'काला चश्मा' जैसे हिट आइटम सांग में अपने लटके-झटके दिखा चुकी हैं। वह 24 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म 'सूर्यवंशी' में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी।

करण ने साझा की शाह रुख संग पुरानी तस्वीरें

मंगलवार को करण जौहर ने एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर साझा की। इस फोटो में उनके साथ शाह रुख खान भी नजर आ रहे हैं। दोनों डांस करते दिख रहे हैं। दरअसल, यह फोटो 1998 में हुई संजय कपूर और महीप कपूर की शादी के संगीत का है, जिसमें करण और शाह रुख अपने डांस के जौहर दिखा रहे हैं। करण ने लिखा, 'संजय कपूर और महीप की शादी का संगीत। सुपरस्टार जब पैर हिलाता है तो सिंक बैकग्राउंड डांसर को भूल जाता है'। इस पोस्ट पर संजय कपूर ने लिखा, 'सात दिसंबर, 1998'। अक्षय मारवाह ने भी टिप्पणी की, 'मुझे यह रात अच्छी तरह याद है। उस समय सभी मस्ती के मूड में थे'। इस फोटो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। करण जौहर अपनी फिल्म 'तख्त' की तैयारियों में जुटे हैं।

शाह रुख के साथ फिल्म नहीं कर रहीं काजोल

फिल्म 'जीरो' के बाद से सिल्वर स्क्रीन से दूर चल रहे शाह रुख खान की अगली फिल्म को लेकर खबरें सुर्खियों में छाई हैं। बॉलीवुड गलियारों से आ रही खबरों में कहा जा रहा है कि वह अगली फिल्म राजकुमार हिरानी के साथ करेंगे। कुछ खबरों में राज ऐंड डीके के साथ एक्शन फिल्म साइन करने की खबरें भी सुर्खियों में छाई रहीं। हालांकि शाह रुख की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस बीच इन फिल्मों में शाह रुख के अपोजिट काजोल के होने की खबरें भी चर्चा में छाई रहीं, मगर काजोल ने इस प्रकार की कोई फिल्म ऑफर होने से इन्कार किया है।

उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह बताया है। दोनों की जोड़ी 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे', 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम' और 'दिलवाले' में नजर आ चुकी है। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि शाह रुख अपनी अगली फिल्म की घोषणा दो नवंबर को अपने जन्मदिन पर कर सकते हैं।

हालांकि शाह रुख कह चुके हैं कि फिलहाल वह अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी अगली फिल्म घोषित करने की बात कही है। उम्मीद है कि वह दिन जल्द आएगा।

20 मार्च को रिलीज होगी 'संदीप और पिंकी फरार'

दिबाकर बनर्जी निर्देशित फिल्म 'संदीप और पिंकी फरार' की रिलीज करीब दो साल से टल रही थी। अब उसकी रिलीज तारीख सामने आ गई है। अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा अभिनीत यह फिल्म बीस मार्च को रिलीज होगी। यशराज प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा करते हुए परिणीति को संदीप और अर्जुन को पिंकी के तौर पर परिचित कराया है। अर्जुन और परिणीति ने अपने फिल्मी करियर का आगाज वर्ष 2012 में रिलीज फिल्म 'इश्कजादे' से किया था। उसके बाद यह जोड़ी वर्ष 2018 में रिलीज 'नमस्ते इंग्लैंड' में नजर आई थी। दिबाकर और यशराज फिल्म्स इससे पहले फिल्म 'तितली' और 'व्योमकेश बख्शी' का साथ में निर्माण कर चुके हैं। 'संदीप और पिंकी फरार' को वर्ष 2018 में रिलीज करने की योजना थी, बाद में उसे 2019 में रिलीज करने की बात हुई। बहरहाल, अब फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंचेगी। फिल्म में अर्जुन कपूर हरियाणवी पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि परिणीति कॉरपोरेट में काम करने वाली महत्वाकांक्षी लड़की की भूमिका में होंगी।